

राजस्थान

भू-राजस्व अधिनियम,

१९५६

(राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट)

(एक्ट नम्बर १५, सन् १९५६ ई०)

(रूपांतरकार)

जी एम गोस्वामी

संगोपनकर्ता

बी एल पगारिया



प्रकाशक —

वाफना बुक डिपो

चौडा गम्ता, जयपुर

प्रकाशक

पाकना पुरु द्विपो

घोड़ा रास्ता

जयपुर

सर्वाधिकार प्रकाशक द्वारा सुरक्षित है ।

[अप्राधिकृत अनुवाद]

मुद्रक

कीर्ति प्रिन्टर्स

महावीर पाक रोड

जयपुर-३

अनुक्रमिका

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम १९५६

अध्याय १

प्रारम्भिक

धारा	विषय	पृष्ठ सं०
१	सक्षिप्त नाम विस्तार एवं प्रारम्भ	१
२	अधिनियम से सम्प्रभावित कानून	१
३	“याख्या”	२

अध्याय २

राजस्व-मण्डल

४	मण्डल की स्थापना एवं निमाण	३
५	सदस्यों की कार्यविधि	३
६	बाढ़े की बैठक का स्थान	३
७	सचिवालय अधिकारी	५
८	बोर्ड की शक्तियाँ	४
९	अधीन राजस्व मण्डालत पर ग्राम निगरानी	४
१०	मण्डल के क्षत्राधिकार का प्रमाण	४
११	बच को परामर्श हेतु मामला भेजने का अधिकार	५
१२	किसी प्रश्न को उच्च “यायालय” के विचाराय भेजना	६
१३	मतभेद की धक्का में निराय	६
१४	रजिस्टर भाग का रखा जाना	६

अध्याय ३

राजस्थान न्यायालय और अधिकारी

(क) क्षत्रीय विभाग

१५	क्षत्रीय विभाजन	६
१६	डिविजन आदि के निर्माण समूह तथा परिवर्तन का अधिकार	६

(ख) “यायालय” एवं अधिकारी

१७	(विस्तारित)	७
१८	सेट नोट कमिशनर और प्रतिरिक्त सेट नोट कमिशनर	७
१९	लण्ड रेपाड डायरेक्टर और सहायक भूतल अभ्यन्त	७

२०	अथ अधिकारिया की नियुक्ति	८
२०का	राजस्व अफीम अधिकारी	८
२१	पदेन नियुक्तिया	८
२२	नियुक्तिया की विज्ञप्ति	९

(ग) शक्तिया

२३	नियंत्रण शक्ति	९
२४	राजस्व मायालया एवं अधिकारिया की क्रमगत आधीनता	९
२५	मायालया और अधिकारिया के अधिकार एवं वस्तु	१०
२६	मायालया अधिकारिया की अतिरिक्त शक्तिया	११
२७	मायालया एवं अधिकारिया के आत्मजात अधिकार	१२
२८	स्थायी रिक्त स्थानों का अस्थायी काल के लिये अधिकारिया द्वारा सभालना	१२
२९	अधिकारियों को अस्थायी अनुपस्थिति	१३

(घ) पटवारी कानूनगो और निरीक्षक

३०	पटवारिया के सफिला का निर्माण एवं परिवर्तन	१३
३१	पटवारिया की नियुक्ति	१३
३२	भूलेख निरीक्षण सफिला का निर्माण एवं परिवर्तन	१४
३३	गिरदावर कानूनगो या भूलेख निरीक्षक को नियुक्ति	१४
३४	सदर कानूनगो	१४
३५	पटवारी एवं कानूनगो की योग्यतायें आदि	१४
३६	भूलेख तयार करने के लिय आवश्यक सूचना देने का उत्तरदायित्व	१४

(ङ) ग्राम अधिकारी तथा कर्मचारी

३७	(विलोपित)	१४
३८	(विलोपित)	१४
३९	(विलोपित)	१४
४०	(विलोपित)	१५
४१	ग्राम सचिव	१५
४२	रिक्त स्थान	१५
४३	ग्राम सेवक पंजिका	१५
४४	ग्राम सेवका का पारिश्रमिक	१५
४५	पारिश्रमिक कुर्की एवं हस्तांतरण में प्रभावित रहगा	१६
४६	ग्राम सेवका के वस्तु	१६
४७	नियुक्तिया करने की प्रणाली	१६
४८	नियुक्ति के लिय अयोग्यतायें	१६
४९	लम्बरदारों तथा ग्राम सेवका को दण्डित करना, मोक्षित करना और उनको नौकरी से हटाना	१७
५०	ग्राम प्रहरा को पुलिस अधिकारिया के अंतर्गत रखने का अधिकार	१७

अध्याय ४

राजस्व न्यायालय तथा अधिनारियों की कायप्रणाली

५१	न्यायालय के बैठने अथवा जाच पड़ताल करने का स्थान	१७
५२	भूमि पर प्रवेश करने तथा पैमाइश का अधिकार	१८
५३	बोर्ड इत्यादि के मामलों को स्थानांतरित करने सम्बन्धी सरकारी अधिकारी	१८
५४	अधीनस्ता से अथवा अधीनस्तों के मामले स्थानांतरित करने के अधिकार	१८
५५	मामला का एकीकरण	१८
५६	आवेदनपत्र तथा उपस्थिति इत्यादि कीन दे	१९
५७	राजस्व न्यायालयों अथवा अधिकारियों की व्यक्तियों की उपस्थिति और प्रपत्र को प्रस्तुत करने तथा साक्षी प्रहण करने के सम्बन्ध में शक्तियाँ	१९
५८	सम्मान हस्ताक्षरित और मुद्रांकित होंगे	२०
५९	सम्मान की तामील	२०
६०	नोटिस को तामील करने की प्रणाली	२१
६१	घोषणा प्रकाशित करने की प्रणाली	२१
६२	कोई शुद्धिपत्र घोषणा या सूचना पत्र अमाय नहीं होंगे	२१
६३	पत्रकार की अनुपस्थिति में मुनबाई करना	२१
६४	मुनबाई को स्थगित करना	२१
६५	धारा ६३ के अधीन निम्नलिखित गये आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं सुनी जावेगी	२२
६६	व्यय दिलाने और वितरण करने का अधिकार	२२
६७	शुद्धि अथवा भूल का संशोधन	२२
६८	पंच निर्णय के लिये मामला भेजने का अधिकार	२२
६९	पंच निर्णय के लिये प्रेषित मामला की कायशाही	२३
७०	पंचनिर्णय को रद्द करने के लिये आवेदन पत्र	२३
७१	पंचनिर्णय के अनुकूल निर्णय देना	२३
७२	दीयाना अदालत में पुनरावेदन अथवा याद दायर करने पर बन्धन	२३
७३	अचल सम्पत्ति का अधिपकार सतपर्ण	२३

अध्याय ५

पुनरावेदन, अभिप्रेत, निगरानी तथा नजरसानी

७४	इस अधिनियम द्वारा स्वीकृत अपील	२३
७५	प्रथम पुनरावेदन	२४
७६	द्वितीय पुनरावेदन	२४
७७	शुद्ध मामला में पुनरावेदन का निषेध	२५
७८	पुनरावेदन के लिये अपेक्षित	२५

७६	विवाद प्रस्त	२५
८०	अपोलेट अथोरिटी की शक्तियाँ	२६
८१	अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा के इजराय को रोकने की शक्ति	२६
८२	रमिशनर के अभिलेख (Record) आदि संग्रहाने के अधिकार और सरकार अथवा बोर्ड को मामला विचारार्थ भेजना	२६
८३	रेकड संग्रहाने एवं आदेशों के पुनर्वाचन की सरकार की शक्ति	२७
८४	रेकड संग्रहाने तथा आदेश पर पुनर्वाचन करने सम्बन्धी बोर्ड के अधिकार	२७
८५	मुनघाई	२७
८५अ	राज्य सरकार द्वारा नजरसानी	२७
८६	बोर्ड एवं न्यायालयों द्वारा पुनर्विचार	२८
८७	एक्ट सं० ६ सन १९०८ का प्रभाव	२८

अध्याय ६

भूमि

८८	जिन पर किसी दूसरे का अधिकार न हो वे समस्त मार्ग व समस्त भूमि राज्य की सम्पत्ति होंगे।	२८
८९	एनिज पदार्थ खान खोदने और मछली पकड़ने का अधिकार	२९
९०	रानस्व या लगान की अदायगी या उत्तरदायित्व समस्त भूमि पर	३१
९०क	कृषि की भूमि को गैर कृषि कार्यों में प्रयोग	३२
९१	भूमि पर अनाधिकृत आधिपत्य	३३
९२	विरोध कार्यार्थ भूमि को विलग करना	३४
९३	चारागाह के उपयोग का नियमन	३४
९४क	खण्ड के किनारे वृक्ष	३५
९४ख	अनाधिकृत रूप से काम में लिये गये बिना आज्ञा के पेड़ों आदि की रकम की वसूली	३५
९५	आवादी का विकास	३५
९६	प्रीमियम की दरें कन्स्टट नियत करेगा	३६
९७	आवादी की भूमि की निलामी	३७
९८	घास भरने के कोठे तथा कूड़ा करकट भरने की भूमि	३७
९९	गावमें भवन निमाण के नियमन की शक्ति	३८
१००	औद्योगिक एथम् व्यायसायिक क्षेत्रों की भूमि का विनियम	३८
१०१	कृषि कार्यों के लिये भूमिका आवंटन	३८
१०२	विरोध शान पर तथा कृषि के अनिश्चित अन्य कार्यों के लिये सरकार द्वारा भूमि का आवंटन	३९
१०२क	भूमि जो स्थानीय अधिकारियों को सौंपी जाय	३९
१०२	प्रकरण ६ के लिय भूमि और आवासी का परिभाषा	३९

१०८	स्थानीय सस्थाओं द्वारा जिन मामलों में राज्य अधिकारियों के अधिकार प्रयोग में लाये जायेंगे	४०
१०५	राज० टैन्सी अधिनियम संख्या ३ आक १६५५ की धारा ३१ के अधीन आसामियों द्वारा प्राप्त अधिकार अप्रगृहीत	४०

अध्याय ७

भूमी-मापन और अभिलेख संग्रह

(क) सामान्य

१०६	भूमापन तथा पुनः भूमापन	४०
१०७	अभिलेख संग्रह कार्यक्रम	४१
१०८	भूलेखाधिकारी	४१
१०९	कार्य के सम्पादन का विवाद	४१

(ख) सीमा विवाद

११०	सीमा विवादों की भूमापन में सहायता	४१
१११	सीमा सम्बन्धी विवाद का निष्पत्ति	४१

(ग) नक्शा एवं तस्तरा

११२	नक्शा एवं तस्तरा बनाना	४२
-----	------------------------	----

(घ) अधिकार अभिलेख

११३ ✓	अधिकार अभिलेख	४२
११४ ✓	अधिकार अभिलेख के अंग	४२
११५	ऐसी भूमि के सम्बन्ध में यदि आमतिन करना जिसका कोई स्वामी न हो	४३
११६	अनाधिकृत भूमि को सार्वजनिक कार्यों में प्रयुक्त किये जाने की प्रक्रिया	४३
११७	ऐसी भूमि पर सीमित अधिकार होने की दशा में कार्यवाही	४३
११८	निर्धारण एवं सुदृढीकरण भूमि का रकार्ड	४४
११९	किसी गांव की आबादी का निधारण	४३
१२०	ग्राम पंचिका	४४
१२१ ✓	सर्वोत्तम में दर्ज किये जाने वाले विवरण	४४
१२२	इन्द्राजा का सत्यापन और मजदूरों का निर्णय	४५
१२३	आसामी के वर्ग का निधारण	४५
१२४	देय राज्य अथवा लगान के सम्बन्ध में विवाद	४५
१२५	अधिकार अभिलेख की प्रविष्टियों के विषय में उदाहरण मजदूरों का निपटारा	४५
१२६	यन्त्रमान लेख संग्रह का प्रयोग	४६
१२७	भूमापन एवं भूलेख कार्यक्रम की समाप्ति पर विचारार्थ अग्रिम विवाद	४६

(ड) मानचित्र रास्ते की गुंथा

१२८	सीमा सम्बन्धी विवाद	१६
१२९	सीमा चिह्न के सम्बन्ध में भूमि धारिया का उत्तर दायित्व	१६
१३०	सीमा चिह्न को नष्ट करने या हटाने पर शास्ति	१७
१३१	मानचित्र रास्ते का प्रबंध	१७

✓ (च) वार्षिक पत्रिका

१३२	वार्षिक पत्रिका	१७
१३३	उत्तराधिकारी तथा कर्त्तबेहरे हरान्तरण का रिपोर्ट	१७
१३४	रिपोर्ट देने में लापरवाही करने पर दण्ड	१८
१३५	रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर कार्यवाही	१८
१३६	विवादों पर निष्पत्ति	१८
१३७	सम्पत्तियों की विरासत	१९

(छ) निविध

१३८	अभिलेख का निरीक्षण	१९
१३९	प्रतिष्ठिया की नकल	१९
१४०	प्रतिष्ठियों के विषय में कल्पना	१९
१४०क	खुदकाशत इदनात सम्बन्धि विवाद अस्त प्रतीया	१९
१४१	निर्णय राजस्व न्यायालयों को माँग होगा	१०

अध्याय ७क

✓ आमादी क्षेत्रों का सर्वेक्षण चेमाइश

१४१का, परिभाषाये	२०
१४१का, सर्वेक्षण की आज्ञा देने की शक्ति	२१
१४१गा, भूमि में प्रवेश	२१
१४१घा, सर्वेक्षण का नोटिस पहले दिया जाना	२०
१४१डा धारा १४१ घा के अधीन नोटिस तामील किये जाने के प्रचालन व्यवस्था	२०
कार्य का प्रारम्भ किया जाना	२०
१४१चा सर्वेक्षण का नक्शा तथा रजिस्टर	२०
१४१द्वा सीमा चिह्नों का लगाया जाना	१३
१४१जा अस्थायी सीमा चिह्नों का संचालन	२३
१४१भा सीमाओं के सम्बन्ध में विवाद	२३
१४१बा कलक्टर को अपील की जाना	२४
१४१टा पंचायत को निर्णय हेतु भेजने की शक्ति	२४
१४१ठा सर्वेक्षण से सम्बन्धित दस्तावेजों को, सर्वेक्षण अधिकारी या जम्माज अधिकारी के पास भेजा जाना	२४

- १८१३ नक्शा तथा रजिस्टरो का सधारण
 १८१४ सर्वेक्षण शुल्क
 १८१५ सर्वेक्षण का खर्चा
 १८१६ नोटिस की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में बिन्दु
 १८१७ नक्शा, रजिस्टरो तथा अन्य दस्तावेजों का निर्माण
 की प्रतिया
 १८१८ नियम
 १८१९ कार्यशक्ति या अनौपचारिकता (enformality)
 १८२० नक्शा तथा रजिस्टरो में प्रविष्टियों के सम्बन्ध में

अध्याय

भू प्रमन्त्र सभ

(क) सामान्य

- १८२ भू प्रमन्त्र तथा पुन भू प्रमन्त्र
 १८३ पुन बंदोस्त के अनुमानन परिणाम
 १८४ पुन बंदोस्त के औचित्य को तय करने के
 १८५ भू प्रमन्त्र अधिकारी
 १८६ भू प्रमन्त्र अधिकारी को भूलेख अधिकारी के
 १८७ नियम

(ख) लगान की दरें

- १८८ आर्थिक सर्वेक्षण
 १८९ कर निर्धारण क्षेत्र या वर्ग
 १९० मिट्टी का वर्गीकरण
 १९१ लगान की दरों का विकास
 १९२ लगान दरों का आधार
 १९३ दरों का मसौदा
 १९४ निर्णीत एवं अभिलेख मामले
 १९५ प्रस्तावों का प्रकाशन तथा प्रस्तुती करण
 १९६ प्रस्तावों की रीति

(ग) लगान का

- १९७ लगान का निधारण
 १९८ निर्धारण अप्रभावित भूमि
 १९९ विकास के लिए मुक्ति
 २०० लगान निधारण के समय धनमान लगान
 २०१ वृद्धि की सीमा
 २०२ प्रगतिशील वृद्धि

१६३ 'चाही जोत' के लगान निधारण के लिए अतिरिक्त प्रायधान	६०ग
१६४ पचां का निर्माण तथा वितरण	६०घ
१६५ पैदानारी लगान की बसूली पर अन्तरिम अवरोध	६०घ
१६६ आपत्तियों की सुनवाई तथा लगान का निधारण	६०ङ
१६७ लगान किस दिनांक से देय होगा	६०झ
१६८ नियत लगान की अस्वीकृति करने का कृपक को विनय प्राप्त होगा	६०च
१६९ अस्वीकृति का प्रतिफल	६०च
१७० जोत का अन्य व्यक्ति को दिया जाना	६०च
१७१ स्वीकृति के उपरांत जांचा	६०च
१७२ बन्दोबस्त की अवधि के भीतर लगान नहीं बढ़ेगा	६०च
१७३ ग्राम के दस्तूर का निर्माण	६०छ
१७४ बन्दोबस्त का प्रमाणपत्रों की परिकल्पना	६०छ

(घ) बन्दोबस्त की अवधि

१७५ बन्दोबस्त की अवधि	६०छ
१७६ बन्दोबस्त की अवधि की शुरुआत	६०ज
१७६ बन्दोबस्त की पूर्ण समाप्ति	६०ज
१७६क बन्दोबस्त करने के दौरान में, अन्तरिम सहायता	७०अ
१७७ समाप्त किये गये बन्दोबस्त के अन्तगत भूमि का नये बन्दोबस्त तक स्वरूप	६०झ

(ङ) मध्यवर्ती पुनर्वाचन

१७८ अल्प कालीन बन्दोबस्त	६०झ
१७९ प्रवाह से हुये भू क्षय और कच्चा भूमि के बन्दोबस्त पर निधारण का पुनर्वाचन	६०झ
१८० सरकार को अतिरिक्त राहरी दर बसूल करने का अधिकार	६०झ

(च) नियम

१८१ बन्दोबस्त के कार्य की समाप्ति के समय बन्दोबस्त अधिकारी के पास विचाराधीन प्रार्थना पत्र एवं कार्यनाहिया	६०झ
१८२ भूल चुक का सरोधन	६०झ
१८३ स्वीकृत लगानदरों पर पुनर्विचार	६०झ

अध्याय ६

सम्पत्तियों का वितरण

१८४ वितरण	६१
१८५ वितरणीय सम्पत्तियाँ	६१
१८६ व्यक्ति को कि रिमानन के अधिकारी होंगे	६१
१८७ वितरण का आवेदन पत्र	६१

१८८	प्रार्थना पत्र कैसे प्रस्तुत हो	६१
१८९	विभिन्न तिलों में अग्रस्थित सम्पत्तियों का बंटवारा	६२
१९०	मागों का एकीकरण	६२
१९१	सम्पत्ति के विभाजन को रोकने की शक्ति	६२
१९२	विभाजन के आवेदन पत्र की घोषणा	६२
१९३	टाइटल के सम्बन्ध में आपत्ति	६२
१९४	अपील के निर्णय तक विभाजन पर रोक	६३
१९५	विभाजन की पूर्णता के पूर्व सम्पत्ति की कुर्की	६३
१९६	तजरीन की प्रणाली	६३
१९७	सिद्धांत के निर्धारण व मूल्यांकन की शर्तें	६४
१९८	विभाजन के लिए प्राथमिक आदेश	६४
१९९	विभाजन कौन करेगा	६५
२००	संविदा सम्मत विभाजन	६५
२०१	पंचों द्वारा विभाजन	६५
२०२	न्यायालय द्वारा विभाजन करेगा	६६
२०३	विभाजन व्यवस्था का अनुमान और उसकी वस्तु	६६
२०४	अमीन आदि की नियुक्ति और बारीक जारी करना	६६
२०५	वारंट निष्पादन की प्रणाली	६६
२०६	घोषणा करना	६७
२०७	प्रस्तावों पर विचार तथा दावों एवं आपत्तियों का निरूपण	६८
२०८	कृषक की ज़ोत का विभाजन	६८
२०९	सुदक्षरत की भूमि	६८
२१०	संयुक्त भूमि का आर्गटन	६८
२११	आर्गटिड भूमि पर किसी हिस्सेदार का मकान या बाड़ा आदि	६८
२१२	तालाब, कुये, जल प्रणालियाँ और पाल	६९
२१३	देयस्थान, रमशान अथवा फ़रगाह	६९
२१४	असंपठित विभाजन अस्वीकृति का आधार	६९
२१५	विभाजन के परचातु शहर का वितरण	६९
२१६	विभाजन का अन्तिम आदेश	६९
२१७	बंटवारे के फागनात	७०
२१८	विभाजन पर आर्गटिड सम्पत्ति का कटना देना	७१
२१९	सम्मिश्रित सम्पत्तियों का बंटवारा	७१
२२०	शहर का प्रपञ्चनात्मक अथवा धामक वितरण	७१
२२१	कम निधारित सम्पत्तियाँ अधिक निधारित को वापिस छोटा देगी	७१
२२२	एक गाँव की विभिन्न सम्पत्तियों का एकीकरण	७१
२२३	सरकार एवं सम्पत्तिधारी के मध्य में होने वाले विभाजन के सम्बन्ध में यह अध्याय लागू नहीं होगा	७१

अध्याय १०

राजस्व-संग्रह

२२४ भूमि और उसने उत्पादन पर प्रथम भार के रूप में राजस्व	७२
२२५ राजस्व का उत्तरदायित्व	७२
२२६ अशरोपा के भुगतान के नियम और दोषी	७३
२२७ प्रमाणित हिसाब अशरोपा की साक्षात् होना	७३
२२८ दातव्यों की वसूली की मायनाही	७३
२२९ मागपत्र एवं उपस्थिति पत्र	७३
२३० चल सम्पत्ति की कुर्की एवं विक्री	७३
२३१ भूमि की कुर्की	७४
२३२ कर्ता के अधिकार और आभार	७४
२३३ कुर्की की घोषणा	७४
२३४ दोषी के भाग का हस्तांतरण	७४
२३५ दोषी के निर्विण्ट हल्के, पट्टी या सम्पत्ति का विक्रय	७५
२३६ भूमि का विक्रय भार मुक्त होगा	७५
२३७ दाप से असम्पन्न सम्पत्ति में निहित दोषी के हिता के विरुद्ध कार्यवाही	७५
२३८ विक्रय की घोषणा	७६
२३९ विक्रय कर और क्रिसके द्वारा होगा	७६
२४० विक्रय के सम्बन्ध सम्पत्ति पर बोली लगाने और उसके ग्रहण करने पर निषेध	७६
२४१ विक्रय को रोकना	७६
२४२ खरीददार द्वारा धरोहर रखना व उसके अभाव में पुनर्विक्रय	७६
२४३ क्रय के मूल का चुकाया जाना	७७
२४४ पुन विक्रय से होने वाली हानि के लिए क्रेता का दायित्व	७७
२४५ पुन विक्रय के पूर्ण घोषणा	७७
२४६ अशरोप के जमा होने पर विक्रय की निर्मूल करने का आवेदन पत्र	७८
२४७ अनियमित इत्यादी की वजह से विक्रय को निर्मूल करने का आवेदन पत्र	७८
२४८ विक्रय को पुष्ट अथवा निर्मूल करने हेतु आग्रा	७८
२४९ अनियमितता अथवा गलती पर आधारित दावा पर प्रतिबंध	७८
२५० विक्रय के रद्द होने पर क्रय राशि की जापिसी	७८
२५१ क्रेता को आधिपत्य दिलाना व विक्रय प्रमाण पत्र देना	७९
२५२ विक्रय की आमदनी का प्रयोग	७९
२५३ राजस्व या लगान के विषय में क्रेता का दायित्व	७९
२५३ भागीदारों या साझीदारों के सम्बन्ध में पूर्ण क्रियाधिकार	७९
२५५ अधिनियम व प्रभावशाल होने के समय अशरोपा के लिय प्रावधान	८०
२५६ विविध राजस्व और अन्य राशिआ की वसूली	८०
२५७ प्रतिभूतियों से धनराशि की वसूली	८०

अध्याय ११

विविध

२५७क धारा २५६ व २५७ में निर्दिष्ट धन राशियां की वसूली के लिये आवदन पत्र	८१
२५७ख विरोधपत्र (प्राटेस्ट) के अधीन भुगतान तथा भागे का उपचार	८२
२५७ग व्यक्ति जिससे धनराशि प्राप्त है की परिभाषा	८२क
२५७घ इस अध्याय के प्रावधानों पर अधिनियम के प्रारम्भ के समय देय समस्त धनराशियों पर लागू होना	८२क
२५८ व्यय यदि की वसूली	८२क
२५९ दीवानी यादानी का क्षेत्राधिकार बहिष्कृत होगा	८२ख
२६० प्रत्यायोजन	८२ख
२६१ नियम बनाने का अधिकार	८२ग
२६२ पटवारी इत्यादि जन-सेवक होंगे	८३
२६३ परित्राण एवं क्षण्डन	८३

प्रथम अनुसूची (धारा २३ देखिये)

याचिक मामला की सूची	८८
---------------------	----

द्वितीय अनुसूची (धारा २६३ देखिये)

सूची उन अधिनियमों की जा रहे कर दिये गये	८८
---	----

राजस्थान राजस्व विधियां (विस्तार) अधिनियम १९५७

१ सक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ	९०
२ परिभाषाएं	९०
३ राजस्थान राजस्व विधियों का संशोधन	९०
४ राजस्थान राजस्व विधियों में सामान्य रूपभेद	९०
५ राज राजस्व विधियों तथा उनसे अलग निमित्त नियमों आदि का विस्तार	९०
६ अधिकारियों तथा प्राधिकारियों का निर्देश	९१
७ भय लगाने का नियम	९१
८ कठिनाइयां को दूर करने की शक्ति	९१
९ निरसन तथा परित्राण	९२

प्रथम अनुसूची

नोट	९२
-----	----

द्वितीय अनुसूची (देखिये धारा ९)

निरस्त की गई अधिनियमवित्तियों की सूची	९२
---------------------------------------	----

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, १९५६

(राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट)

[राष्ट्रपति द्वारा २३ मई १९५६ को स्वीकृत]

[एक्ट संख्या १५, सन् १९५६ ई०]

[राजस्थान राजपत्र गजट विशेष दिनांक १ जून १९५६ के खण्ड ४ में प्रकाशित हुआ]

भूमि, राजस्व अदालतों, राजस्व अधिकारियों एवं ग्राम सेवकों की नियुक्ति उनके हक और कर्तव्य, भूमि के नक्शों व रेकार्डों के बनाने-एवं सुरक्षित रखने, राजस्व एवं लगान के निर्धारण, सम्पत्ति के विभाजन, राजस्व के संग्रह एवं वसूलन की कानून के परीक्षण एवं संशोधन हेतु,

एक

अधिनियम

भारत गणराज्य के मातृवर्ष वर्ष में राजस्थान राज्य विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में निर्मित हुआ—

(नोट 'ग्राम अधिकारियों' विलोपित—राज एक्ट १८ सन १९६१।)

अध्याय १

प्रारम्भिक

[धारा १] संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ — (१) यह अधिनियम राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम १९५६ कहलायेगा।

(२) इसका विस्तारक्षेत्र सम्पूर्ण राजस्थान राज्य होगा।

(टिप्पणी—[यह अधिनियम मात्र अजमेर और मुनेन क्षेत्र के लिए भी दिनांक १५ जून १९५६ से, जिस दिन से राजस्थान अधिनियम १९५६ संख्या २ राजस्व विभाग (ग) की विनियम संख्या एक (१८१) राजस्व / ६/५६-निका-७५-३-५८ को राजस्थान राजपत्र गजट १८ दिनांक २३ मई १९५६ के पृष्ठ ७५१ में प्रकाशित किया गया, लागू हुआ]

(३) यह [सरकारी गजट] में, राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित विज्ञप्ति में नियुक्त दिनांक से प्रभाव में आयेगा। १-६-५६

[धारा २] अधिनियम से अप्रमाणित कानून — इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान की व्याख्या यों नहीं की जायेगी कि जिससे राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्गठन अधिनियम १९५२ (एक्ट नं० ६ सन् १९५२) [या अजमेर अयोध्या नगर आरु इण्टरमीडियरी एण्ड रिफोर्म एक्ट १९५५ (अजमेर का एक्ट ३ सन् १९५५)]

या मोम्ने मन्ड टरीटरीज एण्ड गरियाग (जागीर अगोलोशन) एक्ट १९५३ (मोम्ने एक्ट XXXIV आफ १९५४) जहा तक रिचर्ड आयू कुत्र को लागू होता है या मध्य भारत जमींदारी अगोलोशन एक्ट, सन् २००८ (मध्यभारत एक्ट १३ आफ १९५१) और मध्य भारत अगोलोशन आफ नागार एक्ट मध्य २००८ (मध्य भारत एक्ट २८ आफ १९५१) जहा तक यह सुनेल या क्षेत्र को लागू होता है। राजस्थान मंजिल भू-प्रबंध अधिनियम १९५३ (एक्ट सं० १६ सन् १९५३) या राजस्थान टीने सो एक्ट १९५४ (एक्ट संख्या ३ १९५५) या राजस्थान पंचायत अधिनियम १९५३ (एक्ट संख्या २१ सन् १९५३) अथवा धारा २६३ द्वारा स्थापित नहीं किये गये किसी अन्य कानून या विधान के प्रावधान की प्रभावशीलता को प्रभावित करें या उस पर प्रतिबंध लगाय।

(धारा ३) व्याख्या — (१) विषय अथवा सदस्य द्वारा प्रयुक्त शब्दों का अर्थ निम्न होने पर इस अधिनियम में—

(१) 'लैंड रेकॉर्ड आफिसर' का अर्थ कन्क्टर से होगा और इमर सहायक अथवा अतिरिक्त लैंड रेकॉर्ड आफिसर भी सम्मिलित हैं

(क) 'म्युनिसिपैलिटी' से मतलब यह होगा जिससे तात्पर्य राजस्थान टाउन म्युनिसिपैलिटी एक्ट १९५१ (राजस्थान एक्ट २३ आफ १९५१) से या अन्य किसी म्युनिसिपल कानून से जो फिलहाल लागू हो से है,

(ख) 'नजूल भूमि' से अभिप्राय राज्य सरकार के मातहत उस आमादी भूमि से है जो म्युनिसिपैलिटी या पंचायत सर्किल या, गांव कस्बा या शहर की सीमा के अंदर है।

(ग) 'पंचायत सर्किल' से तात्पर्य उस मतलब से है जिसका मतलब राजस्थान पंचायत कानून १९५३ (राजस्थान एक्ट २१ आफ १९५३) या अथवा किसी पंचायत कानून जो फिलहाल लागू हो से है।

[] टिप्पणी — [राजस्थान अधिनियम सभा २, १९५८ के सत्र ४ द्वारा जो राजस्थान एक्ट, सत्र ४ में विधेयक दिनांक ११ १५८ द्वारा परिवर्तित किया गया]

(२) 'निवारित' से अर्थ इस अधिनियम अथवा इसके अधीन निर्मित नियमों द्वारा निर्धारित से होगा,

(३) किसी पार्टी (पक्ष) के स्वीकृत प्रतिनिधि से तात्पर्य इस अधिनियम के मातहत बनाये गये नियमों के अंतर्गत किसी ऐसे व्यक्ति से होगा जो पार्टी द्वारा उसके लिये हाजिरी देन प्रार्थनापत्र पेश करने एवं अन्य कार्य करने के लिये अधिकृत किया गया हो

(३ का) 'राजस्व अपील प्राधिकारी' से अभिप्राय उस अधिकारी से होगा जो धारा २० का के अंतर्गत ऐसे रूप में प्राधिकारी नियुक्त किया गया हो,

(४) 'भू प्रबंध अधिकारी' में सहायक भू प्रबंध अधिकारी भी सम्मिलित होगा,

(५) 'गांव से अभिप्राय ऐसे भूमि खण्ड से होगा जो स्वीकृत होकर रेकॉर्ड कर लिया गया है अथवा भविष्य में स्वीकृत होकर रेकॉर्ड कर दिया जाय

(६) इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी अधिकारी को किये गये सदम या अभिप्राय किसी ऐसे सदम से भी होगा जे कि उसी दूँ पर उसी रीति से आंतरिक अधिकारी की हैधियत से नियुक्त किये गये अधिकारियों को किया गया हो,

(७) राजस्थान काउन्सिलर कानून १९५५ (अधिनियम संख्या ३ सन् १९५५) में परिभाषित शब्द एन फयन जहा कहीं इस अधिनियम में आय है, वैसा ही अर्थ प्रकट करेंगे जो कि उक्त कानून में उनके साथ लगाया गया है, और

(८) किसी अधिकार स्वतः या हित का बोझ उठाने जाने शब्द एवं कयन के अर्थ में ऐसे व्यक्ति के अधिकार, स्वतः या हित में उनके पूर्वगामी एवं अनुगामी व्यक्तियों को भी शामिल किया जायेगा।

अध्याय २

राजस्व मण्डल

[धारा ४] मण्डल की स्थापना एवं निर्माण — (१) राजस्थान राज्य के लिये एक राजस्व-मण्डल (BOARD OF REVENUE) की स्थापना की जायेगी और उसे अधिनियम में आगे केवल मण्डल या 'बोर्ड' के नाम से सम्मिलित किया जावेगा।

(२) इस बोर्ड का एक अध्यक्ष होगा तथा अन्य ऐसे सदस्य होंगे जिनकी नियुक्ति राज्य सरकार समय समय पर करेगी और ऐसे सदस्यों की संख्या कम से कम ३ होगी।

(३) उप धारा (१) के अधीन की गई सभी नियुक्तियों की सूचना [सरकारी गजट] में प्रकाशित की जायेगी।

(४) राज्य सरकार बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिये योग्यतायें निर्धारित करेगी।

[धारा ५] सदस्यों की कार्यविधि — [गवर्नर] के आदेशानुसार बोर्ड के सभी सदस्य अपना २ पद भरण करेंगे।

[धारा ६] बोर्ड की बैठक का स्थान — राजस्व मण्डल का मुख्य कार्यालय [अथर्व] में रहगा लेकिन राज्य सरकार की विशेष या साधारण हिदायतों के अधीन वह क्षेत्राधिकार में किसी भी स्थान पर बैठक कर सकेगा।

इस सरकार ने इस धारा ५ ध्यान राजस्व मण्डल के सदस्यों की योग्यताएँ निर्धारित महा की प्रत्येक माना कनाम कयाण — १९६६ धारा ० धारा ० की ० २५० में राजस्व मंडल द्वारा पूर्ण याचालय (पुनर्बैध) में ब ड की स्थापना को पर कानूनी करार दे दिया बाद में राजस्थान ०७-११ मन् १९६६ के द्वारा उक्तो के धन प्रणाल की गई है।

[धारा ७] सचिवालय अधिकारी.—बोर्ड के लिये एक रजिस्ट्रार की तथा ऐसे फमचारीगण की नियुक्ति की जायेगी, जो इस अधिनियम द्वारा या वतमान में प्रभावशील किसी अन्य विधान नियम या आज्ञा द्वारा या उसके अंतर्गत बोर्ड के लिये नियत कतव्यों के पालनार्थ या बोर्ड की प्रदत्त अधिकारी के लिये आवश्यक हों।

(१) राज्य सरकार के विशेष व साधारण आदेशों के अधीन उपधारा (१) के अन्तर्गत नियुक्त रजिस्ट्रार तथा अन्य अधिकारी ऐसे अधिकारों का प्रयोग करेंगे और ऐसे कतव्यों का पालन करेंगे जिसका बोर्ड निर्देश करे।

[धारा ८] बोर्ड की शक्तियाँ —(१) बोर्ड इस अधिनियम के अधीन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम १९५५ (अधिनियम संख्या ३, सन् १९५५) या प्रभावशील किसी अन्य विधि के अंतर्गत रहते हुए, राजस्थान के पुनर्निवेदन, निगरानी अथवा प्रसंग के लिये सबसे बड़ी राजस्व अदालत होगी।

परंतु शर्त यह है कि जहां कहीं किसी दीवानी या किसी राजस्व अदालत के बीच उनके क्षेत्राधिकार एवं विचारार्थिकार के सम्बन्ध में कोई संदेह या विवाद होगा तो ऐसे मामले में हाई कोर्ट द्वारा दिया गया निर्णय राजस्थान [राज्य] की सभी दीवानी व राजस्व अदालतों के लिये जिसमें बोर्ड भी सम्मिलित होगा अंतिम व मान्य होगा।

(२) उपधारा (१) में उल्लिखित शक्तियों के अन्तर्गत बोर्ड ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा जो समय २ पर राज्य सरकार द्वारा उसे प्रदत्त की जाय अथवा इस अधिनियम द्वारा या इसके अंतर्गत अथवा वतमान में प्रभावशील किसी अन्य विधि के द्वारा या उसके अंतर्गत बोर्ड को प्रदान किये जाय या उस पर आरोपित हों।

[धारा ९] अधीन राजस्व-अदालत पर आम निगरानी—इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अंतर्गत सभी राजस्व अदालतों एवं राजस्व अधिकारी बोर्ड के अधीन रहेंगे तथा ऐसी अदालतों एवं अधिकारों पर आम निगरानी एवं नियंत्रण रखने का बोर्ड का अधिकार होगा।

[धारा १०] मण्डल के क्षेत्राधिकार का प्रयोग—(१) सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में अथवा उसके किसी भाग विशेष में वतमान में लागू किसी विधि या विधान में अथवा प्रस्तुत अधिनियम के अधीन या इसके अंतर्गत निर्मित नियमों द्वारा प्रावहित किये जाने के अतिरिक्त और इस विषय में निर्मित नियमों के अधीन, बोर्ड का क्षेत्राधिकार प्रयुक्त किया जायगा—

(ग) अध्यक्ष अथवा बोर्ड के किसी अन्य अंग्रेज सदस्य द्वारा, या

(ख) दो या दो से अधिक सदस्यों द्वारा निमित्त बोर्ड की किसी बैठक द्वारा

परंतु शर्त यह है कि किसी अकेले सदस्य द्वारा न्ये गये निर्णय से असन्तुष्ट पक्ष को ऐसे अकेले सदस्य द्वारा निर्णय दिये जाने की शारीर के वा एक मास की अवधि से भीतर दो या दो से अधिक सदस्यों द्वारा निर्मित बोर्ड की किसी वेंच के समक्ष पुनर्निवेदन करने का अधिकार होगा यदि निर्णय देने वाला सदस्य यह घोषणा करता है कि यह मामला अपील किये जाने योग्य है।

[धारा १०] (२) बोर्ड में एक चेयरमैन व कम से कम ३ और अधिक से अधिक सदस्य होंगे।

[धारा १०] (३) उपधारा (१) के अधीन किया गया प्रत्येक कार्य या प्रभावित किया गया प्रत्येक आदेश अथवा उपधारा (२) के अधीन विवरण या जिम्माजन् के अनुसार किया गया कार्य या दिया गया आदेश बोर्ड का ही कार्य अथवा आदेश जैसी भी स्थिति हो, समझा जावेगा।

[धारा १०] (४) कोई भी व्यक्ति बोर्ड का मेम्बर नियुक्त नहीं किया जाएगा तब तक कि वह आई ए० एस के रूप में कम से कम १२ वर्ष तक कार्य न कर चुका हो।

[धारा ११] वेंच में परामर्श हेतु मामला भेजने का अधिकार—एक ही स्थिति में कार्य करने वाला अध्यक्ष या बोर्ड का कोई अन्य सदस्य यदि उचित समझे तो उस विषय के कारणों को लेखबद्ध करने के उपरान्त ऐसे किसी भी कानून के या रिवाज के जो कानून के समान ही प्रभावशील हो या उसी मामले में पेश किये जाने वाले किसी कानून की बनावट के प्रश्न को वेंच के परामर्श के लिये भेज सकता है और ऐसा मामला या कार्यवाही वेंच की राय के अनुसार ही निपटाई जायेगी।

इस धारा के अधिन उन मामला में स्वैगम अपील वेग नहीं हो सकती कि जिनम अपील के माँग मातरी होते हैं। राजस्व मण्डल का निर्णय सरकार द्वारा राबत हिम्मतसिंह-१९६६ धार० धार० बी०-१४० को मसुदा करत हुए राजस्थान व न-यापालय ने राबत हिम्मतसिंह बनाम राज्य सरकार की रिट याचिका १९७० धार० धार० बी० ५२ में राजस्थान कोरेस्ट एक्ट के अधीन स्वैगल अपील मुकने की राह की मनाही की है। इस निष्ठय से बोर्ड का फलता वेतल बाबा स्टोर एंड क्रोरी प्राइवेट लि० बनाम राज्य सरकार १९६५ धार० धार० बी० ८२ भी प्रभावित होता है। ए० आई० धार० १९५८ सर्वोच्च न्यायालय १९८० की स्वीकार करने हुए बोर्ड ने यनरयाम बनाम महत रामचरणदास १९६४ धार० धार० बी० २३३ में निर्णय दिया कि किसी हुजम मन्तनई की दरखास्त पर अपील का पमना पन्तिप निर्णय नहीं होता है अपवा उप धारा (१) के अधीन ऐसे मामला में आई अपील नहीं मुनी जा सकती है क्योंकि अधिन एक मुन अधिका होता है। ए० आई० धार० १९५७ सर्वोच्च न्यायालय-४०४।

इस धारा व अधीन आई का बोर्ड भी लख पाठ (बैच) किसी अधिका सख्या वाले या गुर्ल न्यायालय (कुन बैच) की जिमा भी प्रश्न पर रेफरेंस कर सकता है। पनेसिंह बनाम गुमानसिंह १९६४ धार० धार० बी० १०१।

[धारा १२] किंगी प्रश्न को उच्च न्यायालय के विचारार्थ भेजना —

(१) धारा ११ में उल्लिखित किसी मामले में उठाये गये प्रश्न को यदि बैंच आम जनता से सम्बन्धित मानत हुए महत्वपूर्ण समझे और यह भी विचार करे कि उस पर उच्च न्यायालय की राय लेना उचित होगा तो यह ऐसा प्रश्न हाईकोर्ट की राय के लिये भेजेगा।

(२) उच्च न्यायालय ऐसी सुनवाई के बाद निम्ने यह उचित समझे इस प्रकार भेजे गये प्रश्न पर अपनी सलाह को लेख्यद्वारा करेगा और उस मामले का निर्णय ऐसी सलाह से सान्धरत होगा।

[धारा १३] मत भेद की समस्या में निर्णय — (१) जब कोई मामला बौद्ध की बैंच के द्वारा सुना जाता हो, ऐसे मामले का निर्णय सुनवाई करने वाले सदस्यों के बहुमत के अनुसार होगा।

(२) यदि ऐसे विषय में आज्ञा देने के सम्बन्ध में मतविभाजन परास्पर हो जाय तो यह विषय किसी अन्य सदस्य को विचार हेतु भेजा जावेगा तथा तत्परवाना सभी सदस्यों के बहुमत के अनुसार निर्णय दे दिया जायेगा जिसमें वे सदस्य भी सम्मिलित होंगे जिन्होंने कि विषय की पहली सुनवाई की थी।

[धारा १४] रजिस्टर आदि का रखा जाना — बौद्ध ऐसे रजिस्टर पुस्तकें और हिसान लिखाय धनरायेगा और उनकी व्यवस्था करेगा जो कि नियत किये जायें अथवा जिनकी बौद्ध के कार्या के निष्पादन हेतु आवश्यकता हो।

अध्याय ३

राजस्थान न्यायालय और अधिकारी

(क) क्षेत्रीय जिले

[धारा १५] क्षेत्रीय विभाजन — (१) राजस्थान के प्रयोक्त्रनाथ तथा राज्य के सामान्य प्रशासन के लिये समस्त राजस्थान में इतने जिले होंगे जितने कि राज्य सरकार उचित समझे।

(२) [प्रिलोपित]

(३) अपनी शक्तानुसार राज्य सरकार किसी भी जिले को सब डिविजनों में विभाजित कर सकती है। प्रत्येक सब डिविजन एक या एक से अधिक तहसीलों होंगी।

इस धारा के प्रावधान जायदादीवाणी की धारा ६८ के प्रावधानों से सहज ही मेल खाते हैं किन्तु राजस्थान टिने की एक्ट के अधिन यह धारा लागू नहीं होगी। गगाराम बनारस के राजस्थान १९६५ धारा १० धारा १० डी० ८ में बौद्ध को पुनः बैंच के तहत किया कि इस धारा में प्रयुक्त शब्द मामलों का का मतलब बजो के मध्य उत्पन्न विवाद किन्तु से होता है।

(४) राज्य सरकार यदि उचित समझे तो एक तहसील को उप-तहसीलों में विभाजित कर सकती है।

(५) इस धारा के अधीन निर्मित प्रत्येक जिले, सब डिविजन तहसील और उप तहसील की सीमा का राज्य सरकार निर्धारण करेगी।

(६) इस धारा के अन्तर्गत निर्मित सभी जिलों, सब डिविजनों, तहसीलों और उप तहसीलों की सूचना राजस्थान सरकारी गजट में प्रकाशित की जायेगी।

(७) इस अधिनियम के प्रभावशील होने के समय वर्तमान जिले सब डिविजन, तहसीलें एवं उप तहसीलें [जिन किन्हीं स्थानीय नामों से बोले जाते हों] इस अधिनियम के अंतर्गत निर्मित जिले, सब डिविजन तहसीलें एवं उप-तहसीलों के रूप में तब तक कार्य करते रहेंगे जब तक कि इस सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन अथवा इस अधिनियम के अनुपालन में कोई अन्य प्रावधान नहीं कर दिये जाय।

[धारा १६] जिले आदि के निर्माण, उन्मूलन तथा परिवर्तन का अधिकार —
राज सरकार, राजस्थान में सरकारी गजट विज्ञप्ति प्रकाशित कर—

(क) नये जिलों सब डिविजनों, तहसीलों और उप तहसीलों का संगठन कर सकती है अथवा वर्तमान जिलों, सब डिविजनों, तहसीलों और उप तहसीलों की समाप्ति कर सकती है, और

(ख) इनमें से किसी की भी प्रादेशिक हद्दबन्दी में परिवर्तन कर सकती है।

(स) न्यायालय एवं अधिकारी

[धारा १७] [विलोपित]

[धारा १८] सेटलमेण्ट कमिशनर और अतिरिक्त सेटलमेण्ट कमिशनर—
राज सरकार समय-समय पर राज्य के लिये एक सेटलमेण्ट कमिशनर की नियुक्ति करेगा और अतिरिक्त सेटलमेण्ट कमिशनर की नियुक्ति ऐसी सख्या तक की जा सकती है जो उसकी राय में उचित हो।

[धारा १९] लेण्ड रेकार्ड्स डाइरेक्टर और सहायक भूलेख अधिकारी—
सम्पूर्ण राज्य के लिये राज सरकार एक डाइरेक्टर आर्क लेण्ड रेकार्ड्स की नियुक्ति करेगा तथा यह ऐसी सख्या में अतिरिक्त एवं सहायक भूलेख अधिकारी नियुक्त करेगा जो कि उसको आवश्यक प्रतीत हो।

[धारा २०] अन्य अधिकारियों की नियुक्ति—

- (क) (१) प्रत्येक जिले में एक कलक्टर जो कि जिले के लिये भूलेख अधिकारी भी होगा, और
- (२) प्रत्येक तहसील में एक तहसीलदार,
की नियुक्ति राज्य सरकार करेगी।
- (ख) (१) जिले में एक अतिरिक्त भूलेख अधिकारी,
(२) जिले में सेटलमेंट अधिकारी (गू प्रवाच अधिकारी)
(३) जिले में इतने सहायक फलक्टर, जितने कि वह उचित समझे और
(४) तहसील में इतने नायब तहसीलदार जितने कि वह उचित समझे कि
नियुक्ति राज्य सरकार कर सकती है—
- (ग) (१) किसी सहायक फलक्टर को जिले के एक या एक से अधिक
सब डिविजन का प्रभारी
(२) किसी तहसीलदार या नायब तहसीलदार को किसी एक या एक से
अधिक उप तहसीलों का प्रभारी—

राज्य सरकार स्थित करेगी और

- (घ) (१) किसी एक जिले के लिये दो या दो से अधिक जिलों के सम्मिलित क्षेत्र
के लिये किसी अतिरिक्त फलक्टर और
(२) किसी एक तहसील के लिये या दो या दो से अधिक तहसीलों के सम्मिलित
क्षेत्र के लिये अतिरिक्त तहसीलदार—

राज्य सरकार नियुक्त कर सकती है।

[धारा २० का]—राजस्व अपील प्राधिकारी—(१) राज्य सरकार राजस्व यायिक
घादों Revenue Judicial cases तथा ऐसे अन्य मामलों में जो विधि द्वारा विशेष
रूप से प्रावहित किए जाय के नियम में अपील पुनरीक्षण तथा निर्देश (References)
प्राप्त करने उनकी सुनवाई करने तथा उनका निपटारा करने के लिए इतने अधिकारी
जो, तीन से कम न होते हय आवश्यक प्रतीत हों नियुक्त कर सकेगी।

(२) इस प्रकार नियुक्त प्रत्येक अधिकारी राजस्व अपील प्राधिकारी कहलायेगा
तथा वह अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग तथा अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए ऐसे
स्थान या स्थानों पर, जिनका राज्य सरकार, समय समय पर, निर्देश दे, इजलास करेगा।

[धारा २१] पदन नियुक्तियाँ—धारा १७ या १८ या १९ या २० अथवा धारा
२० का के अधीन कोई भी नियुक्ति कार्यालय के निमित्त की जा सकती है।

[धारा २७] नियुक्तियों की विनियमिता—धारा १७ से धारा २१ के अधीन की गई सभी नियुक्तियां राजस्थान सरकार के गृह में विज्ञापित की जायेंगी, किंतु शर्त यह है कि नायब तहसीलदार की नियुक्तियों का ऐसा प्रकाशन आवश्यक नहीं होगा।

(ग) शक्ति

[धारा २३] नियंत्रक शक्ति—(१) राज्य में राजस्व से सम्बंधित सभी गैर अदालती विषयों में निम्न भू प्रत्यक्ष से सम्बंधित मामलों सम्मिलित नहीं होंगे, नियंत्रण की सत्ता राज्य सरकार में निहित होगी और सभी अदालती मामलों की तथा भू प्रत्यक्ष से सम्बंधित सभी मामलों के नियंत्रण की सत्ता रोड में निहित होगी।

(२) शब्द "अदालती विषय" से तात्पर्य ऐसी किसी कार्यवाही से है जिसमें कि किसी राजस्व अधिकारी या अदालत में उस विषय के व्यक्तियों के अधिकारों एवं उनकी निम्नोक्तियों का निश्चय करना पड़ता है, और प्रथम अनुसूची में निम्न विषयों को कार्यवाही और आलाय तथा पुनरावेदन देवरेल और सहम इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ अदालती विषय माने जायेंगे।

[धारा २४] राजस्व न्यायालयों एवं अधिकारियों की समस्त आधीनता—धारा ६ एवं धारा २३ के अन्तर्गत रहत हूँ—

(१) (बिलोपित)।

(२) किसी जिले में सभी अतिरिक्त जिलाधीश सत्र द्विविधनल अधिकारी सहायक जिलाधीश, तहसीलदार, अतिरिक्त तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार ऐसे जिले के कलक्टर के अधीन रहेंगे।

(३) किसी सत्र द्विविधन में सभी तहसीलदार अतिरिक्त तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार ऐसे सत्र द्विविधन के सब द्विविधनल अधिकारियों के अधीन होंगे।

(४) किसी तहसील में सभी अतिरिक्त तहसीलदार और नायब तहसीलदार पंजी तहसील व तहसीलदार के अधीन रहेंगे।

(५) सभी अतिरिक्त भू प्रत्यक्ष व आयुक्त जिलाधीश अतिरिक्त जिलाधीश भू प्रत्यक्ष व अधिकारी, तहसीलदार अतिरिक्त तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार सरलमेण्ट कनिस्टर के अधीन होंगे।

अधिक नियम व राजस्थान की आवश्यकता से मान कर नायब दिया जाता प्रमाणित है और तहसीलदार नियमों व मुताबिक प्रमाणन तथा सभी जमान की कोई मूका प्रमाणित व नियम नहीं बनावे और जमान का वास्तव उनके द्वारा मुद्रा के वास्तव में कर दिया है ता ऐसे मामलों में प्रमाणन नियमों के अनुसार करेगा।

(६) किसी तहसील में सभी तहसीलदार, अतिरिक्त तहसीलदार और नायब तहसीलदार, ऐसी तहसील में अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने वाले भू प्रबंध अधिकारी के आधीन रहेंगे।

(७) सभी अतिरिक्त एवं सहायक लेण्ड रेजिस्ट्रार, जिनाधीश अतिरिक्त जिनाधीश लेण्ड रेजिस्ट्रार अधिकारी तहसीलदार, अतिरिक्त तहसीलदार और नायब तहसीलदार, लेण्ड रेजिस्ट्रार का आधीन रहेंगे।

(८) किसी तहसील में सभी तहसीलदार, अतिरिक्त तहसीलदार और नायब तहसीलदार ऐसी तहसील में अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने वाले लेण्ड रेजिस्ट्रार अधिकारी के आधीन होंगे, और —————

(९) किसी स्थानीय क्षेत्र के लिए विशेष रूप से अध्याय ७ के अंतर्गत नियुक्त अधिकारी ऐसे क्षेत्र के लिए नियुक्त लेण्ड रेजिस्ट्रार अधिकारी के मातहत रहेंगे जबकि अध्याय ८ के अंतर्गत इस प्रकार विशेषज्ञ पर नियुक्त सभी अधिकारी ऐसे क्षेत्र के भू प्रबंध अधिकारी के आधीन होंगे। —————

[धारा २५] न्यायालयों और अधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य —

(१) प्रत्येक कलक्टर अथवा सन डिविजनल अधिकारी अथवा तहसीलदार क्रमशः अपने डिविजन, जिले सब डिविजन या तहसील में इस अधिनियम द्वारा या उसके आधीन या राजस्थान कार्यकारी अधिनियम, १९५५ (राजस्थान अधिनियम सं० ३ सन १९५५) अथवा वर्तमान में प्रभावशील किसी कानून के द्वारा या उसके आधीन प्रदत्त सभी अधिकारों का प्रयोग करेगा और आरोपित किये गये समस्त कर्तव्यों का पालन करेगा।

(२) राज्यभर के भू प्रबंध सूचनी सभी विषयों का प्रभारी भू प्रबंध आयुक्त होगा जो इसके सम्बन्ध में इस अधिनियम या वर्तमान में प्रभावशील किसी अन्य कानून द्वारा या उसके आधीन दिये गये सभी अधिकारों का प्रयोग करेगा तथा निर्धारित सभी कर्तव्यों को पूरा करेगा।

(३) समग्र राज्य की पैमाइश और भूलेख के निर्माण, पुनर्जांच एवं प्रबंध का प्रभारी भूलेख अग्रणी होगा जो इसके सम्बन्ध में इस अधिनियम द्वारा या वर्तमान में प्रभावशील किसी अन्य कानून द्वारा अथवा उसके अंतर्गत प्रदत्त सब शक्तियों का प्रयोग करेगा एवं सौंपे गये सभी कर्तव्यों का पालन करेगा।

(४) भूलेख अधिकारी अथवा अध्याय ७ के आधीन नियुक्त किया गया कोई भी अधिकारी इस अधिनियम या वर्तमान में प्रभावशील किसी अन्य कानून द्वारा या उसके अंतर्गत प्रदत्त सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा और सौंपे गये सभी कर्तव्यों का पालन करेगा।

(५) अध्याय ८ के अन्तर्गत नियुक्त किया गया कोई भी अधिकारी या भूप्रबंध अधिकारी इस अधिनियम या वर्तमान में प्रभावशील किसी अन्य कानून द्वारा या उसके अन्तर्गत प्रदत्त सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा और आरोपित किये गये सभी कार्यों का पालन करेगा।

(६) कोई अतिरिक्त भूप्रबंध आयुक्त या कोई अतिरिक्त सहायक भूलेख अभ्यक्ष या कोई अतिरिक्त जिलाधीश या कोई अतिरिक्त तहसीलदार उस क्षेत्र में जिसके लिए वह मقرر किया गया है क्रमशः भूप्रबंध आयुक्त या भूलेख अभ्यक्ष या जिलाधीश या तहसीलदार के ऐसे अधिकारों एवं कर्तव्यों का कि हों ऐसे विषयों या मामलों के समूह के सम्बन्ध में [इस कानून के अन्तर्गत जो उस समय लागू हों] जिनके लिये राज्य सरकार निर्देश करे, प्रयोग एवं पालन करेगा तथा प्रत्येक अतिरिक्त भूप्रबंध आयुक्त या अतिरिक्त या सहायक भूलेख अभ्यक्ष या अतिरिक्त जिलाधीश या अतिरिक्त तहसीलदार, उस क्षेत्र में जिसने लिये उसकी नियुक्ति की गई हो, ऐसे अधिकारों का प्रयोग या ऐसे कर्तव्यों का पालन करने के समय, सभी कार्यों के लिये आयुक्त या भूप्रबंधायुक्त या भूलेख अभ्यक्ष या कलक्टर या तहसीलदार जैसी भी सूरत हो, समझा जायेगा।

(७) कोई सहायक जिलाधीश या नायब तहसीलदार ऐसे जिले या तहसील के अन्तर्गत् जैसी भी स्थिति हो जिसके लिये वह नियुक्त किया गया है इस अधिनियम या वर्तमान में प्रभावशील किसी अन्य विधि या उसके आधीन प्रदत्त एवं आरोपित अथवा राज्य सरकार के किसी या मामांय या विशेष आदेश द्वारा समर्पित अधिकारों एवं कर्तव्यों का क्रमशः प्रयोग एवं पालन करेगा।

[धारा २६] न्यायालयों और अधिकारियों की अतिरिक्त शक्तियाँ —

- (१) [सरकारी गनट] में विद्यमान द्वारा, राज्य सरकार
- (२) किसी नायब तहसीलदार को तहसीलदार के सभी या कोई अधिकार
- (३) किसी तहसीलदार को सहायक कलक्टर के सभी या कोई अधिकार,
- (४) किसी सहायक कलक्टर को सब डिविजनल अधिकारी या भूलेख अधिकारी या भूप्रबंध अधिकारी या जिलाधीश के सभी अथवा आंशिक अधिकार
- (५) किसी सब डिविजनल अधिकारी को भूलेख अधिकारी या भूप्रबंध अधिकारी या कलक्टर के सभी या आंशिक अधिकार,
- (६) किसी भूलेख अधिकारी या भूप्रबंध अधिकारी को सब डिविजनल अधिकारी या सहायक जिलाधीश या कलक्टर के सभी या कोई अधिकार
- (७) किसी कलक्टर को भूप्रबंध अधिकारी के सभी या कोई अधिकार,
- (८) (विलोपित)
- (९) किसी भूप्रबंध आयुक्त को भूलेख अभ्यक्ष के सभी या कोई अधिकार प्रदान कर सकती है।

(२) उपधारा (१) के अधीन दिये गये अधिकारों का सिद्दी एम क्षेत्रों में और सिद्दी ऐसे विषयों या मामलों या विषयों या मामलों या समूह के सम्बन्ध में प्रयोग किया जायेगा जिनके लिए राज्य सरकार निर्देश करे।

(३) राज्य सरकार व्यक्तियों को उनके नाम से अथवा अधिकारियों को सामान्य रूप से उनके पदों या नाम द्वारा इस धारा के अधीन सशक्त बना सकती है।

यदि किसी तहसील, सब डिविजन जिले, अथवा अन्य किसी क्षेत्र का कोई पदाधिकारी, जिससे हम धारा ८ अन्तर्गत मनोनीत कोई अधिकार सौंप गये हों किसी समान प्रकृति एवं समान श्रेणी के पद पर किसी अन्य तहसील सब डिविजन जिले या क्षेत्र में स्थानान्तरित कर दिया जाता है तो भा यह, चरित कि राज्य सरकार अन्य निर्देश न करे, ऐसे तहसील, सब डिविजन, जिले, अथवा क्षेत्र में इस धारा के अन्तर्गत उन्हीं (पुनर्वत्) अधिकारों से समाविष्ट अधिकारी माना जावेगा।

टिप्पणी—उक्त धारा में इस अधिनियम के अन्तर्गत उन अतिरिक्त अधिकारों का उल्लेख है जो अधिकारी अपने वास्तविक अधिकारों के अलावा प्रयोग में लायेगा। वह अधिकार स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार के होते हैं। इस प्रकार दिये गये नये अधिकारों का प्रयोग अधिकारी स्थानांतरण होने के बाद अपने नये क्षेत्र में भी करेगा जब तक सरकार उन अधिकारों को वापिस न ले ले।

[धारा २७] न्यायालयों एवं अधिकारियों के आत्म जात अधिकार — धारा २५ एवं २६ में निर्दिष्ट अधिकारों के अतिरिक्त—

(क) राजस्व अपील प्राधिकारी को कलक्टर, सब डिविजनल अधिकारी, सहायक कलक्टर एवं तहसीलदार के सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त होंगे।

(ख) कलक्टर को सब डिविजनल अधिकारी सहायक कलक्टर और तहसीलदार के सभी अधिकार प्राप्त होंगे।

(ग) सब डिविजनल अधिकारी को सहायक कलक्टर एवं तहसीलदार के सभी अधिकार प्राप्त होंगे

(घ) सहायक कलक्टर को तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार के सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त होंगे,

(ङ) तहसीलदार को नायब तहसीलदार के सभी अधिकार प्राप्त होंगे, और

(च) भूलेख अधिकारी अथवा भूप्रशाधिकारी को तहसीलदार या नायब तहसीलदार अथवा अध्याय ७ या अध्याय ८ के अधीन नियुक्त किये गये किसी भी अधिकारी के समस्त अधिकार प्राप्त होंगे।

[धारा २८] स्थायी रिक्त स्थानों को अस्थायी काल के लिये अधिकारियों द्वारा समालोचना — कलक्टर अथवा सब डिविजनल अधिकारी अथवा तहसीलदार के पद के स्थायी रूप से रिक्त हो जाने के कारण जब कोई अधिकारी जिले, सब डिविजन

या तद्वसील के जैसी भी अवस्था हो, मुख्य प्रवाधिकारी प्रशासन का अस्थायी रूप से अधिकारी होता है—तब वह राज्य सरकार के आदेशों-तक, '[राज्य]-म-वर्तमान-किसी भी प्रभावी-तक कानून द्वारा या उसके अधीन कलस्टर या मंत्र विभिन्नल अधिकारी या तद्वसीलतार की प्रदत्त सभी अधिकारों एव उस पर आरोपित सभी कर्तव्यों का क्रमगत प्रयोग तथा पालन करेगा।

(धारा २६) अधिनियमों की अस्थायी अनुपस्थिति — कोई अधिकारी जब अपने पद से अस्थायी रूप से अनुपस्थित हो—

(१) अपने हेडक्वार्टर पर कार्यरत अन्य समान श्रेणी वाला अधिकारी या यदि कोई समान श्रेणी वाला अधिकारी न हो, इस प्रकार कार्यरत कोई अन्य ऊंची श्रेणी वाला अधिकारी अधिकांशतः कोड ऐसा उंची श्रेणी वाला अधिकारी न हो कोई अन्य निम्न श्रेणी का इस प्रकार कार्यरत अधिकारी अपने साधारण पद एवं कर्तव्यों को निभाते हुये अनुपस्थित अधिकारी के पद का कार्यभार सम्भालेगा और उस पद पर नियुक्त किसी अन्य अधिकारी द्वारा कार्यभार न ले लेने तक इस पद का कार्याधिपति बना रहेगा और कार्यवाहन का अग्रिम अनुपस्थित अधिकारी के दैनिक कर्तव्यों की पूर्ति करेगा और

(२) यदि इस प्रकार के हेडक्वार्टर पर-कोई-समान-उच्च या निम्न श्रेणी का अधिकारी कार्य न कर रहा हो अथवा स्वयं वह भी गैरहाजिर हो तो मुख्य सचिवालय कमचारी को समय समय पर किसी नियम, मामले या कार्यवाही का स्थगित करने का अधिकारी होगा।

टिप्पणी—इस धारा का अर्थ यह है कि किसी अधिकारी की अनुपस्थिति में, यदि इस कार्यालय में उक्त श्रेणी का कोई अन्य अधिकारी मौजूद न हो तो, उसके ऊपर की श्रेणी का समान नीच की श्रेणी का अधिकारी उक्त कार्य सम्भालेगा। नाम सम्भालने वाला अधिकारी केवल राज का नाम ही लिखेगा और किसी भी तथ्य से सम्बन्धित मामल का सम्बन्धित अधिकारी के लिये छोड़ देगा।

(घ) पटवारी, कानूनगो और निरीक्षक

[धारा ३०] पटवारियों के मन्त्रियों का निर्माण एवं परिवर्तन — राज्य सरकार की पत्र-व्यवस्था से भू-लेख अथवा, समय समय पर प्रत्येक जिले के गांव को पटवारों द्वारा सम्मानित कर सनना है और ऐसे मन्त्रियों का संख्या एवं सीमा में परिवर्तन कर सकता है।

[धारा ३१] पटवारियों की नियुक्ति — मन्त्रियनियम के अधीन बनाय गये नियमों के मातहत अध्याय ७ के अंतर्गत वर्णित पत्र-व्यवस्था एवं लक्ष्य समुदाय तैयार करने के लिये एवं उनमें सुधार करने के लिये अपना नियुक्ति के संकेत के आसामियों एवं

भूमिधारियों से यथासा लुगाएँ, राजस्व और अन्य मतलबों के समूह के लिये राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट किन्हीं अन्य कार्यों के लिये कलकत्ता प्रत्येक क्षेत्र के लिये एक पटवारी नियुक्त करेगा।

[धारा ३२] भूलेख निरीक्षण मकानों का निर्माण एवं परिवर्तन — भूलेख अधिनियम राज्य सरकार की पूर्ण स्वीकृति से, प्रत्येक जिले के पटवारी-ऑफिसों को भूलेख-निरीक्षक क्षेत्र के रूप में व्यवस्थित कर सक्ता है।

[धारा ३३] गिरदारर, कानूनगो या भूलेख निरीक्षक की नियुक्ति — कलकत्ता प्रत्येक भूलेख निरीक्षक क्षेत्र में इस अधिनियम के अधीन अध्याय ७ के अन्तर्गत धार्मिक पत्रिकाओं एवं लेख समूह के निरीक्षण, प्रकाश एवं सुधार के लिये एक गिरदारर या कानूनगो या भूलेख निरीक्षक की नियुक्ति करेगा।

[धारा ३४] सदर कानूनगो — इस अधिनियम के अन्तर्गत निर्मित निषेध के अधीन भूलेखाध्यक्ष प्रत्येक जिले में गिरदारर, कानूनगो या भूलेख निरीक्षण र कार्य के निरीक्षण हेतु और राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट किन्हीं अन्य कार्यों के सम्पादन हेतु एक या एक से अधिक सदर कानूनगो की नियुक्ति करेगा।

[धारा ३५] पटवारी एवं कानूनगो की योग्यताएँ आदि — पटवारी गिरदारर कानूनगो अथवा भूलेख निरीक्षक और सदर कानूनगो की योग्यताओं उनकी नौकरी की शर्तों एवं उनके कर्तव्यों का नियमन इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा निमित्त नियमों के अनुसार होगा।

[धारा ३६] भूलेख तैयार करने के लिये आवश्यक सूचना देने का उत्तरदायित्व — वर्तमान में प्रभावशील किसी विधान द्वारा या ऐसे विधानाधीन निमित्त किसी नियम द्वारा किसी पटवारी अथवा गिरदारर कानूनगो या भूलेख निरीक्षक अथवा सदर कानूनगो द्वारा किसी व्यक्ति का हित, अधिकार या उत्तरदायित्व सार्वकारी पत्रिका में दर्ज किया जाना आवश्यक हो तो उसके चाहने पर पत्रिका के ठीक समूह के लिये आवश्यक सभी सूचनाओं को देने के लिये ऐसा व्यक्ति रख बाध्य होगा।

टिप्पणी — इस धारा के अनुसार जो व्यक्ति अपनी भूमि में सम्बन्ध में कोई भी अप्रत्यक्ष अधिकार धर्म या वाणिज्य रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहेगा तो यह उसका स्वयं का कर्तव्य होगा कि वह अपना व पानिक जिम्मेदार सम्बन्धित अधिकारी को उनकी सूचना दे।

[धारा ३७] [विलोपित]

[धारा ३८] [विलोपित]

[धारा ३९] [विलोपित]

[धारा ४०] (निलोपित)

[धारा ४० का] लम्बगटारों की सेवाओं की ममाप्ति — (१) राजस्थान जनरल क्लानेन एक्ट, १९५५ राजस्थान एक्ट ८, सन् १९५५), या तत्समय प्रभावी लॉ ज़िमी भी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अन्तर्गत नियुक्त या नियुक्त किये हुए समझे गये समस्त लम्बगटार, राजस्थान लैंड रेवेन्यू (सशो जन) अधिनियम १९६३ के प्रारम्भ होने की तारीख से उस गांव या गांवों के उस ममुनाय, जिसने या जिनके लिए वे नियुक्त किये गये वे के लम्बगटार नहीं रहेंगे और इस अधिनियम द्वारा बनने वाले प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग एवं उनको सौंप गये कार्य एवं कर्तव्यों को निभाना न करेंगे तथा राजस्व या लगान या राज्य के किसी भी अन्य मतालये की जम्मी करने का कार्य न करे कि राज्य सरकार अथवा निर्देश न दे दे, इसके क पटवारी द्वारा सम्पन्न किया जायगा ।'

[धारा ४१] ग्राम सेनक — प्रत्येक गांव में या गांवों के समुदाय में निम्नांकित में से इतने एवं ऐसे कमचारी जैसे क्लर्क, राज्य सरकार के आदेशाधीन निर्देश करे, नियुक्त एवं व्यवस्थित किये जायेंगे अथवा—

- (१) एक गांव का प्रहरी या चौकीदार
- (२) एक गांव मामी, और
- (३) ऐसे अन्य ग्राम सेवक जिनके विषय में समय समय पर राज्य सरकार [सरकारी गजट] में विज्ञप्ति प्रकाशित करे ।

[धारा ४२] रिक्त स्थान — पटवारी जिसकी मर्हिल में ग्राम या ग्रामों का समूह हो पंद्रह दिन की अवधि के भीतर किसी ग्राम सेवक के नियुक्त त्यागपत्र दान या पत्र पत्र किये जाने अथवा अन्य किम रीति के उसके स्थान के जाली दान की मूचना तहमीलदार को देगा । तत्परचात तहमीलदार नियमानुसार कार्यवाही करेगा ।

[धारा ४३] ग्राम सेनक पत्रिका — (१) प्रत्येक तहमीलदार अपनी तहमील के प्रत्येक गांव या गांवों के समूह के लिये क्लर्क द्वारा नियुक्त अथवा के भीतर प्राप्त मगानम माहौल के आधार पर निर्धारित निरर्णा महिन मभी ग्राम सेनकों की एक पत्रिका तैयार करेगा ।

(२) उपधारा (१) के अन्तर्गत बनाया गया प्रत्येक रजिस्टर स्थायी रेकर्ड के अन्तर्गत अप-टुडट रमा एवं व्यवस्थित किया जायगा और समय समय पर ग्राम सेवकों की सम्पत्ति में उनके व्यक्तियों में तथा अन्य विवरणों में किये जाने वाले सुधार जिनमें टोड दग से अंकित किये जायेंगे तथा कानूनी रूप में प्रमाणित किये जायेंगे ।

[धारा ४४] ग्राम सेनकों का पारिश्रमिक — धारा ४१ के अधीन नियुक्त

एव व्यवस्थित किये जाने वाले ग्राम सेवक का अधिनियम व अधीन निमित्त नियमों द्वारा निर्धारित परिमाण में तथा नियत तरीके से निरिक्त पारिश्रमिक पाने के दस्तदार होगा।

[धारा ४५] पारिश्रमिक, पूर्वी एव हस्ता तरण से अप्रमाणित रहेगा —
जिसी ग्राम सेवक का पारिश्रमिक चाहे वह भूमि व रूप में हो या भूमि से समाविष्ट हित के रूप में हो या किसी अन्य रूप में हो हस्ता तरण या राजस्थान वास्तव्य अधिनियम (मर्यादा ३, स. १९२५) द्वारा प्रशस्ति सोमा अतिरिक्त किसी भी अन्य भार के योग्य नहीं होगा और किसी भी याचालय के लिये यह, बंध नहीं होगा कि यह एव पारिश्रमिक या उसके किसी अंश को गुरु करे या उचें।

—टिप्पणी—उक्त धारा में ग्राम सेवक का संरक्षण उन्नत किया गया है। पारिश्रमिक पर कोई याचालय किसी भी प्रकार की डिमी नहीं जा सकता है। यद्यपि वह कुछ प्रश्न और सफ़ट प्रस्त है तो भी ग्रामसेवक के रूप में धरने वर्तव्य का पूरा कर जानी सामाजिक प्रतिष्ठा बनाये रख सकता है।

[धारा ४६] ग्रामसेवकों के कर्तव्य — (१) इस अधिनियम के अधीन नियुक्त प्रत्येक ग्रामसेवक, ग्राम चौकीदार के अतिरिक्त, इस अधिनियम के नियमों द्वारा आरोपित कर्तव्यों का अनुपालन करेगा।

(२) इस अधिनियम के अधीन नियुक्त प्रत्येक ग्राम चौकीदार इस अधिनियम के अंतर्गत निर्मित नियमों द्वारा दिये गये एव आरोपित अथवा पुलिस सुपरिटेंडण्ट द्वारा आयोजित अधिकारों एव कर्तव्यों का क्रमशः पालन तथा प्रयोग करेगा।

[धारा ४७] नियुक्ति का करन की प्रणाली — जब जिलाधीश या निर्देश करे कि कोई ग्राम सेवक किसी गांव या गावों के समुदाय के लिये नियुक्त किया जायगा अथवा जब कभी किसी ग्राम सेवक का पद रिक्त हो जाय तब निर्देश के अथवा ऐसे पदा के रिक्त होने के पश्चात् ६ माह की अवधि के भीतर तहसीलदार उस पर नियुक्ति करेगा।

[धारा ४८] नियुक्ति के लिए अयोग्यताएँ — ऐसा कोई व्यक्ति जो कि —

(क) वयस्क न हो या

(ख) अपने पद से सम्बद्ध कार्य करने के लिये आवश्यक मानसिक अथवा शारीरिक शक्ति से युक्त न हो या

(ग) नस जेज में निवास न करता हो जिसके लिये वह नियुक्त किया जा रहा हो, अथवा

(घ) किसी को नदारी अमानत द्वारा नैतिक पतन युक्त दुष्चरण के अपराध में अस्वाधी करार द दिया गया हो।

टिप्पणी—इस धारा के अनुसार ग्राम सेवाक वृत्त के लिए केवल वयस्क व्यक्तियों की ही नियुक्ति होगी। भारतीय वयस्क अधिनियम १८७१ की धारा ३ के अनुसार वयस्क होने के लिए १८ वर्ष की आयु निर्धारित की गई। वयस्कता के मतानुसार ग्राम योग्यताएँ भी ग्रामसेवक के पद पर नियुक्त होने के लिए आवश्यक हैं जैसे शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य उस ग्राम का परिपालन, सबसे आवश्यक नैतिक चरित्र, आदि हैं। किसी नैतिक अपराध में दण्डित व्यक्ति को भी इस पद के लिए प्रयोग्य समझा जावेगा।

(धारा ४६) लम्बरदारों तथा ग्राम सेवकों को दण्डित करना, मोचनिल करना और उनको नौकरी से हटाना — (१) अपने कर्तव्यों को ठीक ढंग से न निभाने के कारण दोषी ग्राम सेवक, तहसीलदार की आज्ञानुसार अधिक से अधिक तीन रुपये जुमाने के तौर पर दण्डित किया जाएगा।

(२) इस अधिनियम के अन्तर्गत निमित्त किहीं नियमों के अधीन ग्रामसेवक या लम्बरदार यदि—

(१) इस तरह काम करने के लिये तैयार न हो अथवा काम करने के लिये शारीरिक रूप से योग्य न हो या

(२) किसी बड़ दुराचरण अथवा कर्तव्यों की अधिरल एवं आचर्यमयी लापरवाही का दोषी हो, या

(३) अन्य किसी प्रणाली से अपने पद योग्य न रहे तो अपने आचरण का प्रमाण दिये जाने या नष्ट मुनबाई का मौका दिये जाने बाद मोचनिल किया जायेगा, पदच्युत किया जायेगा या पद से हटा दिया जायेगा।

[धारा ५०] ग्राम प्रहरी को पुलिस अधिकारियों के अन्तर्गत रखने का अधिकार — सरकार यह निश्चय दे सकती है कि किसी ग्रामसेवक को (धारा ४० और ४६ के अधीन) नौकरी देने या सजा देने के अधिकार किसी विशेष क्षेत्र में समस्त अथवा किसी एक ग्राम प्रहरी के सम्बन्ध में किसी पुलिस सुपरिटेण्डेंट या पुलिस इंसपेक्टर द्वारा व्यवहार में लाये जाय, शर्त कि इस सम्बन्ध में एक माह की अवधि के भीतर निला मोनस्ट्रट की पुनरावेदन पेश किया जाय।

अध्याय ४

राजस्व न्यायालय तथा अधिकारियों की कार्य प्रणाली

(धारा ५१) न्यायालय के बैठने अथवा जाने पड़तान करने का स्थान —

(१) अध्याय ३ के अधीन नियुक्त प्रत्येक अधिकारी धारा २०३ में अन्तर्गुह्य प्रायधानों के अधीन रहत हुए अपने कार्यक्षेत्र की सीमा के अन्दर किसी भी स्थान पर अपनी अदालत की बैठक रख सकता है और पूछताछ कर सकता है।

(२) रकाब दिये जाने योग्य कारणों के अलावा कोई भी ऐसा अधिकारी ऐसी सीमा के बाहर किसी भी स्थान पर न कोई मामला सुनेगा और न वचन पूछताछ करेगा।

(धारा-५२) भूमि पर प्रवेश करने तथा पैमाना का अधिकार — जब कभी मौखिक या लिखित रूप से अग्रहण दिये जाय तो सभी राजस्व तथा ग्राम अधिकारी

और उनसे सेवक एवं कर्मचारी किसी भी भूमि पर प्रवेश कर सकते तथा वहाँ पैमाइश पर सफेगी या सीमा के निशान पता सफेगी तथा इस अधिनियम या वर्तमान में प्रमाण शील अन्य कानून के अधीन प्रावधानित कार्य कृत्यां में सम्बन्धित अन्य कोई कार्य पर सफेगी।

परन्तु कोई भी व्यक्ति किसी घर में या रिहायशी घर में जुड़ दूये किसी उद्यान या बाड़े पाले चबूतरे पर तब तक प्रवेश नहीं करेगा जब तक कि उस स्थान पर कांजिस से कम से कम २४ घण्टे की सूचना देकर अनुमति न ले ली गई हो और इस प्रकार के प्रवेश के समय मकान में रहने वालों की धार्मिक व सामाजिक भावनाओं का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिये।

—(धारा ५३) बोर्ड इत्यादि के मामलों को—स्थानान्तरित करने सम्बन्धी सरकारी अधिकार —राज सरकार या भूलेखाध्यक्ष भू प्रयोजन से "असलमन्" किसी भी गैर अदालती मामले या मामलों के समूह को और बोर्ड या भूप्रयोजन आयुक्त या भूलेखाध्यक्ष किसी अदालती या भूप्रयोजन सम्बन्धी मामले या ऐसे मामलों के समूह को किसी एक मातहत राजस्व अदालत या राजस्व अधिकारी से किसी अन्य अदालत या अधिकारी की जो उक्त मामले में कार्यवाही करने के लिए उत्तम हो, स्थानान्तरित कर सकता है।

—[धारा ५४] अधीनस्तो से अथवा अधीनस्तो के मामले स्थानान्तरित करने के अधिकार —सब डिविजनल अधिकारी, भूलेखा अधिकारी अथवा भूप्रयोजन अधिकारी कलक्टर, तहसीलदार इस अधिनियम के अंतर्गत खड़े होने वाले अथवा अथर्व रूप में पृष्ठताब्द या निर्णय के लिए कोई मामला या मामले अपनी फाइल में से किसी अधीनस्त राजस्व अधिकारी के पास भेज सकता है जो कि उक्त मामले या मामलों की उच्चतम के लिये योग्य हो अथवा किसी ऐसे राजस्व अधिकारी से किसी मामले या मामलों का वापिस ले ले और ऐसे मामले या मामलों का निपटारा खुद करे अथवा निपटारे हेतु उह किसी ऐसे अन्य राजस्व अधिकारी के पास भेज दे जिसको उन्हें सुनने एवं निपटाने का अधिकार प्राप्त हो।

परन्तु किसी मामले में पृष्ठताब्द के बाद किसी राजस्व अधिकारी द्वारा अन्तिम आदेश के लिए कोई रिपोर्ट पेश की जाती है तो बाद वाला अधिकारी अन्तिम आदेश जारी करने के पहले फरीफेन की सुनवाई का एक मौका देगा।

[धारा ५५] मामलों का एकीकरण —निर्णय हेतु चयन मुख्यरूप से एक ही प्रश्न को अथवा एक ही आधार में लेकर एक से अधिक मामले किसी एक या अधिक राजस्व न्यायालयों में विचाराधीन होंगे तो किसी भी फरीफेन द्वारा उक्त अदालत को जिसके अधीनस्त अन्य अदालत या अदालतें हों इस विषय का आवेदनपत्र देने पर उक्त मध्य मामलों का एकीकरण एक ही अदालत में कर दिया जायेगा और वे सब मामले एक ही फैसले द्वारा तय कर दिये जायेंगे। ऐसे मामले उच्चतर न्यायालयों में प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

[धारा ५६] आवेदन पत्र उपस्थिति इत्यादि कौन दे ? — 'वर्तमान' में प्रभावशाली किसी विधि अधीन अथवा इस अधिनियम के अन्तर्गत अथवा इससे अधीन बनाये गये नियमों के अन्तर्गत किसी राजस्व न्यायालय या राजस्व अधिकारी के समक्ष किये जाने वाले कार्य, दिये जाने वाले आवेदनपत्र एवं उपस्थितियाँ प्रस्तुत की जा सकती हैं—

(क) फरीकेन द्वारा व्यक्तिगत रूप से, या

(ख) उनके स्वीकृत प्रतिनिधियों द्वारा अथवा

(ग) विधि-व्यवसायियों द्वारा जो ऐसी अदालत में अधिकारी के समक्ष बका लत करने के लिए समर्थ हों तथा फरीकेन द्वारा विधिवत स्वीकृत हों—

परन्तु राजस्व अदालत या अधिकारी द्वारा किसी फरीक की उसके द्वारा स्वीकृति अभिमर्ता या वकील की नियुक्ति किये जाने के बावजूद भी व्यक्तिगत उपस्थित किसी कार्यवाही में याद्वित हो सकती है।

[धारा ५६का] आवेदन पत्रों, अपीलों आदि का प्रस्तुत किया जाना—

(१) समस्त आवेदन-पत्र, अपीलें तथा कार्यवाहियाँ, प्रतिदूल प्रभाव रखने वाले प्रावधान के अन्तर्गत, ऐसे न्यायालय अधिकारी अथवा प्राधिकारी की निम्नलिखित या जिसको ऐसे आवेदन-पत्र, अपीलें या कार्यवाहियाँ इस अधिनियम या तदन्तर्गत बनाये गये नियमों अथवा तत्समय प्रभावी किसी भी अन्य विधि या ऐसी-विधि के अधीन बनाये गये नियमों के किसी भी प्रावधान के अन्तर्गत पेश होती हैं, प्रस्तुत की जायगी—

परन्तु यदि ऐसे किसी भी प्रावधान के अधीन कोई भी आवेदन-पत्र, अपील या कार्यवाही राजस्व अपील प्राधिकारी को पेश होती है तो ऐसा आवेदन-पत्र, अपील या कार्यवाही उस निम्नलिखित कि ऐसे आवेदन पत्र, अपील या कार्यवाही के लिये पूर्णतः या अंशतः वाद हेतु उत्पन्न होता है—के क्लर्क को प्रस्तुत की जा सकेगी या के द्वारा प्राप्त की जा सकेगी।

(२) उप धारा (१) के परंतुक के अधीन आवेदन पत्र, अपील या कार्यवाही प्राप्त होने पर क्लर्क यह देखने के लिए उसकी जाँच करेगा कि क्या उम पर यथोचित न्यायालय शुल्क दिया जा चुका है, क्या यह उमको उस समयवधि, यदि कोई हो क अन्दर अन्दर प्रस्तुत की गई है जो ऐसे प्रस्तुतीकरण के लिये निर्धारित की गई है, क्या निर्णयों, द्विवियों और आवाजों की समस्त आवश्यक प्रमाणोक्त प्रतियाँ उसके साथ संलग्न हैं तथा क्या धारा ५६ के अधीन ऐसा करने के लिए सत्तम व्यक्त द्वारा उक्त पत्र में प्रस्तुत की गई है और तत्परवान यदि आवेदन पत्र, अपील या कार्यवाही नियमा नुसार पाई जाय या क्लर्क द्वारा देखे गये दोष यदि कोई हो, नही कहीं सम्भव हों, दूर पर दिन जान क परवान, क्लर्क आवेदन पत्र अपील या कार्यवाही को सामन क रखाई सहित उसको सुनने तथा निपटान क लिए तत्समय सक्षम राजस्व अदाल प्राधिकारी को भेजेगा।

[धारा ५७] राजस्व न्यायालयों अथवा अधिकारियों की शक्तियों की उपस्थिति और प्रपत्रों को प्रस्तुत करने तथा साची ग्रहरा करने के सम्बन्ध में शक्तियाँ — (१) तात्वा दीगानी—(केन्द्रीय एक्ट संख्या ५ सन १९०८) की धारा

१३२ एवं १३३ तथा इस अधिनियम के अन्तर्गत निर्मित नियमों के प्रावधानों के अधीन रहते हुए प्रत्येक राजस्व-यायालय या अधिकारी को किसी व्यक्ति को बुलाने का अधिकार होगा जिसकी उपस्थिति या तो किसी मामले में फरीश व रूप में जांच करने के लिए या गवाही के रूप में या किसी मामले या तथ्य पड़ताल के सम्बन्ध में ता कि उस अधिनियम के अन्तर्गत या वर्तमान में प्रभावशील किसी अथवा धारा के अधीन पैदा हुई हो, किसी प्रपत्र के प्रस्तुत किये जाने के लिए आवश्यक समझी जायेगी।

(२) प्रपत्र प्रस्तुत करने के हेतु निम्नलिखित गया सम्मन किसी गाम निर्दिष्ट प्रपत्र को प्रस्तुत करने के लिये हो सक्ता है तथा बुलाय गये व्यक्ति के अधिकार में मौजूद किसी प्रकार के सभी प्रपत्रों को प्रस्तुत करने के लिये भी हो सक्ता है।

(३) इस प्रकार बुलाये जाने वाले सम्मन व्यक्ति व्यक्तिगत तौर पर या अभिर्वात के द्वारा, पैसा भी सम्मन उन अधिकारी या यायालय निर्देश कर उपस्थित होने के लिए और ऐसे विषय में जिसके लिए उनकी जांच की जा रही हो अथवा निम्नलिखित सम्बन्ध में वे बयान दे रहे हों सत्य भाषण के लिये तथा चाहे गये दस्तावेजों पर अथवा पदार्थों को प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होंगे।

(४) यदि कोई व्यक्ति जिस पर कि सम्मन तामील हो चुका है सम्मन की आज्ञा पालन करने में असफल रहता है, तो सम्मन जारी करने वाला अधिकारी या यायालय ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए जमानती वारंट जारी कर सकता है।

(५) कोई भी राजस्व अधिकारी या यायालय उपस्थित हुए किसी भी व्यक्ति से साक्षी देने का आग्रह कर सकता है तथा उस समय उसके अधिकार या कब्जे में होने वाले किसी दस्तावेज को पेश करने की हिदायत कर सकता है।

[धारा ५८] सम्मन हस्त-लिखित और मुद्रांकित होंगे — प्रत्येक सम्मन की लिखित में दो परतें आवश्यक हैं तथा उसे निम्नलिखित वाले अधिकारी अथवा किसी ऐसे व्यक्ति के जिसे वह इस विषय में प्राधिकृत कर उस पर हस्ताक्षर अनिवार्य है और मुद्रा भी होगी तथा उसमें किसी व्यक्ति के उपस्थित होने का स्थान व समय भी प्रकट होगा और वह भी लिखा होगा कि वह साक्षी देने के लिये बुलाया जा रहा है अथवा कोई प्रपत्र प्रस्तुत करने के लिये।

[धारा ५९] सम्मनों की तामील — प्रत्येक सम्मन की तामील कराई जायेगी

(१) एक प्रतिलिपि भेजकर या देकर—

(क) बुलाये गये व्यक्ति को अथवा

(ख) उसके माय प्रतिनिधि को या वकील को या

(ग) सामान्यतः उनके साथ रहने वाले उसके कुटुम्ब के किसी व्यक्ति सदस्य, या

(२) यदि उपर्युक्त व्यक्तियों में से कोई भी न मिले या अस्वीकृत कर दे तो उसके सामान्यतः या अन्तिम बार के मकान पर सरलता से दिखाई देने वाले स्थान पर सम्मन की एक प्रतिलिपि चिपका कर, या

(३) ऐसा व्यक्ति यदि किसी अन्य जिले में रहता हो तो उस जिले के फलकटर को ऐसा सम्मन सख्त (१) या सख्त (३) के अनुसार तामील कराये जाने के लिये डाक द्वारा भेजकर, या

(२) कारण रकूँ करने के पञ्चान्न रात्रय न्यायालय या अधिकारी यदि कोई निर्देश दे तो मर्दान्क रत व्यक्ति को ऐसे सम्मान की एक प्रति तामील के किसी अन्य तराफ के धनाय या उसके अलावा, रजिस्टर्ड दान द्वारा भेजकर ।

— [धारा ६०] नोटिस को तामील करने की प्रणाली — सम्बन्धित व्यक्ति को सम्मान की एक प्रति सुपुर्द कर या लेकर इस अधिनियम के अन्तर्गत-प्रत्येक सूचनाओं को तामील या भारतीय डाक अधिनियम १८६५ (केंद्रीय एक्ट संख्या ६ सन् १८६५) के अधीन एक रजिस्टर्ड लिफाफे में दान द्वारा भेजकर कराई जायगी अथवा यदि उपरोक्त तरीके से तामील नहीं कराई जा सकती तो अन्तिम रूप से ज्ञात उसके निवासस्थान पर या उस गांव में जिसमें नोटिस सम्बन्धित तामील हो, आम लोगों के उठने बैठने की जगह पर, उस सम्मान की एक प्रतिलिपि बिपना कर तामील की जायगी ।

[धारा ६१] घोषणा प्रकाशित करने की प्रणाली — इस अधिनियम के अन्तर्गत यदि कोई घोषणा की जायगी तो उसे करने वाले अधिकारी के कार्यालय में उस तहमील के कार्यालय में जिसमें घोषणा से सम्बन्धित जमीन स्थित हो और सम्बन्धित जमान पर या उसके समीप धान लोगों के उठने बैठने के किसी स्थान पर उस घोषणा की प्रतियां बिपनाई जायेंगी और यदि घोषणा जागी करने वाला अधिकारी निर्देश कर तो सम्बन्धित भूमि पर या उसके आस पास कोई विट्ठा कर भी घोषणा कराई जा सकती ।

[धारा ६२] कोई नृत्तिग घोषणा या सूचना पर यमान्य नहीं होंगे — कोई भी सूचनापत्र या घोषणा उसमें लिख किसी व्यक्ति के नाम गिरण या पत्र अत्र प्रामाणिक किसी भूमि के गिरण मरुति रह जाने के कारण अमान्य नरक नहीं होगी परन्तु कि इस प्रकार की नृत्ति मरुति वास्तविक अथवा न होना हो ।

[धारा ६३] पक्षकार की अनुपस्थिति में सुनवाई करना — (१) यदि राक्षस न्यायालय या अधिकारी के समान किसी मामले में कार्यवाही में पक्षी की तारीख पर अथवा पक्षी पक्षी किसी तारीख या किहीं तारीखों पर दिन पर सुनवाई की नियम किया गया हो कोई पक्षकार उपस्थित न हो तो मामला या कार्यवाही उसकी अनुपस्थिति में सुनी प्र निर्णय की जा सकती है अथवा अनुपस्थित के अन्तर्गत सूचना रजिस्ट्री में सकती है ।

(२) कोई रात्रय न्यायालय या अधिकारी किसी मामले में कार्यवाही की सुनवाई की तारीख पर यह न्याय किसी पार्टी पर उसके लिफाफे पार्टी द्वारा सम्मान की ताराख आदि-कृतिय अनिवार्य मरुति केंद्रीय-दामिन नहीं कराया जाना सम्मान या सूचनापत्र तामील नहीं दिये जा सकूँ हों वह ऐसी-प्रक्रिया सम्बन्धी शुल्क नाना न कराने-य अत्रात में मानने या कार्यवाही को निराल कर सकता है ।

[धारा ६४] सुनवाई को प्रकाशित करना — (१) कोई भी अधिकारी या रात्रय न्यायालय समय-पर किसी भी मामले या कार्यवाही की सुनवाई की स्थिति पर सकता है ।

(२) किसी मामले या कार्यवाही की ऐसी स्थिति का जो सुनवाई के समय और स्थान की सूचना स्थान के समय मौजूद पत्रकार या साक्षिणों को दी जायेगी।

[धारा ६५] धारा ६३ के अन्तर्गत निम्नलिखित गये आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं सुनी जायेगी — (१) किसी राजस्व-याचाल या अधिकारी द्वारा याच्य पर निर्णयित मामले या कार्यवाही के अतिरिक्त, धारा ६३ के अन्तर्गत दिये गये किसी भी आदेश के विरुद्ध कोई भी अपील नहीं होगी।

(२) ऐसा कोई भी पक्षकार जिसने विरुद्ध धारा ६३ के अन्तर्गत आदेश दिया गया हो, ऐसे आदेश के बाद ३० दिन की अवधि के भीतर, जो प्रमाण दत्त हुए कि वह सुनवाई के दिन पर्याप्त कारणों पर उचित हानि में अथवा बिलाक पार्टी पर सम्मन या नोटिस तत्पर करने के लिये आवश्यक शुल्क जमा करने में विफल रहा, उक्त आदेश को समाप्त करने के लिये एक आदेश पत्र दे सकता है और राजस्व अधिकारी या बिलाक पार्टी को नोटिस देने तथा आवश्यक समझी जाने योग्य जांच करने के परवाना निकालने गये आदेश को समाप्त कर सकता है।

[धारा ६६] व्यय दिलाने और वितरण करने का अधिकार — (१) किसी मामले या कार्यवाही में हुए व्यय को कोई भी राजस्व अधिकारी या अधिकारी किसी ऐसी मोमा तब और किसी ऐसी रीत से दे और वाट सकता है जो कि उसके विचार में समुचित हो।

(२) राज्य सरकार के अतिरिक्त किसी अन्य पक्षकार को सूचना दिलाने या उधार (१) अन्तर्गत जारी किया गया आदेश में प्रचार पालन योग्य होगा मानों वह किसी राजस्व-याचालय द्वारा दी गई रूपया की डिक्की हो।

[धारा ६७] त्रुटि अथवा भूल का संशोधन — कोई भी राजस्व-याचालय या अधिकारी जिसने एक अधिनियम के अधीन कोई आज्ञा किसी कार्यवाही में दी अपनी इच्छा से अथवा किसी पक्ष के प्रावनापत्र प्रस्तुत करने पर आग्रहक परीक्षण को मर म मूला देने के उद्देश्य से अपने आदेश की किसी की कोई भूल अथवा जो मामले के किसी भी महत्वपूर्ण अंश को प्रभावित किये बिना, सुधार सकता है।

— [धारा ६८] पक्ष निर्णय के लिये मामला — जने का अधिकार — राजस्व मण्डल, राजस्व अधिकारी प्राधिकारी भूप्राप्त आयुक्त अतिरिक्त भूप्राप्त आयुक्त भूलेखी ध्यान अतिरिक्त या सहायक भूलेखीय अतिरिक्त कर संपादक सत्र विनिर्णय आफिपर मायक कर संपादक, भूलेखीय अधिकारी, भूप्राप्त अधिकारी, तहसीलदार और अतिरिक्त तहसीलदार पक्षकार की स्वीकृति से अपने समक्ष रखे किसी भी विवाद को अपने आदेश द्वारा पक्ष निर्णय के लिये भेज सकते हैं।

[धारा ६९] पक्ष निर्णय के लिये प्रेषित मामलों की कार्यवाही — धारा ६८ के अधीन पक्ष निर्णय के लिए प्रेषित सभी मामलों में पक्ष निर्णय अधिनियम (केन्द्रीय अधिनियम संख्या १० मंत्र १९४१) के ऐसे सभी प्रावधान लागू होंगे जो इस अधिनियम के सम्मिलित किसी भी बात से असंगत न हों।

[प्राग ७०] पचनिर्णय को रद्द करने के लिये आवेदन पत्र तीस दिन की अवधि के भीतर (यदि निर्णय ४ दिन से) पच निर्णय को रद्द करने के लिये प्रत्येक आवेदनपत्र प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

नियम १०० — यदि किसी पञ्चकार का विषय पचायत का पञ्चता मजूर न जाता व ठहरे प्राप्त सूचना के दिन से २० दिनों के भीतर ऐसे निर्णय को रद्द करने के लिये आवेदन पत्र मर्जेगे।

[प्राग ७१] पच निर्णय के अनुमूल निर्णय देना — यदि पच-निर्णय के लिये मामला प्रेषित करने वाला राजस्व अधिकारी या न्यायालय पच-निर्णय को अवधायक निर्णय हेतु प्रेषित किसी भी प्रिय पर द्वितीय बार विचार करने के लिये लौटाने का पर्याप्त कारण अनुभव नहीं करे और पच निर्णय को रद्द करने के लिये कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत न किया गया हो कठवा ऐसा आदेश पत्र पर दृष्ट दया गया हो ऐसा न्यायालय या अधिकारी विचार का फैसला उस पच निर्णय के अनुसार कर देगा और यदि पचनिर्णय किसी विशेष मामले के रूप में पञ्च किया गया हो तो ऐसे मामले में उसकी अवधायक अपनी सम्मति के अनुसार ऐसा निर्णय करेगा।

[प्राग ७२] टीपानी अदालत में पुनरावेदन अथवा रात्र दायर करने पर धन्य — जब तक कि वह निर्णय पचनिर्णय के अनुसार न हो या उसका उल्लंघन करना हो या तब तक जब मामले के अध्यापक कानूनी रूप में पचनिर्णय वैध नहीं है ऐसा निर्णय तत्काल प्रभावित किया जायेगा और उस सम्बन्ध में कोई अपील नहीं होगी।

एक कोई भी व्यक्ति किसी भी शिवानी अदालत में पच निर्णय को रद्द कराने के निमित्त से या ऐसा पच निर्णय देने के कारण पचों के विरुद्ध कोई भी रात्र दायर नहीं कर सकेगा।

[प्राग ७३] अग्रिम सम्पत्ति का अधिस्तर उपपन्न — छात्रा देने वाला न्यायालय या अधिकारी यदि अचल सम्पत्ति र करने के समस्त काल में मामला निर्णय हो तो उस आदेश के अनुसार पचिगोप या उस ही अन्य कार्य के सिलसिल में उस अधिस्तर पर प्रणालिगत प्रयुक्त करते हुए जो शिवानी अदालत अपनी द्वितीयों के इतराव में विधिवत प्रयोग में लानी है अधिस्तर दिलाया सक्ता है।

अध्याय ५

पुनरावेदन, अभिदेश, निगरानी तथा नजदगानी

[प्राग ७४] इस अधिनियम द्वारा स्वीकृत अपान — इस अधिनियम में प्रावधानित प्रणाली के अतिरिक्त, राजस्व न्यायालय अथवा अधिकारी द्वारा प्राप्त किसी आदेश के विरुद्ध कोई भी पुनरावेदन प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा चाहे वर्तमान में काट भा कानून पक्ष दक्षी हो।

[प्राग ७५] प्रथम पुनरावेदन — सिवाय इसके कि इस अधिनियम में अन्यथा प्रावहित किया जाय, प्रथम पुनरावेदन प्रस्तुत किया जायेगा।

- [(क) सहगीलदार द्वारा दी गई मूल आज्ञा से, जो भूप्रबंध या भूलेख के मामलों से सम्बंधित नहीं हो, क्लर्क को
 (ख) "अभिस्टेट क्लर्क" या मध्य विधिजनल आफिसर या क्लर्क द्वारा दी गई मूल आज्ञा से जो भूप्रबंध से सम्बंधित नहीं हो, राजस्व अपील प्राधिकारी को ।

[अथ विधिजनल कमिशनर के पद समाप्त हो जाने के कारण इस धारा में परिवर्तन किया जाएगा]

- (ग) उसमें अधीनस्थ राजस्व यायालय या अधिकारी की मूल आज्ञा के विरुद्ध भूप्रबंध अधिकार को ।
 (घ) उसके अधीनस्थ राजस्व यायालय या अधिकारी की मूल आज्ञा के विरुद्ध भूलेखाधिकारी को ।
 (ङ) भूप्रबंधायुक्त को भूप्रबंध के मामलों में क्लर्क या भूप्रबंध अधिकारी द्वारा दी गई मूल आज्ञा से विरुद्ध ।
 (च) भूलेख संप्रदाय सम्बंध में भूलेख अधिकारी द्वारा दी गई मूल आज्ञा के विरुद्ध भूलेख अधिकारी को और
 (छ) बोर्ड रो रजिस्ट्रार अपील प्राधिकारी भूप्रबंध आयुक्त या भूलेखाधिकारी की मूल आज्ञा के विरुद्ध ।

(धारा ७६) द्वितीय पुनरावेदन — पुनरावेदन में दी गई (आज्ञा) के विरुद्ध पुनरावेदन किया जाये ।—

- (क) भूप्रबंध या भूलेख से, असम्बद्ध मामला में क्लर्क द्वारा पास किये गये मामलों के विरुद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी को या
 (ख) भूप्रबंध अधिकारी या धारा १८१ के अधीन काम करते हुए क्लर्क द्वारा दी गई आज्ञा के विरुद्ध भूप्रबंध आयुक्त को, या
 (ग) भूलेखाधिकारी द्वारा दी गई आज्ञा के विरुद्ध भूलेखाधिकारी को, या
 (घ) राजस्व अपील अधिकारी या भूप्रबंधायुक्त द्वारा दी गई आज्ञा के विरुद्ध बोर्ड को ।

(२) [विलोपित—]

धारा ७७] कुछ मामलों में पुनरावेदन में निषेध —

- (क) भारतीय मियाद विधि १९०८ (क द्वितीय अधिनियम सरया ६ सन् १९०८) की धारा ४ में निर्दिष्ट माध्यम पर किसी पुनरावेदन या आवेदन पत्र को रजिस्टर करन के आदेश के विरुद्ध अथवा
 (ख) किसी आवेदन पत्र को निगरानी या नजरबंदी के लिये अस्वीकृत करन के आदेश के विरुद्ध या
 (ग) किसी [X X] आदेश के विरुद्ध जो इस अधिनियम में स्पष्टतः अंतिम बनाई गई है—

बोर्ड अपील नहीं हो सकेगी ।

[धारा ७२] पुनरावेदन के लिये अधि —

- (क) क्लर्क या मूलेन अधिकारी या मूषन-वाहारी के पास ऐसी आज्ञा के, जिसका विरोध किया जा रहा हो, जारी होने की तारीख के बाद तीस दिन की समाप्ति पर,
- (ख) रानर अरीन प्राधिकारी या मूषन-वा आयुक्त या मूलेन-वाह के पास ऐसी तारीख के बाद साठ दिनों की समाप्ति पर, या
- (ग) जोर के पास ऐसी तारीख के बाद नव्वे दिनों की समाप्ति पर—
कोर पुनरावेदन नहीं किया जा सकेगा ।

[घाग ७६] मिनाइग्रन्थ आदेश की प्रतिलिपि को अपील के साथ सम्मिलित करना — जब तक कि प्रतिलिपि अस्तुतः क्रिया जाना किसी आज्ञा द्वारा अनिवार्य न कर दिया जाय पुनरावेदन के प्रत्येक आवेदनपत्र के साथ ऐसी आज्ञा की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की जाती रहेगी ।

टिप्पणी — इस धारा में यह मन्त्र है कि जब कभी किसी मामले में प्रतीत की जाय तो सवाल व सावधान्य व सावधान्य की प्रमाणित प्रतिनिधि सम्मिलित हो जाय। प्रमाणित प्रतिनिधि प्राप्त करने का कार्य तथा सम्बन्धित न्यायालय में प्रस्तुत करने का कार्य अवधि के अन्तर् ही होना चाहिये।

[धारा ८०] अपीलेंद अयोरिटी की गन्तियाँ—(१) यदि अपीलेंद अपारिटी पाई हो अपील स्वीकार कर सक्ती है या रेकार्ड भगवा कर तथा पुनरावेदक को मुनगाई का एक मौका देने के उपरांत मरकारी तौर पर उसे थस्वीकृत कर सक्ती है।

परन्तु जब अशील अधि के बाहर हो अथवा अशील प्रस्तुत नहीं की जा सकती हो तो अमिलब मानने के लिये अशीलाद अथारिटी माध्य नहीं होगी।

(२) यदि असेल शोकार करली जायती तो मुनबाई की कोई सारीख तय की जायेगी त्रिमही सूचना प्रतिवादी को दी जायेगी।

(३) यदि पक्षकार उपस्थित हो तो उ हं सुनने के बाद अपीलेंट अधीक्षकरी गिराफ़्तार अपील की पुष्टि कर सकती है उनमें सशोभन कर मन्त्री है या उसे पलट मन्त्री है, या

किसी विरोध जाच पड़ताल या किसी अतिरिक्त साक्षी को सुनने के लिये नैसा यह उचित समझे, निदर्श कर सकती है या

यह स्वयं ऐसी अतिरिक्त साक्षी को सुने, या ऐसे विषयों की, ऐसे निदर्श सहित जो यह उचित समझे निपटारे के लिये वापस लाता सकती है ।

[धारा ८१] अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा के इजराय को रोकने की शक्ति — (१) यदि कोई अपील स्वीकृत करली जाती है तो अपीलेंट अधीक्षकरी अपील के निष्णय किये जाने तक ऐसी आज्ञा के जिससे अपील की गई हो इजराय को रोकने का निर्देश कर सकती है ।

(२) कोई भी राजस्थान न्यायालय या अधिकारी जिसने की आज्ञा दी हो ऐसी आज्ञा के इजराय को अपील के लिये नियत अग्रथि की समाप्ति के पहले किसी भी समय यदि अपील दायर नहीं की गई हो रोकने के लिये आदेश दे सकती है ।

यदि उपधारा (१) अधिन उपधारा (२) के अन्तर्गत किसी आज्ञा के इजराय को रोक दिया गया हो तो ऐसी अमानत ली जा सकती है अथवा ऐसी शर्तें लगाई जा सकती हैं जो कि अपीलेंट अधीक्षकरी या राजस्थान न्यायालय या अधिकारी उचित समझे ।

[धारा ८२] कमिशनर के अभिलेख (RECORD) आदि मगाना के अधिकार और सरकार गवर्नर बोर्ड की मामला विचारार्थ भेजना — किसी आदेश की वैधता एवं महत्ता के सम्बन्ध में और किसी कार्यवाही की नियमितता के सम्बन्ध में अपने आप को सन्तुष्ट करने के अथ से कोई भी आयुक्त या भ्रमण ध आयुक्त या भलेलाध्यक्ष या क्लर्क अपने अधिनस्थ किसी राजस्थान न्यायालय या अधिकारी द्वारा तय किये गये मामले या पूरी की गई कार्यवाही के रेकॉर्ड को मगवाकर उमकी जाच पड़ताल कर सकता है ।

साथ ही यदि उसका मत यह हो कि ऐसे अधिनस्थ न्यायालय या अधिकारी द्वारा जारी किये गये आदेश या की गई कार्यवाहियां परिवर्तित, निरसित या उल्टी जानी चाहिये

॥ सरकार बनाम भाग्या—१९६७ धार० धार० की ५६ में बोर्ड ने तय किया कि बोर्ड रेकॉर्ड को सुन सकता है वास्तुतः यह कि किसी मामले में बोर्ड को अपील पेश होती हो ।

तो यह अपनो राय के साथ ऐसे मामले को बोर्ड के पास आदेश के लिये भेज देगा, किन्तु शर्त यह है कि मामला अगलगी के योग्य हो अथवा भूप्रत्यय से सम्बन्धित हो अथवा यदि मामला गैर अगलगी हो कर भूप्रत्यय से सम्बन्धित न हो तो राज्य सरकार को आदेश हेतु प्रेषित करेगा,

और बोर्ड अथवा राय सरकार जैसी भी स्थिति हो, इसके परचात् उसे आदेश जारी करगी जो कि नमूने राज में दी गई हो ।

[धारा ८३] रेगर्ड मंगवाने एवं आदेशों के पुनर्वाचन की सरकार को शक्ति — राज्य सरकार अपने अगलगी किन्हीं भी अधिकारी से भूप्रत्यय से असम्बद्ध किसी गैर अगलगी कार्यवाही के रेगर्ड को मंगवा सकती है और उस सम्बन्ध में ऐसी आज्ञा दे सकती है जो यह उचित समझे ।

[धारा ८४] रेगर्ड मंगवाने तथा आदेश पर पुनर्वाचन करने सम्बन्धी बोर्ड के अधिकार — बोर्ड अगलगी दफ्तर के अथवा भूप्रत्यय से सम्बन्धित किसी विषय का निम्नलिखित में बोर्ड में कोई पुनरावेदन नहीं किया जा सकता हो, रेगर्ड मंगवा सकता है यदि ऐसा प्रतीत हो कि उस न्यायालय या अधिकारी ने जिसके द्वारा मामला नया लिया जाय ऐसा विचारधारा का प्रयोग किया है जो कानून द्वारा उसमें निहित नहीं किया गया है अथवा निम्नलिखित में किसी विचारधारा के प्रयोग करने में असफल रहा है अथवा अपने विचारधारा के प्रयोग में गैर कानूनी दम से या महत्वपूर्ण अनियमितता से काम लिया है और उस मामले में ऐसा आदेश दे सकता है जो यह उचित समझे ।

[धारा ८५] सुनवाई — धारा ८० या धारा ८१ या धारा ८२ के अधीन किसी भी शक्ति के विरुद्ध कोई आदेश तब तक नहीं दिया जा सकेगा जब तक कि उसे सुनवाई का एक मौका न दे दिया जाय ।

टिप्पणी — यह धारा उस प्रकार की सुनवाई का अधिकार देती है जिस पर रेगर्ड अपील, जोच पड़ाना आदि भी कार्यवाहियों के परिणामस्वरूप कोई फरार होने वाला हो । सरकार के विचार माग्न न होने बिना किसी भी प्रकार की आज्ञा उस पर लागू नहीं होगी ।

[धारा ८५] या राज्य सरकार द्वारा नजरसानी — राज्य सरकार अपने आप न्याय की शक्ति से अथवा बाद में सम्बन्धित किसी के आवेदन-पत्र देने पर नजरसानी कर सकती है या रोक, बदल कर सकती है या किसी आज्ञा को जो इस कानून के अधीन ही गढ़ हो बहाल रख सकती है ।

टिप्पणी — [राजस्थान लेग्ड रेग्युलेशन (एक्ट्स) एक्ट १९९० (एक्ट २९ भाग १९९०) को राजस्थान पत्र विनोदीय कण्ड ४ व विनोद १४-६ ९० को सम्बन्धित हुआ के अनुसार प्रावधान सम्मिलित हुआ]

(३) यदि पक्षधार उपस्थित हो तो उक्त गुण के बाद अपीलेट अथॉरिटी रिवाद परत अपील की पुष्टि कर सकती है उनमें संशोधन कर सकती है या उसे पत्रट मफनी है, या

किसी विशेष जाच पड़ताल या किसी अतिरिक्त साक्षी को सुनने के लिये नैमा यह उचित समझे, निदरा कर सकती है या

यह स्वयं ऐसी अतिरिक्त साक्षी को सुनने, या उसे विषयों की, ऐसे निरा सहित को यह उचित समझे निपटारे के लिये वापस लौटा सकती है।

[धारा ८१] अधीनस्थ न्यायालय की आना रु इजराय को रोकने की शक्ति — (१) यदि कोई अपील स्वीकृत करली जाती है तो अपीलेट अथॉरिटी अधीन के निणय किये जाने तक ऐसी आह्वा के जिसकी अपील की गई हो इजराय को रोकने का निर्देश कर सकती है।

(२) कोई भी राजस्थान न्यायालय या अधिकारी जिसने की आना दी हो ऐसी आह्वा के इजराय को अपील के लिये नियत अग्रधि की समाप्ति के पहले किसी भी समय, यदि अपील दायर नहीं की गई हो, रोकने के लिये आदेश दे सकती है।

यदि उपधारा (१) अधवा उपधारा (२) के अन्तगत किसी आह्वा के इजराय को रोक दिया गया हो तो ऐसी जमानत ली जा सकती है अधवा ऐसी शर्तें लगाई जा सकती हैं जो कि अपीलेट अथॉरिटी या राजस्थान न्यायालय या अधिकारी उचित समझे।

[धारा ८२] कमिश्नर के अभिलेख (RECORD) आदि मगानन रु अधिकार और सरकार अथवा बोर्ड को मामला विचारार्थ भेजना — किसी आदेश की वैधता एवं महत्ता के सम्बन्ध में और किसी कायवाही की नियमितता के सम्बन्ध में अपने आप को मतुष्ट करने के अथ से कोई भी आयुक्त या भ्रम्रध आयुक्त या अलेखधध, या कमिश्नर अपने अधिनस्थ किसी राजस्थान न्यायालय या अधिकारी द्वारा तय किये गये मामले या पूरी की गई कायवाही के रेकाड को मगानन उमधी जाच पड़ताल कर सकता है कि

साथ ही यदि उमका मत यह हो कि ऐसे अधिनस्थ न्यायालय या अधिकारी द्वारा जारी किये गये आदेश या की गई कायवाहिया परिवर्तित निरसित या उल्टी नानी चाहिये

कि सरकार वनाम मागवा—१९६७ धार० धार० की ४६ में बोड ने तय किया कि बोड रेकरेत की मुन सकता है वाबजूद इसके कि किसी मामले में बोड को अपील देना होती हो।

तो यह अपनी राय के साथ ऐसे मामले को बोर्ड के पास आगे के लिये भेज देगा, किन्तु तब यह है कि मामले का अग्रचरण के योग्य हो अथवा भूप्रत्यय में सम्बन्धित हो अथवा यदि मामला गैर अग्रचली हो कर भूप्रत्यय में सम्बन्धित न हो तो राज्य सरकार को आदेश हस्त प्रेषित करेगा,

और बोर्ड अथवा राज्य सरकार जैसी भी स्थिति हो, इसके परचात् ऐसे आदेश जारी करेगी जो कि उसी राय में दी गई हो ।

[भाग ८२] रेकर्ड मंगवाने एवं आदेशों के पुनर्वाचन की सरकार की शक्ति —राज्य सरकार अपने अग्रचल्य किसी भी अधिकारी से भूप्रत्यय से असम्बद्ध किसी गैर अग्रचली कार्यवाही के रेकर्ड को मंगवा सकती है और उस सम्बन्ध में ऐसी आज्ञा दे सकता है जो वह उचित समझे ।

[भाग ८४] रेकर्ड मंगवाने तथा आदेश पर पुनर्वाचन करने सम्बन्धी शक्ति के अतिरिक्त —बोर्ड अग्रचली दफ्तर के अथवा भूप्रत्यय से सम्बन्धित किसी विषय का, निम्नोक्त मन्त्र म बोर्ड म कोई पुनरावेदन नहीं किया जा सकता हो, रेकर्ड मंगा सकता है यदि ऐसा प्रतीत हो कि उस न्यायालय या अधिकारी ने जिसके द्वारा मामला नय किया जाय ऐसा विचाराधिकार का प्रयोग किया है जो कानून द्वारा उसमें निहित नहीं किया गया है अथवा निहित विनियमों किसी विचाराधिकार के प्रयोग करने में असमर्थ रहा है अथवा अवन विचाराधिकार के प्रयोग में गैर कानूनी दम से या अन्यायपूर्ण अनियमितता से काम लिया है और म मामले में ऐसा आदेश दे सकता है जो वह उचित समझे ।

[धारा ८६] बोर्ड ऑफ न्यायालयों द्वारा पुनर्विचार—(१) यो अपना इच्छा से अथवा मामले या कार्यवाही के किसी पक्ष के प्रार्थनापत्र पर अपने द्वारा या अन्य सदस्य म से किसी भी सदस्य द्वारा दी गई आज्ञा पर पुनर्विचार पर सत्ता है और उसे रद्द, संशोधित या पुष्ट पर सत्ता है।

(२) प्रत्येक अन्य राज्य यायालय या अधिमारी इच्छा से अथवा स्थापन करने वाले किसी व्यक्ति या प्रार्थनापत्र पर अपने ही द्वारा अथवा अपने पूर्वगामी पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त आज्ञा या पुनर्विचार पर सत्ता है तथा उससे सम्पन्न म मने आदेश द सकना है जो यह उचित समझे कि-उ शान यह है कि—

(१) कोई भी आज्ञा उस समय तक सराफित या परिवर्तित नहीं की जायगी जब तक कि उसमें दिन रखने या न पक्षकारों को उपस्थित होने का ऐसी आज्ञा के पक्ष में कुछ कहने का मौका नहीं दिया जायेगा,

(२) किसी भी आज्ञा पर जिसने विरुद्ध अपील कर दी गई हो अथवा जो निगरानी की कार्यवाही का विषय हो, उस समय तक पुनर्विचार नहीं किया जा सकेगा जब तक कि ऐसी अपील या कार्यवाही विचारणीय हो,

(३) किसी भी आज्ञा को जो निजी-व्यक्तियों के बीच किसी अधिकार के प्रश्न पर प्रभाव करती हो, कार्यवाही में सम्मिलित पक्ष के प्रार्थनापत्र देने के अलावा पुनर्विचार नहीं किया जायेगा और इस प्रकार के पुनर्विचार का कोई भी आवेदनपत्र ऐसी आज्ञा के जारी होने के उपरान्त नब्बे दिन समाप्त हो जाने के उपरान्त प्रस्तुत किये जाने पर स्वीकार नहीं की जायेगी।

(४) इस धारा के अन्तर्गत पुनर्विचार के लिए आवेदनपत्र जलवा दीवानी (केन्द्रीय एक्ट स० ५ सन् १९०८) अधिनियम की प्रथम अनुसूची के आदेश ४७ के नियम १ में बताये गये आधारों में से किसी पर भी दी जा सकती है और उपधारा (१) एवं (२) के अन्तर्गत उक्त आदेश के प्रावधान प्रयोग में लाये जायेंगे।

टिप्पणी—उक्त धारा यह प्रक करती है कि कि बोर्ड, पुनर्विचार कर किसी सत्य का आज्ञा को रद्द कर सकता है अथवा उसमें संशोधन, परिवर्तन कर सकता है। यह अधिकार राजस्व अधिकारियों का भी प्राप्त है। पुनर्विचार, याचनार्थ पक्षों अधिकारियों कभी कभी अपनी इच्छा से भी कर सकता है किन्तु व्यक्तिगत मामलों में यह कार्य इतना रखने वाले व्यक्ति द्वारा आवेदनपत्र देने पर ही किया जायेगा।

(धारा ८७) एक्ट स० ६ सन् १९०८ का प्रभाव—भारतीय अन्ति अधि नियम १९०८ (केन्द्रीय एक्ट स० ६ सन् १९०८) के प्रावधान इस अधिनियम के अन्तर्गत होने वाली अपील एवं पुनर्विचार पर लागू होंगे।

अध्याय ६

भूमि

(धारा ८८) जिन पर किसी दूसरे का अधिकार न हो वे समस्त मार्ग व समस्त भूमि राज्य की सम्पत्ति होंगे—(१) समस्त आम सड़कें, गलियाँ रास्ते पुल

एवं गड़ने, तथा उपर या उनके चारों ओर की सभी बाड़ें समस्त नदियां, निर्धार, नाने मीलों व तालाब, सभी नहरें तथा जल प्रणालियां सभी स्थिर एवं प्रबलमान जल और वही भी स्थित सभी जमीन जो कि किसी व्यक्ति या पुरुषों या राजा की जो सम्पत्ति रखने के लिए वैधानिक रूप से अधिकारी है, सम्पत्ति नहीं हो राज्य सरकार की सम्पत्ति है केवल उम हूँ तब कि उस पर उन व्यक्तियों या निवासी का कोई अधिकार स्थापित किया जाय और केवल उस हूँ व जो किसी अन्य प्रभावशील कानून के द्वारा उम सम्पत्ति में मजूर की जाय तथा हमारे द्वारा घोषणा की जाती है कि ऐसी समस्त सम्पत्तियों पर या उनमें समाविष्ट अधिकार तथा उनसे सलज्ज सम्पत्तियों पर अधिकारी भी राज्य सरकार में समाहित होंगे और राज्य सरकार के आदेश के अन्तर्गत कलक्टर के लिये यह रचित होगा कि वह निर्धारित शक्ति से उनका नियंत्रण कर सितु, राशियों के हक पर कानूनन अधिकारी व्यक्ति एवं आम जनता के अधिकारों का भेद ध्यान रखा जायेगा।

(५) किसी सम्पत्ति में या उम पर सरकार द्वारा उमरी ओर से अथवा सरकार के विरुद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी अधिकारी या अश का चर कमी द्वारा दायर किया जाय ता फलस्तर को यह हक होगा कि वह ऐसी आम जाच पड़ताल के परचान विसर्जी सूचना भी गड़ हो ऐसे दाव के तय करने हेतु आवश्यक आदेश निशाले।

(६) उपधारा (१) प्रथमा उपधारा (२) के अधीन दिये गए आदेश की तारीख के परचान या यदि अधि उ धीच एव या एक से अधिक व्यक्तियों ऐसे आदेश के विरुद्ध पेश की गड़ हो तब ऐसी तारीख के परचान जबकि अन्तिम पुनरावेदन अधिकारी आदेश एक वर्ष के उपरांत दायर किया गया तथा स्थापित कर दिया जायगा (अधि की रक्षा न साधन न बना गया हो) यदि दावा ऐसे आदेश को खण्डित करने हेतु दायर किया जाय अथवा मांगी गई सहायता इसके विरुद्ध हो।

परंतु उपधारा (५) के अधीन निकाले गए आदेश की अरथा में मुद्दह को अनि वाय सूचना प्राप्त हो गड़ हो।

(७) किसी आदेश या जाच पड़ताल की आवश्यक सूचना में धारा के अधीन व्यक्ति को दावी, यदि इस अधिनियम या इसके अन्तर्गत निर्मित नियमों के अनुसार कोई सूचना दी जायगी।

(८) उपधारा (१) या उपधारा (२) के अधीन निकाला किया गया प्रत्येक आदेश का फलस्तर, नियत प्रणाली से इतराव करायगा।

(धारा ८६) सनित्र पत्राओं, सान खोने और मजनी पड़ने का अधिकार — (१) नदिया में मजली निकालना नौकानयन या मिगड़ के सभी प्रकारों पर शिष्टों सभी सनित्र पदार्थ, खानों पर पथर की खानों पर राज्य सरकार या हक होगा और राज्य सरकार के, ऐसे अधिकार के पूर प्रयोग के लिए, सभी हक सन्निहित होंगे।

(२) पत्थर की मानों तथा अथ समस्त खातों के हक में जो देने के काय एवं पत्थर की तुलनाई के लिए उस भूमि पर पट्टा चो का अधिष्ठात भी शामिल होगा तथा निम्नवर्ती भूमि को कब्जे में लेने का अधिकार भी होगा कि जो जो देने के काय से मूल्यन कार्या की पूर्ति हुआ आधारित हो नैव कि कार्यालय पर महानान बनाने मन्त्रों के नियाम गृह एवं मशीनघरा के बनाने, स्वनिज पदार्थों के संग्रह के भित्ति गोदाम बनाने तथा बूँद को भरने के स्थान बनाने, रेल या ट्राम मद्र के निर्माण करने और किसी अथ कार्य करने के लिए जिसे राज्य सरकार जो देने के काय पर पत्थर तुलनाई से सन्तान घटित कर ।

(१) यदि राज्य सरकार किसी व्यक्ति को स्वनिज पदार्थ खाना एवं पत्थर की तुलनाई सम्बन्धी करने अधिकार मौके और यदि ऐसे हक के प्रयोग के लिए उपधारा (१) तथा (२) में निर्दिष्ट मन्त्रों या किसी अधिकार का ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रयोग किया जाना आवश्यक प्रतीत हो तो कन्स्ट्रक्टर एक लिखित आदेश द्वारा, स्वनिज शर्तों एवं आरक्षणों के अन्तर्गत उस व्यक्ति को शक्तियाँ मौके सहज है जिससे कि अधिकार मौके दिये गये होंगे ।

परन्तु ऐसा कोई समपण नहीं किया जायेगा तथा उस सम्पद में उनके जब तक सम्बन्धित भूमि में अधिकार रखने वाले अथ व्यक्तियों को सूचित नहीं कर दिया हो द्वारा उठाई आपत्तियों की सुनवाई न करली गई हो ।

(५) यदि पूर्वलिखित किसी अधिकारी के उपयोग के कारण किसी ऐसी भूमि की सतह को अधिकार में लेने या अन्य प्रकार से उपरोध पैदा करने से किसी के अधिकारों पर हमला हुआ तो राज्य सरकार या उसका प्रहण करने वाला ऐसे व्यक्तियों को ऐसे आघात के लिए क्षतिपूर्ण देगा और ऐसे क्षतिपूर्ण की रकम का हिसाब क्लर्कटर द्वारा तय किया जायेगा अथवा यदि उसका निर्णय अस्वीकृत रहे तो दीवानी अदालत द्वारा जहाँ तक हो सके राजस्थान भूमि अधिपति अधिनियम १९५३ (राजस्थान भूमि अधिपति अधिनियम संख्या ४ सन् १९५३) के प्रावधानों के अनुकूल ही क्षतिपूर्ण का हिसाब निपटारा जायेगा ।

(५) राज्य सरकार का कोई भी गृहीता क्लर्कटर की पूर्ण स्वीकृति के बिना किसी भी भूमि सतह पर न प्रवेश कर सकेगा और न हक ही जब तक क्षतिपूर्ण तय नहीं कर लिया गया हो और उस व्यक्ति को दे न दिया गया हो जिसने अधिकारों में हस्तक्षेप हुआ हो ।

(६) उपधारा (४) के अधीन प्रावधानित क्षतिपूर्ण देने में यदि राज्य सरकार का कोई गृहीता असफल रह तो क्लर्कटर उस क्षतिपूर्ण के हकदार के निमित्त उस गृहीता से ऐसा क्षतिपूर्ण वसूल करने की भाँति कार्यवाही करेगा मानो वह कोई भूराजस्व का ही लगान हो ।

(७) बिना किसी वैध अधिकार के यदि कोई किसी खान पत्थर की खान से स्वनिज पदार्थ निकालता है या हटाना है जिसका अधिकार राज्य सरकार में समाहित हो और जो किसी अन्य व्यक्ति को मारा नहीं गया हो किसी अथ कार्यवाही के लिए

जाने पर कोई भी प्रभाव नहीं डालने हुए, क्लकटर के लिखित आदेश पर ऐसे निशानों को या हटाये गये खनिज पदार्थ के प्रत्येक टन या उसके किसी अंग पर अभिलिखित ५०) २० के हिसाब से शास्त्रित न का दरदानी होगी।

परन्तु यदि इस प्रकार दिनांक लगाई रकम एक हजार से कम होगी तो शास्त्रित ऐसी कोई अधिकतरकम होगी जो क्लकटर द्वारा आरोपित की जाय लेकिन वह रकम एक हजार से अधिक नहीं होगी।

दफ्तीकरण — 'खनिज पदार्थ' शब्द के अन्तर्गत इस धारा में किसी भी प्रकार की खनिज मिट्टी भी शामिल होगी जिसका खनिज जनता के उपयोग का होना या व्यापारिक विशेषता का होना राज्य सरकार द्वारा घोषित कर दिया गया हो।

टिप्पणी — यह धारा भूमि पर, खानों पर तथा नदियों पर राज्य सरकार के अधिकार का प्रादुर्भाव करती है। राज्य सरकार ऐम अधिकार अन्य व्यक्तियों को सौंपती मकर पट्टों पर द मकती है। यदि राज्य सरकार अपना उनका पट्टेदार खान खाने समय या निभाई करत समय अन्य व्यक्तियों का भूमि का मुकसान पहुँचाता है तो वह उन व्यक्तियों को क्षति दमे। धारदकता पटन पर यह शक्ति सम्बन्धित व्यक्तियों को सरकार निभा सकती है। का शक्ति बिना किसी बाधनी अधिकार का खान खान या पत्थर हटाय ता उस पर कोबगरी कापवाही का अधिकार ५१) ६ प्रति टन का हिसाब से शास्त्रित निभाई जायगा। यह शास्त्रित अधिकार अधिक १०००) ६० तक हो सकती है।

[धारा ६०] राजस्व या लगान की श्रृंगारगी या उत्तरदायित्व समग्र भूमि पर — (१) निराय इसके कि ऐसी भूमि राज्य सरकार के किसी विशेष अनुदान के अन्तर्गत तथा सरकार के साथ किने गये किसी मरिदा के अनुसार अथवा वर्तमान में प्रमान्यित किमा कानून के प्रावधानों द्वारा ऐमे अनुदान से पूर्ण रूपेण मुक्त हो, इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों के रहत हुए समस्त भूमि चाहे वह किन्हीं पर अवस्थित हो और चाहे किसी कार्य से प्रयुक्त हो, राज्य सरकार को दय राजस्व या लगान के लिये प्रतिनियमित होगी।

(२) राजस्व या लगान की अदायगी में ऐसी भूमि को न भूमि के आधिपत्य का दीर्घ अवधि यवा सकती है और न किसी सम्पत्ति धारक द्वारा प्रदत्त अनुदान हो।

(३) राज्य सरकार किसी विशेष अनुदान या मरिदा द्वारा या वर्तमान में प्रभाव शाल किमी कानून के प्रावधानों के अनुसार किमी भूमि में ऐसी अदायगी की जम्मेदारी से मुक्त कर सकती है।

(४) इसके अतिरिक्त कि ऐमा राजस्व या लगान उनके सुपुर्गा, मुक्ति समन्धीन अथवा पुनरोद्धार के कारण राज्य सरकार को देय नहीं हो, राजस्व या लगान सैन्य भूमि पर निधारित किया जायेगा।

[धारा ६० क] कृषि की भूमि को गैर कृषि साधों में प्रयोग—(१) कोई व्यक्ति, जो कृषि प्रयोगागालु किसी भूमि को रगना हो और कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने ऐसी भूमि या भूमि का हिस्सा लगादना की गद्द हो, उस भूमि को या भूमि के हिस्से का उस पर इमारत बनाना या प्रयोग में अथवा अथ विसा प्रयोजन में नही लावगा भिनाय इससे कि यह राज्य सरकार से लिखित में यद्दा यता, गद्द प्रणाली या अनुमति तथा अन्य प्रकार की गद्द आशा की शर्ता या अनुमति अनुमति प्राप्त नहीं कर लें।

(२) ऐसा पाद् व्यक्ति जो ऐसी भूमि को या भूमि के हिस्से को गैर कृषि के किसी अन्य कार्य में प्रयोग में लाना या इत्यादि हो तो यह याद्विध इत्यादि के लिये याद्विध प्रणाली से और याद्विध अधिकारी को दरतास्त दगा और रसा दरतास्त में याद्विध विवरण दिया हुआ होगा।

(३) राज्य सरकार नियत प्रणाली द्वारा उचित जाच करने या जाच का प्रकार की कार्यकारी करने या तो इत्यादि देने में नामजुरी कर दगी अथवा अन्य शर्ता या नियमों पर स्वीकृति प्रदान कर देगी।

(४) जब कभी ऐसी भूमि या भूमि के हिस्से के विषय में किसी व्यक्ति को गैर कृषि कार्य के प्रयोग के लिए इत्यादि देदी जावे तो उस व्यक्ति को जिसे ऐसी इत्यादि मिली हो राज्य सरकार को उस भूमि के लिए,

(क) राज्य सरकार द्वारा इस विषय में बनाये गये नियमों में बनाई गई रद्द और उत्पन्न किये गये तराजे से नगर सुधार कर (अरबन असेसमेंट), जो लागू किया गया हो, या

(ख) राज्य सरकार से नियत की गई रकम प्रीमियम के रूप में, या

(ग) दोनों,

देने होंगे।

(५) यदि ऐसी कोई भूमि—

(क) राज्य सरकार की लिखित अनुमति पहले प्राप्त किये बिना, या

(ख) उक्त अनुमति के निम्नधना तथा शर्ता या अनुसरण न करते हुए अन्य प्रकार से, या

(ग) ऐसी अनुमति दी जाने से उपधारा (३) के अन्वीन इत्यादि कर दिया जाने के बाद, या

(घ) उप धारा (४) में निर्देशित गुणानों में से किसी का भी भुगतान किये बिना, उक्त रूपण काम में लाई जाय तो, यह व्यक्ति जो उस भूमि को प्रारम्भत कृषि के लिये धारण करता हो तथा समस्त अनुमति हस्तांतरिती यदि कोई हो, यथास्थिति, अतिव्यवहारी (ट्रैसपासर) समझा जायगा/समझें जायेंगे और धारा ६१ के अनुसार उसे/उन्हें इस प्रकार चेदल किया जा सकेगा माना उसका/उनका बिना वैध अधिकार के उस भूमि पर कब्जा

या/या कच्चा नारी रहा था और प्रत्येक ऐसी कार्यवाही पर राजस्थान टोनेन्सी एक्ट, १९५५ (राजस्थान एक्ट सं० ३, सन् १९५५) की धारा २१२ के प्रावधान इस प्रकार लागू होंगे माना जायेगा कि भूमि नष्ट, क्षतिग्रस्त अथवा अयकान्त किये जाने के स्तर में थी

किंतु राज्य सरकार, वैसे व्यक्ति तथा अनुवर्ती हस्तांतरितियों को सम्बन्धित भूमि से उपरोक्त भाति चेदखल किए जाने के बजाय, उस दशा में जब कि वह/वे यथा स्थिति, राज्य सरकार को, उप धारा (४) के अधीन देय नगर सुधार पर (Urban Assessment) तथा प्रीमियम अदा करने के अलावा उत्तरी शास्ति ऐसा जुर्माना जो निर्धारित किया जाय चुका दे/दें, उक्त भूमि को रखने और कृषि से भिन्न किसी अन्य प्रयोजन के लिये उपयोग करने की अनुमति दे सकेगी।

[धारा ६१] भूमि पर अनाधिकृत आधिपत्य — यदि कोई किसी भूमि पर अधिपत्य करता है अथवा करना चाहता है तो उसे अतिक्रमी समझा जावेगा और तहसीलदार द्वारा उसकी इच्छानुसार अथवा उस स्थानीय सत्ता के आवेदन पर पर जिसकी देखरेख में ऐसा भूमि सौंपी गई है, ऐसा अतिक्रमी भूमि से तत्काल बाहर किया जा सकता है और उस भूमि पर [x x x x] बनाया गया कोई मकान या अन्य ढाचा अथवा संप्रहित कोई वस्तु, तहसीलदार द्वारा समय-समय पर उसको हटाने के सम्बन्ध में दिये गये विहित समय में नहीं हटाये जाने पर, राज्य सरकार के हुक्म में जप्त करली जायेगी और कलक्टर के निर्देशानुसार फैसला कर दिया जायेगा।

परन्तु तहसीलदार किसी ऐसे मकान या अन्य ढाचे को अधिपत्य करने के बजाय उसे या उसके किसी हिस्से को गिराने का भी हुक्म दे सकता है।

(२) ऐसा अतिक्रमणकारी साथ ही प्रत्येक कृषि वर्ष निम्नमें बसने पूरे वर्ष के लिये या वर्षा श के लिये उक्त रूपेण करना धारण किया हो शास्तिके तौर पर ऐसी रकम चुकाने का माग होगा जो सालाना लगान या कर निर्धारण यथा स्थिति के पन्द्रह गुना तक हो सकती है और उक्त रकम भू-राजस्व की वकाला के रूप में समूल की जायेगी किंतु उक्त शास्ति का सुगमन करने पर उसे किसी अन्य एकत्रित फसल का परिपोषण करने एकत्रण करने तथा हटाने का अधिकार होगा।

(३) उपधारा (१) के अन्तर्गत अतिक्रामी को सम्पत्ति ग्रहण करने की कार्यवाही करने के पूर्व तहसीलदार उस व्यक्ति पर जिस पर सम्बन्धित है कार्रवाई तौर पर भूमि के पट्टे में गये जान या रखने की रिपोर्ट की जाय एक सूचना तामील करावेगा जिसमें उस भूमि का उल्लेख होगा तथा ऐसी भूमि का किमा निर्दिष्ट तारीख तक मानी

का अथवा हाजिर होकर अपने उपभोग शुरू नहीं किये जाने के पक्ष में कारण पेश करने के लिये भी निर्देश दगा ।

(४) किसी भी निम्नांकित मामले में, अर्थात्

(१) जब कि उपधारा (३) के अन्तर्गत दिये गये नोटिस के जवाब में अतिरामी न तो भूमि को छोड़ें और न हाजिर ही हो, या

(२) जब कि ऐसे नोटिस के उत्तर में अतिक्रामी भूमि नहीं छोड़ें और हाजिर न हो, किन्तु —

(क) कोई कारण सामने नहीं रटे, अथवा

(ख) विषय की परिस्थितियों के अनुसार प्रस्तुत किया गया प्रतिनिधित्व आय शयक अनुसंधान एव सुनवाई के परचार अस्वीकृत कर दिया नाथ नो तहसीलदार केवल इसके खण्ड (२) के विषय में अतिक्रामी को एक सप्ताह में जमीन खाली करने की आज्ञा दे और उसे छोड़ दे, अतिक्रामी को हटाने का आदेश देगा और उसे हटायेगा या किसी व्यक्ति को उसे उस भूमि से हटाने को और पकड़ा करन को भेजेगा और यदि तहसीलदार या उसके द्वारा प्रेषित व्यक्ति के द्वारा भूमि का आधिपत्य लेने में विरोध या बाधा डाली जाय तो तहसीलदार क्षेत्राधिकार रखने वाले मजिस्ट्रेट के पास आवेदन पत्र भेजेगा और ऐसा मजिस्ट्रेट तहसीलदार को भूमि की वापिसी किये जाने की कार्यवाही करायेगा ।

(५) यदि ऐसी भूमि, उपरोक्त उपधाराओं में उल्लिखित किसी भी बात के अतिरिक्त धारा ६७ के प्रतिबंध के खण्ड (२) में वर्णित वग में सम्मिलित होगी तो तहसीलदार सप्त डिविजनल अधिकारी की सहमति से अतिक्रमिन् को वेच देगा जब कि उसने द्वारा ऐसी उपधारा (२) के अधीन अधिधानिक वज्जे की सम्पूर्ण अवधि के लिये घसूल किए जाने योग्य शास्ति तथा धारा ६६ के अधीन निधारित प्रीमियम जमा करायेगा ।

[धारा ६२] विशेष कार्याय भूमि को विलग करना — (१) क्लर्कर किसी विशेष कार्य के लिए राज्य सरकार के आम सामान्य आदेश के अधीन जैसे कि चौपायों की सुफ्त चराई वन संरक्षण आनादी के विनास या किसी अन्य आम या म्युनिसिपल काम के लिए कोई भूमि अलग से छोड़ सकता है और ऐसी भूमि क्लर्कर की पूर स्वीकृति के अलावा अन्य राज्य के उपयोग में नहीं लाई जायगी ।

[धारा ६३] चारागाह के उपयोग का नियमन — चारागाह भूमि पर चराई का अधिकार गाव या गांव के क्षेत्र उन्ही चौपाये पशुओं तक रहेगा जिनके लिए वह भूमि छोड़ी गई होगी और राज्य सरकार द्वारा निर्मित नियमों के मुताबिक उसका नियमन होगा ।

[धारा ६४क] सड़क के किनारे के वृक्ष :—(१) तमाम सड़क के किनारे के वृक्ष निम्नो सरकार के आदेश से अथवा खर्च से लगाया गया है या पाला गया है, और ऐसे तमाम वृक्ष निम्नो स्थानीय मद या रकम से लगाया, और पाला गया है, जो किसी सड़क के किनारे सड़ें हों, तथा जो राज्य सरकार के हों, उन पर राज्य सरकार का अधिकार होगा।

(२) ऐसे वृक्षों के मर जाने पर अथवा हरा आदि, से गिर जाने अथवा निलावीश के आदेश से काटे जाने पर उनकी सारी राज्य सरकार की सिल्हियत होगी।

[धारा ६४ख] अनधिकृत रूप से काम में लिए गए बिना आज्ञा के पेड़ों आदि की रकम की वसूली :—(१) कोई भी व्यक्ति जो, बिना आज्ञा के, सड़क के किनारे के पेड़ या उसके किन्हीं हिस्से को, अनधिकृत रूप से बेच देगा अथवा, अन्य प्रकार से उपयोग में लेगा, अथवा उस पेड़ की प्राकृतिक उपज को हटा लेगा तो उससे उस वस्तु की कीमत राज्य, सरकार वसूल कर सकेगी, और ऐसी वसूली, भूमि कर, या कराया की भांति ही वसूल की जा सकेगी। यह रकम उस, दण्ड, के अलावा होगी, जो कि किसी कानून के अन्तर्गत, उस व्यक्ति को देनी पड़े।

(२) निलावीश का निर्णय ऐसे पेड़ अथवा हिस्से अथवा उपज की कीमत, के विषय में, अन्तिम होगा।

[धारा ६५] आवादी का विकास :—राज्य सरकार आवादी के विकास के लिए अलग छोड़ी गई भूमि को रिजर्व करने के लिए अथवा ऐसी भूमि के काटे जाने के बारे में या ऐसी भूमि के सम्बन्ध में कोई आवादी के सम्बन्ध में और इस प्रकार के विभाजन के अधिकारों की घोषणा हेतु नज़ूल भूमि के अलाटमेंट करने के लिए या अलग छोड़ी गई ऐसी भूमि के लिए नियम बना सकेगी।

(२) कोई भी व्यक्ति (x x x) आवादी क्षेत्र की कोई भी जमीन, इस अधिनियम के अन्तर्गत नियमित रूप से कोई प्रतिफल दिये बिना, कोई भी जमीन कानून में नहीं लेगा।

(३) आवादी की भूमि में, ऐसा प्रतिफल दे देने के बाद ही सर्वांग पूर्ण अधिकार प्राप्त होगा।

(४) इस अधिनियम के प्रभावशील होने के वक्त किसी व्यक्ति के बंध आधिपत्य में होने वाली (x x x) किसी आवादी के क्षेत्र पर इस धारा की कोई भी बात लागू नहीं होगी।

(५) जहाँ इस अधिनियम के लागू होने के समय कोई व्यक्ति (x x x) आवादी के क्षेत्र की किसी भूमि को मोजित अधिकारों सहित अपने अधिग्रहण में रखे हुए होगा, वह उस भूमि में पूर्ण अधिकार प्राप्त कर सकेगा किन्तु शर्त यह है कि वह ऐसा प्रतिफल अदा करे कि ता इस अधिनियम के अन्तर्गत निश्चय किया जाए।

(६) इस अधिनियम के प्रभावशाल होने के बाद कोई भी व्यक्ति जो, उपधारा (१) के प्रावधानों के अनुसार के अतिरिक्त या उपधारा (१) के अधीन निर्मित नियमों के बाहर कोई भूमि आवादी क्षेत्र में ग्रहण करता है अथवा बिना किसी समुचित अधिधार के ऐसी भूमि पर अलग से अथवा अपने पड़ोसी की जमीन पर पट्टा से स्थित किसी इमारत या ढांचे का पढ़ाते हुए कोई ढांचा तैयार करवाता है या अभी प्रभावशीलता के पर्याप्त किसी उचित अधिकार के अलावा तरीके से उपधारा (५) में संदर्भित भूमि पर अथवा ऐसी भूमि एवं अपने आधिपत्य में स्थित या अन्य रीति से रखी हुई भूमि, किसी अन्य भूमि पर कोई ढांचा बनाता है, अतिरिक्त माना जायेगा। और उसे किसी भूमि को बिना किसी वैध अधिकार के अधिवास में रखने वाला या अधिवास में रखना चाह रखने वाला व्यक्ति समझा जायेगा।

(७) उपधारा (६) में उल्लिखित पुरुष भूमि एवं ढांचों पर धारा ६१ के प्रावधान प्रभावशील होंगे—

परन्तु शत यह है कि—

(१) धारा ६१ की उपधारा (१) (२) (३) और (४) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा प्रयोज्य अधिकार, उसके द्वारा [x x x x] आवादी की भूमि के बारे में या किसी अन्य भूमि के बारे में जो चौपाये की मुफ्त चराई के लिए अथवा आवादी के निवास के लिए या किसी अन्य सार्वजनिक एवं आवादी के प्रबंध के उपयोग के लिए अलग रखी हुई भूमि जो कि धारा ६२ की उपधारा (२) के अंतर्गत या अन्य रीति से किसी स्थानीय संस्था के प्रबंध में धारा १०२ के अनुसार रखी गई हों उससे पास ऐसी संस्था द्वारा अर्जों दिये जाने पर प्रयोग में लाय जायेगे। या स्वतः और जबकि तहसीलदार स्वतः कायदाही करने का विचार करे वह अपने उक्त विचार की मूचना सम्बद्ध स्थानीय संस्था को देगा।

(२) इन उपधाराओं के अधीन अतिक्रमक पर शास्तिया लगाकर ऐसी स्थानीय संस्था के फण्ड में नमा की जायेगी, और

(३) धारा ६१ की उपधारा (५) के अधीन तहसीलदार द्वारा प्रयोज्य अधिकार, पूर्ववत् किसी स्थानीय संस्था के निम्मे रखी गई भूमि के प्रबंध में ऐसी स्थानीय संस्था द्वारा किसी अधिकारी की अनुमति के बिना ही प्रयोग में लाये जायेगे।

[धारा ६६] प्रीमियम की दरें कलक्टर नियत करेगा —(१) राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित कर नजूल या दूसरी भूमि के लिये जो आवादी के क्षेत्र में ही प्रीमियम की दरें नियत करेगी तथा समय समय उ ह दोहरायेगी।

(२) ऐसी दर उसी गांव कस्बों या शहर या गांवों कस्बों व शहरों के समूह के अंदर अन्य विभिन्न क्षेत्रों की तथा भूमि की स्थिति की कीमत को ध्यान में रखते हुए इस अधिनियम के अंतर्गत निर्मित नियमों की संगति में तय की जायेगी।

[धारा ६७] आगदी की भूमि की निलामी — जन् कि [x x] आगदी के क्षेत्र में स्थिति सिता भूमि के टुकड़े के लिये एक से अधिक आवेदक हो, तो ऐसे सभी मामलों में यह नीलाम से मरसे उ ची पोलो लगाने वाले को बेचा जायेगा—

परन्तु शर्त यह है कि—

(१) कलक्टर जिन्ही कारण के लेनखद किये जाने पर किसी चोलो को अस्वीकृत कर सकता है।

() गारा ६६ की उपधारा (१) और (२) के अधीन निरखय की गड वरो पर मर निरिचनल मनिस्ट्रेट की पूर्व स्वीकृति लेनर मौजूदा इमारतों के पडोस की भूमि के टोप छान टुकड़े लिये जा सकेंगे, और

जस धारा के अन्तर्गत नियम की कायगही इस रिषय में राज्य सरकार द्वारा निर्मित नियमा व अन्तर्गत नियमिन की जायगी।

[धारा ६८] घाम भरने के कोठे तथा रुड़ा करकट भरने की भूमि —

(१) राज्य सरकार द्वारा निमत नियमा के अन्तर्गत, इस रिषय में मर डिप्रिचनल आ.व गरी प्रिमियम तथा लगान तथा लगान से मुक्त किसी गाव, कस्बे या शहर के अन्दर नवना लम्बाई चौड़ाई की भूमि चौर घरा के रुड़ा करकट, घुडमाल की लीन और चौपाया व गोबर तथा अन्य फुटे करकट पर खान रखन तथा चौपाया के चारा भरन के लिए आगयन कोठा के काम के लिए निर्धारित की जाय, स सज्जी है—

परन्तु शर्त यह है कि—

(१) जस प्रकार की भूमि का आगयन व रूप भ नहा मागा जायेगा और सभी भूमि तथा न जा सकगा जबकि यह प्राप्त होगी,

() कलक्टर एसा का पुनर्म हल जिना जनिपूरण लिय कर सकेंगा

() यह व्यक्ति जिसको एसी भूमि दी जाय, एसी भूमि का रिनिमय विग्रम रखन करीयक या पहार के रूप में स्थानान्तर नहीं कर सकगा, और

(१) यह व्यक्ति, जिसको एसी भूमि दी जाय इस अधिनियम या जस अधीन निर्मित नियमा के आगिन चारा रिज नय समस्त आगगा का पालन करने के लिये जाय रहगा।

() उपधारा (१) के अन्तर्गत दी गड भूमि सहमीलदार के दर्जे के या उससे उपर व ज व राजस्व अधिकारी का आक्षा के अन्तर्गत पुनर्म हल का जा सकजी है, यदि और तब जब कि जसरा प्राप्त करने वाला जति जम गारा या जस अन्तर्गत निर्मित किसी भी नियम के प्रायमाना का पालन करता है।

टिप्पणी — ठक धारा के अनुसार सरकार उन मुविधा के स्वास्थ्य के लिय कुछ ऐसी भूमि पच लो सकता है जिन के कायस्थक समक। माय हा सरकार अतिष्ठत तोर पर भी सा, व वर न करकट के निवे लोगों को भूमि दे सकता है।

(घ) स्थानीय अधिकारी के अधिकार में आने हुए आबादी क्षेत्र के अन्दर की भूमि अथवा सेक्शन ६२ के अन्तर्गत आरक्षित अथवा विरोध उपयोग के लिए अलग रखी हुई भूमि, और ऐसी भूमि से उत्पन्न होने वाले सभी लाभ तथा अन्य वस्तुएँ जो उम मिट्टी में लगी हुई हों, या स्थाई रूप से उसमें जुड़ी हुई हों, और

(ख) आबादी अथवा 'आबादी क्षेत्र या 'आबादी भूमि का तात्पर्य गाँव, कस्बे अथवा शहर के मनुष्यों से बसे हुए क्षेत्र से है तथा इसमें गाँव, कस्बे, शहर का मोर्चे की स्थिति (Site) सेक्शन ६२ के अन्तर्गत आरक्षित अथवा अलग रखी हुई भूमि जो कि उस आबादी क्षेत्र के विकास के लिए हो और उसके अन्दर का वह भूमि, जो भवन निर्माण आदि के लिए रखी गई हो उसमें भवन निर्माण किया गया हो अथवा नहीं य सभी सम्मिलित हैं।

[धारा १०४] स्थानीय सस्थाओं द्वारा जिन मामलों में राजस्व अधिकारियों के आधिकार प्रयोग में लाये जायेंगे — जहाँ धारा १०४ के अधीन या अन्य किसी रूप में किसी गाँव या कस्बे की आबादी की कोई भूमि अथवा पशुआ को सुपन्न चराई इतु या आबादी के विकास हेतु या किसी अन्य आम या नगरपालिका के उपयोग के लिये अलग से छोड़ी गई नजूल भूमि या भूमि किसी स्थानीय सस्था को सुपुर्द कर दी जाय तो धारा ६७ और ६८ के अन्तर्गत निलामीय अथवा अन्य राजस्व अधिकारी द्वारा प्रयोज्य अधिकार इस विषय में राज्य सरकार द्वारा निमित्त नियमों के अधीन सम्बन्धित स्थानीय सस्था द्वारा एकाधिकार के रूप में प्रयोग में लाये जा सकेंगे।

[धारा १०५] राजस्थान टैनेन्सी अधिनियम मख्या ३ आक १९५५ की धारा ३१ के आधीन आसामियों द्वारा प्राप्त अधिकार अप्रवर्हित — धारा ६५ ६६, ६७ ६८ और १०४ की को भी जान किता भी भाति राजस्थान टैनेन्सी एक्ट १९५५ (राजस्थान एक्ट संख्या ३ सन् १९५५) की धारा ३१ द्वारा आसामियों को जिना किसी चार्ज के गाँव की आबादी के हक्के में रिहायशी मकान के लिये भूमि का कब्जा प्राप्त करने के किये प्रदत्त अधिकारों को न कम करेगा और उन्हें समाप्त ही करेगा।

अध्याय ७

भूमि मापन और अभिलेख संग्रह

(क) सामान्य

[धारा १०६] भूमिमापन अथवा पुनः भूमिमापन — सरकारी गनट में विज्ञप्ति प्रकाशित कर राज्य सरकार निर्देश कर सकती है कि किसी स्थानीय क्षेत्र का भूमि मापन अथवा पुनः भूमिमापन किया जाय और ऐसा प्रत्येक स्थानीय क्षेत्र किसी ऐसी विज्ञप्ति

(२) हम धारा के अधीन, किसी विषय के अनुसार या समय यदि भूलेख अधिकारी यह तय करे कि विफल रहे कि फीनिसा पर अभिप्रेत वाला था या यह बताया जाय कि क्या पैमाने के जेदार था। गलत तरीके से बदल करण दिया गया है और यदि ऐसा अभिप्रेत हमें अनुसार या के तत्काल ३ मास के अंदर प्राप्त किया गया हो तो भूलेख अधिकारी मामूली पद्धताएँ द्वारा यह तय करेगा कि फीनिसा पर हम सम्बन्ध में सर्वात्म्य अधिकार रखता है और उमी के अनुसार सीमा रिट्ट तैयार करेगा।

(ग) नक्शा एवं रसरा

[धारा ११२] नक्शा एवं रसरा बनाना — प्रत्येक स्थानीय क्षेत्र या उसमें किसी खण्ड के धार में जो कि भूमापन या भूलेख कार्य के अन्तर्गत हो, भूलेख अधिकारी इस विषय में राज्य सरकार द्वारा निमित्त नियमा के अनुसार प्रत्येक गांव या उसके किसी भाग के लिये जो कि हमें क्षेत्र में हो या उसके हिस्से में हो एक नक्शा और एक रसरा तैयार करेगा।

(घ) अधिकार अभिलेख

[धारा ११३] अधिकार अभिलेख — (क) भूमापन और लेखा कार्यक्रम या केवल लेखा कार्यक्रम के अधीन किसी स्थानीय क्षेत्र के धार में भूलेख अधिकारी ऐसे क्षेत्र में शामिल किसी गांव या उसमें किसी हिस्से के लिये अधिकार अभिलेख बनानेगा।

[धारा ११४] अधिकार अभिलेख के अंग — अधिकार अभिलेख का निर्माण राज्य सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से किया जायेगा और उसमें निम्नांकित बाने शामिल हानी—

(क) खेवरत — अर्थात् भूमापन और भूलेख कार्य अथवा भूलेख कार्य के प्रभाव क्षेत्र में अस्थित समस्त सम्पत्तिधारका का रजिस्टर जिसमें प्रत्येक सम्पत्ति धारक और उसने सभी हिस्सेदार, उसके कजेदार और उसके अन्तर्गत गैर भूमिदार के रूप में भूमिधारण करने वाले लोगों के, यदि कोई है, हिता की सीमा और उनकी प्रकृति का निर्देश किया जायेगा।

(ख) खतौनी — अर्थात् ऐसे क्षेत्र में भूमि पर खेती करने वाले या किसी अन्य रूप में भूमि पर काना रखने वाले या उसे धारण करने वाले का एक रजिस्टर जिसमें धारा १२१ द्वारा याचित सभी विवरण शामिल किये जायेंगे

(ग) ऐसे क्षेत्र में राजस्व अथवा लगान से मुक्त भूमि को धारण करने वाले लोगों का एक रजिस्टर या

(घ) ऐसे अन्य रजिस्टर जो निर्धारित किये जायें।

[धारा ११५] ऐसी भूमि के सम्बन्ध में वाद आमंत्रित करना निषेध को

प्रामाण्य न हो — (१) जब कि कोई स्थानीय क्षेत्र भूमापन और भूलेख कार्य या केवल भूलेख कार्यक्रम के अधीन हो भूलेख अधिकारी ऐसे क्षेत्र में स्थित ऐसी भूमि की सचि तैयार करेगा जोकि उससे किसी पैघ सम्पत्ति होना प्रतीत न हो और तत्परन्तान् ऐसी भूमि को राज्य की सम्पत्ति के रूप में चिह्नित करने के विचार की सूचना सहित और उसे उस भूमि से सम्बन्धित हिस्सा प्रसार के बाद रखने जान लोगों को निमन्त्रणा न्त हुये एक आम घोषणा प्रकाशित करेगा। ऐसी घोषणा की तारीख के पचास तीन माह की अवधि के भीतर, ऐसे जाल अधिकारी, आधार के निर्देश के सहित अपनी अपनी पेश करेगा।

(२) यदि कोई ऐसी अपनी प्रस्तुत हो तो भूलेख अधिकारी उचित प्रवृत्ताह के जान उसे सरकारी तार पर निर्णय करेगा।

[धारा ११६] अनाधिकृत भूमि को मानवनिर्ज रायों में प्रयुक्त सिंचे जाने की प्रक्रिया — भूलेख अधिकारी यदि धारा ११५ में बताई गई भूमि के लिये कोई जाल प्रस्तुत न किया जाय या यह राज्य सरकार की सम्पत्ति तथ्य नरदी जाय किन्तु आसपास के गांव या गावा के निवासी यह साबित करें कि वे ऐसे निर्णय में पूर्व उस भूमि को चराह अधिका अधि कृषि कार्यों के उपयोग में लेते रहे हैं, ऐसे गांव या गावों को ऐसी भूमि के ऐसे अंश जो कि यह ऐसे कार्य के लिये आवश्यक समझे, सुपुर्ण कर देगा और जेप भूमि को राज्य सरकार की सम्पत्ति घोषित करेगा तथा तत्तुल्य चिह्नित करेगा।

[धारा ११७] ऐसी भूमि पर सीमित अधिकार होने की दशा में कायवाही — यदि धारा ११५ के अधिन जमीन की गद्द घोषणा ग्लिनिवित भूमि में उससे या उस पर हिस्सा ऐसे अधिकार के प्रयोग सिंचे जाने या प्रयोग सिंचे जाने जो कि एकाधिकार का प्रयोग करते नहीं साबित हो जाय तो भूलेख अधिकारी गद्दअधिकारी को ऐसी भूमि के कोई निश्चित ऐसे अंश पर बनने उत्तरी सम्पत्ति को सौंप सकती है अथवा राज्य सरकार का स्वीकृति से अथवा रूप में राजस्थान भूमि अध्यापि अधिनियम १९१३ (राजस्थान गद्द सम्पत्ति) में मन् (६५३) के प्रावधानों के अनुसार ऐसे जाल अधिकारी की क्षतिपूर्ति मंगना है और एका क्षतिपूर्ति ऐसे अर्थोप या प्रयोग के कारण अन्यत्र सभी जानों का समाप्ति पर देगा।

[धारा ११८] निर्धारण एवं सुन्धान्त भूमि का रफाट — भूलेख अधिकारी सुन्धान के तर्ज पर धारा का यह समस्त भूमि की सीमा का निरक्षण अथवा निरक्षण करेगा और उसको उस रूप में लेखन करेगा।

[धारा ११९] किसी गांव की आगामी या निर्धारण — प्रत्येक आगामी गांव के सिंचन में भूलेखाधिकार समझे निवासिया व रहने के लिये तथा उसकी निवास से सम्बन्ध पाया के लिये आरक्षित सिंचे जाने वाले क्षेत्र का निवारण व निष्पाद करेगा और एका क्षेत्र ऐसे गांव की आगामी में समन्वय जायेगा।

टिप्पणा — इस धारा में भूलेख धारिणी व वर्तमान की दृष्टि किया गया है । भूलेख अधिकारी गांव में रहने वाले के लिये रहने तथा पशु पालन के बाड़े बाड़ों में भूमि का व्यवस्था करेगा—ऐसे बाड़ों व लिये भूमि सुरक्षित रहेगा ।

[धारा १२०] ग्राम प निरा — किया प्रपत्र म भूमापन और भूलेख कार्यक्रम अथवा भूलेख कार्यक्रम के अधीन हो । या गांव की पत्र सूचा भूलेख अधिधार लेखार रहेगा जिसमें कि यह निधारित रीति में दिगायेगा—

- (क) उदा धारा में प्रभाषित होन जाला क्षेत्र,
- (ग) अनिश्चित रेनी या क्षेत्र ।
- (ग) इस सम्प्रदाय में निधारित राजस्व या लगान तथा उससे अदा करने वाले व्यक्ति, एवं—
- (घ) ऐसे क्षेत्र जिनका राजस्व और लगान का सम्पूर्ण भाग या कोट अंश जो बमल किया गया हो, छोड़ दिया गया हो सौंपा गया हो, लगान मुक्त किया गया हो या उस विषय म समझौता किया गया हो तो उससे सम्बद्ध शता पत्र प्राधिकार का उल्लेख ।

[धारा १२१] खतौनी म दर्ज रिये जाने वाले निरक्षण — (१) धारा ११४ में एण्ड (ए) द्वारा नियत किसी भूमि के चोटने वाले अथवा अन्यथा प्रकार में उसको धारण करने या उसमें अधिग्राम करने वाले लोगों के रजिस्टर में प्रत्येक आसामी के लिये निम्नांकित निरक्षण दन किये जायेंगे, अर्थात्—

- (क) राजस्थान ^१ [x x x x x x x]
दिन-सौ अधिनियम १९५४ (राजस्थान कानून ३ आफ १९५४) के प्रावधानों के अनुसार निरूपित उससे भू प्रपत्र प्रणाली की प्रकृति एवं श्रेणी एवं ^२ [या अन्य किसी दूसरे कानून या प्रावधान के अनुसार जो उस वक्त राज्य भर में या किसी हिस्से म लागू हो],
- (ग) खतौनी की सीमा की अपाप्ति हेतु उसके द्वारा प्रस्तुत प्रतिफल की रकम यदि कोई हो,
- (ग) खतौनी के पत्र की तारीख और स्थानांतरण यदि कोई हो जो कि इसके द्वारा किये हा, उनसे सम्बद्ध निरक्षणों सहित,
- (घ) उसकी ज़ोत में एवं तत्सम्बन्धित क्षेत्र में सम्मिलित प्रत्येक खेत का खसरा नम्बर,
- (ङ) जपिन लगान जो उससे द्वारा दय हो,
- (च) भू प्रपत्र प्रणाली की कोई अन्य शर्त जो चाहे लिखित पत्रे म सम्मिलित हो अथवा न हो, और

(६) खानगार आसामियों के अलावा व्यक्ति या के मामले में उस भूमि के उससे अधिपत्य होने का समय २ वर्षों में और,

(७) ऐसे अव प्रकरण जो समय समय निवारित किये जाय ।

(८) ऐसे भूमिधारियों का जो कि [x x x x x x x

राजस्थान टैनेन्सी अधिनियम १९३४ (राजस्थान एक्ट ३ आफ १९३४) "या अथ किसी दूसरे कानून या प्रावधान के अनुसार जो उस वक्त राज्य मंत्र या किसी हिस्से में लाहू हो] की प्रणाली के तौर सुन कानून के लिये कोई भूमि धारण किये हुये हो रजिस्टर में प्लेन्स किया जायेगा और ऐसी भूमि के सम्बन्ध में उन वर्षों का निर्देश दिया जायेगा जिनमें वह भूमि इस प्रकार धारण की गई होगी ।

टिप्पणी — राजस्थान एक्ट नं २ आफ १९३८ क सख्त ४ की प्रथम सूचि द्वारा जो राजस्थान एक्ट सख्त ४-घ विधिवत निम्न १३-१५ के प्रकाशित हुये (१) (२) लीपित किया गया व (२) (४) सम्मिलित किया गया ।

[धारा १००] इन्ट्रानों का सत्यापन और भगदों का निर्णय — मन्त्र अधिनियम अधिलेख की समय विवाद रहित इन्ट्रानों में रुचि रखने वाले फरीषेन सत्यापन करों पर ऐसे इन्ट्रानों के सम्बन्ध में समस्त सब बाह्य के मूलेख अधिकारी द्वारा समर्थित हों अथवा किसी अधिलेख रखने वाले पक्ष के आवेदनपत्र पर उठाये गये हों, मूलेख अधिकारी द्वारा धारा १२ और १३ के प्रावधानों के अनुसार निपटारा किया जायेगा ।

[धारा १०३] आसामी क वर्ग का निर्धारण — (१) जिस आसामी के वर्ग अथवा भूमि प्रणाली में सम्मिलित मामले में मूलेख अधिकारी राजस्थान टैनेन्सी अधिनियम, १९३४ में स्थापित सिद्धांतों पर निर्णय करेगा ।

(२) यदि के निपटारे में इस धारा के अधीन, मूलेख अधिकारी ऐसे जाने में काम लगे जो इस अधिनियम के अन्तर्गत नियत किया जाय ।

[धारा १०४] देय राजस्व अथवा लगान के सम्बद्ध विवाद — मूलेख

अधिकारी किमा राजस्व या लगान में सम्बद्ध किसी विवाद में, यदि को तय नहीं करेगा किन्तु अधिकार पत्रिका में वर्ष में देय लगान या राजस्व के रूप में पूरे वर्ष में देय राजस्व या लगान का रकबा करेगा किन्तु यह है कि यह ऐसे अधिनियम अथवा राजस्थान टैनेन्सी अधिनियम १९३४ के अन्तर्गत किमा सविदा, किसी या आसामी द्वारा कम या ज्यादा न कर दिया गया हो ।

[धारा १०५] अधिकार अधिलेख की प्रविष्टियों के विषय में उठाये गये भगदों का निपटारा — (१) अधिकार अधिलेख की प्रविष्टियाँ के सम्बद्ध में उठाये गये अन्य समस्त विवाद अधिपत्य के आधार पर तय किये जायेंगे ।

(क) वे इस प्रकार के गांवा, सम्पत्तियों या राजों पर उचित सीमा चिह्न लगायें
अथवा

(ख) उन पर उचित रूप से उनाये गये समस्त सीमा चिह्न के ऐसे रूप में और
ऐसी सामग्री से मरम्मत कराये या नया पुनर्निर्माण कराव जोकि इस
अवस्था में निर्धारित किये जायें।

(२) यदि ऐसे आदेश या पालन उसके जारी होने के बाद अन्दर मया ३० दिन
नहीं किया जाय तो ऐसा अधिकारी ऐसे सीमा चिह्न को धनमाने नही मरम्मत करवाने
अथवा उनका पुनर्निर्माण करवाने की कार्यवाही कर सकेगा और ऐसा अधिकारी
सम्बन्धित मूधारिया में ऐसे अनुपात में, जो वह उचित समझे खर्च किये गये काम
पमूल करेगा।

(३) राजों की सीमा सम्बन्धी मामलों में, जहाँ सीमा सम्बन्ध कोई विवाद नहीं,
है, वहाँ उपधारा (१) व (२) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा उस दरखास्त के प्रस्तुत होने पर
या अथवा भा कार्यवाही की जावेगी।

[धारा १३०] सीमा चिह्नों को नष्ट करने या हटाने पर शास्ति —
क्रिया ऐसे व्यक्ति के सम्बन्ध में जिसने द्वारा इच्छापूर्वक किसी भूमापन या सीमा के
चिह्न को हटाया जाना, हानि पहुँचाना या नष्ट किया जाना सिद्ध हो जाय तो भूलेख
अधिकारी यह आदेश दे सकता है कि वह किसी एक प्रत्यक्ष हटायें, हानि पहुँचाये या
मिटायें गये चिह्न के तार में अधिक से अधिक ५०) तक की शक्ति, विनयी कि
उपनिर्दिष्ट चिह्न के पुनर्निर्माण हेतु अथवा सूचना देने राज को पारितोषिक देने के लिये
अनिवार्य हो। भूलेख अधिकारी ऐसे निशान या मरम्मत करावेगा और तत्सम्बन्धी खर्च
आसपास के गांवा, सम्पत्तियाँ या राजों के मधारका से जैसी भी अवस्था हो, पमूल कर
लेगा जैसा भा उचित समझे यदि ऐसी रकम प्राप्त नहीं की जा सके या ऐसा होना नहीं
हुंदा जा सके।

[धारा १३१] मानचित्र खमरे या प्रतय — भूलेख अधिकारी, भूमापन और
भूलेख मंत्र के कार्य की समाप्ति पर इस विषय में राज्य सरकार द्वारा निर्मित नियमों के
अनुसार, सुरक्षा करेगा और वह उनमें शक्ति अथवा नीचर के अधिकारों में विनयी कि
राज्य सरकार नियंत्रण कर, सभी परिवर्तन को कि सिमा गांव के हिस्से, सम्पत्ति या
राजों में होने वाले परिवर्तनों को लेन उठ करेगा और ऐसे मानचित्र सतर में सीमा में
पताई यह भूला या सुधार करेगा।

टिप्पणी,—इस धारा के अनुसार मानचित्र खमरे के निर्माण के साथ ही उसकी मूकों का
कार निम्न स्थान दिया जावेगा कराकि य एवं हस्तक्षेप हुआ है।

(च) शक्ति पत्रिका

[धारा १३२] शक्ति पत्रिका — (१) भूलेख अधिकारी अधिकार अभिलेख की
सुरक्षा रखेगा तथा उसके लिए शक्ति रूप में अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अवधि

में धारा ११४ एवं १२० में परिभाषित परिभाषा का मन्त्र धन या मंगोपनि धन, जैसी भी अवस्था हो, तैयार करेगा और उस प्रकार तैयार किया गया रजिस्टर वार्षिक पत्रिका कहलायेगा।

(२) निधारित ढंग से होने वाला सभा परियोजना एवं अभिलेखित अधिनियम या हितों पर प्रभाव डालने वाली वाक्यांशिका का अभिलेखन वार्षिक पत्रिका में करने का कर्तव्य भूल जाधिकारी का होगा।

[धारा १३३] उत्तराधिकारी तथा कर्तव्य क हस्तान्तरण की रिपोर्ट —

(१) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गए नियमों द्वारा तदन्तर विनिर्मित वार्षिक रजिस्टर में प्रविष्ट की जाने योग्य भूमि या उसका लाभ में किसी सम्पत्ति का विरासत, हस्तान्तरण या अन्य रीति से किसी भी प्रकार का अधिकार या हित या कर्तव्य प्राप्त करने वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि यह सम्बन्ध तथ्य का ज्ञान प्राप्त के पट्टेदारी को प्राप्त तथा उस सम्बन्ध का रिपोर्ट उस तहसील के तहसीलदार को दूँ दूँ जिसमें कि यह भूमि स्थित हो चाहे ऐसी रिपोर्ट उस तहसील के तहसीलदार को दूँ निम्न कि यह भूमि स्थित हो, चाहे ऐसी रिपोर्ट ग्राम पट्टेदारी के माफ़न या भूलेख निरीक्षक के माफ़न दी जाय किन्तु ऐसे कर्तव्य की प्राप्ति की तारीख के बाद तीन माह की अवधि के भीतर ऐसी रिपोर्ट दे दी जानी चाहिये।

(२) यदि ऐसा व्यक्ति अव्यक्त है अथवा अन्य रीति से अव्यक्त है तो उसका संरक्षक या उसकी सम्पत्ति की देख रक्ष करने वाला व्यक्ति ऐसी रिपोर्ट दगा।

[धारा १३४] रिपोर्ट देने में लापरवाही करने पर दण्ड — धारा १३३ द्वारा याचित रिपोर्ट प्रस्तुत करने में लापरवाही करने वाले पर अधिक से अधिक १०) २० तक का दण्ड किया जा सकता है।

[धारा १३५] रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर कार्यवाही — (१) ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर अधिकाधिक प्रणाली से इस विषय में जानकारी प्राप्त होने पर तहसीलदार आवश्यक जाच पड़ताल करेगा और विज्ञानमान मामला में यदि विरासत हस्तान्तरण या अन्य रूप से अधिकार होना प्रतीत हो तो उसका अभिलेखन वार्षिक रजिस्ट्रारों में करेगा।

(२) यदि हस्तांतरण, विरासत या अन्य अधिकार विवाद प्रस्तुत हो तो इस अधिनियम या वनमान में प्रभावशील किसी अन्य विधि के अन्तर्गत सामर्थ्य प्राप्त होने पर तहसीलदार विधि के अनुसार ऐसे मामले तय करेगा और यदि इस सम्बन्ध में क्षमता प्राप्त न हो तो ऐसे मामले को सक्षम अधिकारी के पास निष्पत्ति के लिए भेजेगा।

[धारा १३६] विवादों पर निर्णय — दूय लगान या राश्रवण से सम्बन्धित या किसी कृषक के भूमि अधिकारों अथवा धन से सम्बन्धित या वार्षिक रजिस्टर की प्रविष्टियों के विषय में उठाये गये सभी विवाद धारा १२३ या धारा १४ या धारा १२५ के अन्तर्गत अवस्था के अनुसार निर्णय होंगे।

[धारा १३७] सम्पत्तियों की विरामत — इस अधिनियम में उल्लिखित किसी भी बात के होने पर भी किसी सम्पत्ति का उत्तराधिकार या हस्तांतरण सम्पत्ति वाले क्षेत्र में प्रचलित किसी सामानिक रिवाज या प्रथा अथवा प्रमाणशील विधि के अनुसार निरूपण किया जायेगा और उसके द्वारा शासित एवं नियमित होगा तथा ऐसा कानून सामानिक रिवाज या प्रथा धारा २६३ के प्रावधानों के रहते हुये भी, उपरोक्त प्रयोजन के लिये प्रमाणशील रहेंगे।

टिप्पणी — यह धारा स्पष्ट करता है कि भूमि बात क्षेत्र में प्रभावशील विधियाँ विरामत तथा भूमि के हस्तान्तरण के बारे में प्रभावशील रहने और उनके प्रावधानों के अनुसार ही उनके अन्तर्गत के विवाद निर्वाह होंगे यद्यपि धारा २६३ के अंतर्गत कुछ विधियाँ रह कर दी गई हैं।

(क) विविध

[धारा १३८] अभिलेखों का निरीक्षण — समस्त भूमापन मानचित्र खसरे व रजिस्टर जो इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाये जायेंगे, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित समय, स्थान एवं नियमनामा पर जनता के निरीक्षण के लिए सदैव निशुल्क खुले रहेंगे।

[धारा १३९] प्रतिष्ठियों की नकल — इस अध्याय के अन्तर्गत व्यवस्थित रजिस्ट्रार तथा अभिलेखा की प्रतिष्ठियों की नकल राज्य सरकार द्वारा समय समय पर नियमित प्रतिलिपि शुल्क के चुकान पर, जन कर्मा आवश्यक हो तैयार करवा और ऐसी प्रतिलिपियाँ जो निर्धारित रीति से प्रमाणित किया जायेगा।

[धारा १४०] प्रतिष्ठियों के नियम में संशोधन — अधिकार आभरण में समाविष्ट समस्त प्रतिष्ठियाँ सत्य मानी जायेंगी किन्तु शर्त यह है कि उन्हें अन्यथा प्रमाणित न कर दिया गया हो।

[१४० क] मुदरास्त के इन्टरानत सम्बन्धित विवादोस्त प्रतियाँ — धारा १२४ व १३६ में निर्दिष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी जागीरदार द्वारा घास के आरक्षण हेतु रस्ता हट और चराट के हेतु दी हुई, जोड़ अथवा रीढ़ की भूमि के विषय में, घास काटे जा चुकने के पश्चात् अथवा घास हटाने या उसके पतले जावे वह भूमि चराट की फीस लेकर ली हुई हो अथवा बिना ऐसी फीस के दी हुई हो, मुदरास्त के विषय में, हका के रकार्ड में की गई इन्टरान की शुद्धि अथवा अशुद्धि के विषय में यदि कोई विवाद उत्पन्न हो जावे, तो ऐसी विवादोस्त भूमि का निर्णय मुदरास्त की तमीन के अधिकरण (Possession) पर आधारित होगा और यह मुदरास्त का भूमि के आगटन व विभागीकरण (Demarcation) कानून के प्रावधानों के अनुसार होगा, जो उस समय लागू होंगे।

किन्तु शर्त यह है कि जो भूमि इन्टरान पर आपत्ति उत्पन्न नहीं जा सकेगी यदि मुदरास्त का मुल क्षेत्र जो जागीरदार के कब्जे में हो कम से कम उस परिणाम से दुगुने

से अधिनियम हो जो भूराजस्थान टाँगेमा एक्ट १९५४ (राजस्थान अधिनियम ३, १९५४) की धारा १८० की उपधारा (१) यलान (अ) के अन्तर्गत निश्चित अथवा नियत की गई हो।

(२) सुदयारण सम्बन्धी कानून जो एका पक्ष पर रखा गया है तथा जो उसी सुदयारण हेतु उपधारा (१) के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया था या जो भी आदेशों पर अथवा कार्यवाही, राजस्थान भू राजस्व (संशोधन) अधिनियम १९५६ के धनन से पहले अथवा उक्त कानून बनने के ५ वर्ष के अन्दर प्रस्तुत की जानी चाहिए और उक्त अधिनियम के अधीन नहीं।

[धारा १४१] निर्णय रास्ते न्यायालयों से मान्य होंगे — धारा १०४ का उपधारा (३) प प्रावधानों के अन्तर्गत इस अध्याय के अधीन विवादों में दिये गये सभी निर्णय उस समय तक विवाद के विषय के बारे में सभी राजस्व न्यायालयों को मान्य होंगे जब तक कि ऐसा विवाद आसामी द्वारा दायर लगान अथवा राजस्व के सम्बन्ध में न होगा।

अध्याय ७क

आवादी क्षेत्रों का सर्वेक्षण (पंचमांश)

[धारा १४१का] परिभाषाएँ — इस अध्याय के प्रयोजनाथ, जब तक विषय या सदर्भ द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) "आवादी क्षेत्र" का अर्थ यही होगा जो उसे धारा १०३ के खण्ड (ख) द्वारा दिया गया है

(ख) भूमि का अर्थ यही होगा जो उसे धारा १०३ के खण्ड (क) द्वारा दिया गया है,

(ग) 'न्यायी' में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे—

(१) वह व्यक्ति जिसका किसी भूमि या भू-गुहादि में स्थायी हित हो या

(२) ऐसे व्यक्ति का एजेंट या उसकी ओर से प्रबंधक (मैनेजर) या

(३) ऐसे व्यक्ति का न्यायी या

(४) ऐसा निगम जिसका निमित्त कोई भूमि या भू-गुहादि तत्समय निहित है या

(५) किसी भूमि या भू-गुहादि का तत्समय अधिवासी

(घ) 'भू-गुहादि' से तात्पर्य इस अध्याय के अधीन तैयार किये गये किसी अभिलेख में या किसी अन्य पूर्व के मौजूद अभिलेख में इस प्रकार उल्लिखित किसी भूमि या भवन से है।

(ङ) 'सर्वेक्षण' में सीमापारों का अभिमान तथा सर्वेक्षण की प्राथमिक या इससे सम्बन्धित समस्त अन्य कार्यवाहियाँ सम्मिलित हैं।

[धारा १४१गा] मर्जण की आता देने की शक्ति — (१) राज्य सरकार न कमा न उचित समझे सरकारी राप्प में विज्ञप्ति द्वारा आता देने सकेगी कि राज्य के भीतर किसी भी आगानी क्षेत्र का या ऐसी आगानी क्षेत्र के किसी भाग का सर्वेक्षण किया जाय और तदुपरान्त प्रत्येक ऐसी आगानी क्षेत्र या इसका भाग मर्जणाधीन समझा जायगा।

(२) राज्य सरकार उसी विज्ञप्ति द्वारा या तदुपरान्त विज्ञप्ति द्वारा निम्न ले सकेगी कि ऐसा स्थानाव प्राधिकारी (Local authority) जिसका ऐसे आगानी क्षेत्र का समके भाग पर अधिनियम २२ हो, इस प्रकार आज्ञा दिए गए सर्वेक्षण का इन्चार्ज होगा।

(३) ऐसे सर्वेक्षण का इन्चार्ज स्थानीय प्राधिकारी उसके सम्बन्ध में, इस अध्याय के अधीन या अन्यथा ऐसी शक्तियों का प्रयोग करगा और ऐसे कर्तव्यों का पालन करगा जो उपधारा (२) में निर्दिष्ट विज्ञप्ति में निवारित किए जाय।

(४) जहां उपधारा (१) के अधीन आज्ञा देने गये किसी सर्वेक्षण के लिए किसी स्थानीय प्राधिकारी को इन्चार्ज होने का निर्देश नहीं दिया गया हो, तो विने का फलस्वरूप ऐसे सर्वेक्षण का इन्चार्ज होगा।

(५) उपधारा (१) के अधीन आज्ञा दिया गया सर्वेक्षण ऐसे अधिकारी द्वारा जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जान वाले अनिरीक्त मू-अभिनय अधिकारी (Additional Land Record officer) के वर्ग से नाचे का नहीं होगा, निवारित रीति से किया जायगा और ऐसा अधिकारी तदुपरान्त मर्जण का संचालन करने वाला अधिकारी कहा जायगा।

(६) राज्य सरकार सर्वेक्षण का संचालन करने हेतु अपनी सहायक अभिनेत्र अधिकारी (Assistant Records officer), और अन्य अधिकारी तथा कर्मचारी नियुक्त कर सकगा जिन्हें वह उपधारा (५) के अधीन नियुक्त अधिकारी का सहायता के लिए आवश्यक समझे।

(७) उपधारा (५) के अधीन नियुक्त प्रत्येक अधिकारी या कर्मचारी ऐसी शक्तियां का प्रयोग करगा तथा इन कर्तव्यों का पालन करगा जो निवारित किये जाय या जो सर्वेक्षण का संचालन करने वाले अधिकारी द्वारा उसे सुपुर्ण की जाय।

[धारा १४१गा] भूमि में प्रवेश — सर्वेक्षण का संचालन करने वाले अधिकारी को इस अध्याय के प्रयोजना के लिए सर्वेक्षणाधीन आगानी क्षेत्र या उसके भाग के अन्दर किसी भूमि या भू-गुहादि में, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के बीच के घण्टा में, स्वयं या सर्वेक्षण कार्य के लिए नियुक्त किसी अन्य अधिकारी या कर्मचारी द्वारा प्रवेश करने की शक्ति होगी और (घट) प्रवेश के कारण या ऐसी भूमि अथवा भू-गुहादि में, इस अध्याय के प्रावधानों का अनुसरण न किये गये किसी कार्य के कारण उसके विरुद्ध कोई भी वैधिक कार्यवाही नहीं की जायगी।

परन्तु जहाँ यह है कि ऐसी निमा भू भूमि या भू-गृहादि म जहाँ तत्कालीन को नियमित कर रहा हो उस समय तक इस प्रकार प्रवेश नहीं किया जायगा जब तक कि उस अभिवासी की स्थायित्व प्राप्त नहीं कर ला गई हो अथवा उक्त अभिवासी को इस प्रकार प्रवेश के आशय का एक नोटिस - नोटिस पूर्व नहीं द दिया गया हो ।

[धारा १४१ घा] सर्वेक्षण का नोटिस पहिले दिया जाना —सर्वेक्षण के प्रयोजना के लिए किसी भूमि या भू-गृहादि म प्रवेश करने के पूरा सर्वेक्षण का संचालन करने वाला अधिकारी सर्वेक्षण का जान वाली भूमि या भू-गृहादि के स्वामी पर और एक ही सीमा वाली भूमि या भू-गृहादि के स्वामियों पर अपने हस्ताक्षरों के लिए नोटिस तामील करायगा जिसमें उनसे भूमि या भू-गृहादि म उसने समझ या ऐसे अधिकारी के समझ जो उससे द्वारा इस और प्राधिकृत किया गया हो निर्धारित अवधि (चौ ऐसी नोटिस तामील विय जान के परचात् तीन दिन से कम नहीं होगी) के भीतर २ सीमाओं को बतलाने के प्रयोजनाय और ऐसी सूचना देने के लिए जो इस अवधि के प्रयोजना के लिए आवश्यक हो, या तो वैयक्तिक रूप से या अपने एजेंट द्वारा उपस्थित होने के लिए कहा जायगा और प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जिस पर ऐसा नोटिस तामील किया जायगा वैयक्तिक रूप से उपस्थित होने जैसा कि नोटिस द्वारा अपेक्षित है, और कोई भी ऐसी सूचना देने के लिए जो अपेक्षित है और कहा तक वह उसे देने के योग्य है बाध्य होगा ।

[धारा १४१ डा] धारा १४१ घा के अधीन नोटिस तामील किये जाने के परचात् सर्वेक्षण-कार्य का प्रारम्भ किया जाना —धारा १४१ घा के अधीन जारी किये गये नोटिस की उचित तामील होने के परचात्—

(१) सर्वेक्षण का संचालन करने वाला अधिकारी अथवा उसके द्वारा इस और प्राधिकृत कोई भी अन्य अधिकारी या कर्मचारी सर्वेक्षण का कार्य प्रारम्भ कर सकेगा यदि वह व्यक्ति तिन पर ऐसा नोटिस तामील किया गया है, उपस्थित हो या न हो और

(२) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो इस प्रकार उपस्थित होने में विरल रहना है या जो इस प्रकार उपस्थित नहीं है, सर्वेक्षण के परिणामों द्वारा उस रीति से तथा उसी सीमा तक बाध्य होगा मानों सर्वेक्षण उसकी उपस्थिति में किया गया था ।

[धारा १४१ चा] सर्वेक्षण का नक्शा तथा रजिस्टर —(१) सर्वेक्षण का संचालन करने वाला अधिकारी, सर्वेक्षणाधीन आनादी क्षेत्र या उसके भाग का एक नक्शा तैयार करेगा ।

(२) ऐसे आनादी क्षेत्र या उसके भाग के अन्दर की भूमियों और भू-गृहादि को नक्शे में निर्धारित रीति में प्रत्येक प्रत्येक दिखलाया जायगा ।

(३) भूमि के प्रत्येक टुकड़े और प्रत्येक ऐसे भू-गृहादि को जो नक्शे में प्रत्येक दिखलाया गया है संकेतात्मक (Indicative) सर्वेक्षण सख्या दी जायगी ।

(१) संचालन का संचालन करने वाला अधिकारी सर्वेक्षणधीन आगामी २२ या उसके भाग के लिये, भी उसमें स्थित ऐसी समस्त भूमियों तथा भू-गृहादि का, निम्न संचालन किया जा चुका है, एक रजिस्टर तैयार करेगा।

(५) उपधारा (५) के अधीन तैयार किये गये रजिस्टर में, उपधारा (३) के अधीन दत्त प्रत्येक सर्वेक्षणधीन संचालन के सम्बन्ध में, उक्त व्यक्ति या व्यक्तियों के नामों के संचालन के समय उसके स्वामी के रूप में उपस्थित हुआ हो और ऐसे अधिनियम जो निम्नलिखित किये जायें किये जायेंगे।

[धारा १४१] सीमा चिन्हों का लगाया जाना —सर्वेक्षण का संचालन करने वाला अधिकारी, किसी भी समय, किसी भी भूमि पर, जिसका दस अंशों के अधीन सर्वेक्षण किया जाता है या किया गया है, ऐसे पन्ना तथा ऐसी सच्चा पत्र रीति में, जिसे वह सर्वेक्षण के प्रयोजना के लिए पर्याप्त होना निर्धारित कर, अस्थायी या स्थायी सीमा चिह्न लगायेगा।

परन्तु शर्त यह है कि सीमा को स्थायी भवन दीवार या भांडी द्वारा परिभाषित किये जाने की दशा में, कोई स्थायी सीमा चिह्न नहीं लगाये जायेंगे।

[धारा १४१] जो प्रस्थानी सीमा चिन्हों का मधारण —(१) जब धारा १२१ का के अधीन कोई अस्थायी सीमा चिह्न लगाये गये हों तो सर्वेक्षण का संचालन करने वाला अधिकारी उस भूमि या भू-गृहादि निम्न पर या निम्नसे मिलान केमी सीमा चिह्न स्थित है के स्वामी पर उसके दस्तावेजों में लिखित में एक नोटिस तामील करवायेगा निम्नमें उसमें जब तक सर्वेक्षण कार्य पूर्ण नहीं हो जाय, ऐसे सीमा चिह्न का मधारण तथा सम्मन करने की अपेक्षा की जायगी।

(२) यदि ऐसा स्वामी ऐसे नोटिस की तामील नहीं करे तो सर्वेक्षण का संचालन करने वाला अधिकारी, सीमा चिह्न का सम्मन करवा सकेगा और इस कार्य के करने पर हुआ खर्च ऐसे स्वामी में राजस्व की रकमा के रूप में समूली योग्य होगा।

[धारा १४१] भा [सीमाओं के सम्बन्ध में विचार] —(१) इस अध्याय के अधीन सर्वेक्षण कार्य किये जाने के दौरान यदि सर्वेक्षण की जाने वाली किसी भूमि या भू-गृहादि की सीमाओं के सम्बन्ध में किसी विवाद का मौजूद होना पाया जाय तो ऐसे विवाद में निम्नलिखित हु इस विषय में प्राविष्ट किसी सहायक अभिलेख अधिकारी (Assistant Record Officer) द्वारा जांच का जायगी।

(२) उक्त सहायक अभिलेख अधिकारी, अपने दस्तावेजों में लिखित में एक नोटिस सम्बन्धित पत्र पर तामील करवायेगा जिसमें उससे उसके समस्त दायें या किसी प्राधिकृत प्लेट द्वारा किसी निश्चित दिन को स्थित होने और विवाद पर भूमि या भू-गृहादि पर अधिकार होने का समूह प्रमाण करने के लिए कहा जायगा।

प्रस्तुत साक्ष्य गृहण करेगा, ऐसी साक्ष्य पर प्रभाव पर शिन्तन करेगा तथा सभी और साक्ष्य लगा जिस यह आवश्यक समझे और विवाद प्रस्तुत भूमि या भू-शुद्धि के पत्र पर अधिार का, एव पत्रा म से किसी भी पत्र पर स्वयं (Claim) के गुणुदावा का निर्देश (reference) दिए बिना, यह निष्णय करेगा कि कौन सा पत्र वा सहायक के समय, उक्त भूमि या भू-शुद्धि पर पत्रा है।

(२) उपरान्त पात्र के प्रमाणनाथ, सहायक अभिलेख अधिकारी का साक्ष्य का हुलाने और उतरी परिधत दाने के लिए बाध्य करन, और न्याय ताराज से तथा उसी रीति में जसा कि सिविल शास्त्रीय कोर्ट, १९०८ (सेट्टल एक्ट सन् १९०८) के अधिन, न्यायालय के किसी गुपदम के लिए जाराहन है दस्तावेज को प्रस्तुत करन के लिए बाध्य करन की शक्ति होगी।

(३) जाच पूरी हो जाने के परन्तु सहायक अभिलेख अधिकारी, लिखित में ऐसा आज्ञा पारित करेगा जिसमें यह पट्ट रूप से विवाद का विषय बतलायगा और उस पर अपना निर्णय तथा ऐसे निष्णय के लिए कारणों को अभिलिखित करेगा।

[धारा १४१ भा] फलफट्टर को अपील की जाना — धारा १४१ भा के अधिन सहायक अभिलेख अधिकारी द्वारा पारित की गई आज्ञा के विरुद्ध अपील फलफट्टर के पास का जायगी और यह ऐसी आज्ञा की तारीख से ३० दिन के भीतर की जा सकेगा।

[धारा १४१ टा] पचाट को निष्णय हतु भेजने की शक्ति — (१) विवाद प्रस्तुत सोमाया के प्रत्येक मामले में, जाच करने के लिए प्राधिकृत सहायक अभिलेख अधिकारी, पत्रा द्वारा लिखित में आज्ञादन प्रस्तुत करने पर विवाद को एक या उससे अधिक पक्षों (arbitrators) जो क्रमशः पक्षपारा द्वारा मनोनात किये गये हों, के पास निष्णय हतु भेज सकेगा और पक्ष निर्णय देने के लिए ऐसा समय निश्चित करेगा और उनकी अधि के लिए समय को पढ़ावगा नितना उचित हो —

परन्तु शर्त यह है कि यदि सहायक अभिलेख अधिकारी को यह प्रतीत हो कि राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी, ऐसे किसी विवाद में इतने रयते हैं तो यह इस प्रकार निर्देश (reference) करन से मना कर देगा।

(२) उप धारा (१) के अधीन किये गए प्रत्येक निर्देश (reference) और तदन्तगन मनोनीत किये गये प्रत्येक पंच पर आरबिट्रेशन एक्ट, १९४० (सेट्टल एक्ट १० सन् १९४०) के प्राधान, जहा तक सम्भव हो सकेगा लागू होंगे।

[धारा १४१ टा] सचरण से सम्बन्धित दस्तावेजों को, सचरण अधिकारी या इन्वार्न अधिकारी के पास भेजा जाना — (१) सर्वेक्षणधीन आजादी क्षेत्र या उसके किसी भाग का सचरण पूरा हो जाने के परचातु सर्वेक्षण का सचालन करने वाला अधिकारी, ऐसे सर्वेक्षण से सम्बन्धित समस्त नक्शे रजिस्टर और अन्य दस्तावेज, उसके इच्छा अधिकारी या प्राधिकारी को भेजेगा।

(२) ऐसे नकशे, रजिस्टर तथा अन्य दस्तावेजों की प्राप्ति की सूचना ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा सरकारी राजपत्र में विज्ञापित की जायगी और कोई भी व्यक्ति जो सर्वेक्षण में हित रखना हो, ऐसे विज्ञापित की तारीख से दो मास के भीतर २ विसी भी समय, ऐसे नक्शा, रजिस्टरों तथा अन्य दस्तावेजों का निशुल्क निरीक्षण कर सकेगा।

(३) यदि उक्त अधिध के भीतर सर्वेक्षण के सम्बन्ध में, सर्वेक्षण के इन्चार्ज अधिकारी या प्राधिकारी के पास कोई आपत्ति प्रस्तुत की गई है तो ऐसी आपत्ति पर नियम उस अधिकारी द्वारा किया जायगा जिसे राज्य सरकार इस विषय में नियुक्त कर या जहाँ कोई स्थानीय प्राधिकारी सर्वेक्षण का इन्चार्ज हो तो, ऐसे स्थानीय प्राधिकारी द्वारा राज्य सरकार की स्वीकृति से, निर्णय किया जायगा।

(४) उप धारा (३) के अधीन प्रस्तुत समस्त आपत्तियों पर नियम लिए जाने के परवाना सर्वेक्षण का इन्चार्ज अधिकारी या प्राधिकारी, यदि आवश्यक हो, सर्वेक्षण से सम्बन्धित नकशों, रजिस्टरों तथा अन्य दस्तावेजों को, ऐसे निर्णय के अनुसार सही करवायेगा और समस्त कागजात अपनी मिफारिन्ग के सहित राज्य सरकार के पास सर्वेक्षण की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत कर देगा।

(५) यदि राज्य सरकार सर्वेक्षण की स्वीकृति दे देती है तो ऐसी स्वीकृति सरकारी राजपत्र में विज्ञापित की जायगी।

[धारा १४१ टा] नकशों तथा रजिस्टरों का मधारण — (१) धारा १४१अ का उप धारा (५) के अधीन राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत सर्वेक्षण से सम्बन्धित समस्त नक्शे रजिस्टर और अन्य दस्तावेज सर्वेक्षण के इन्चार्ज अधिकारी या प्राधिकारी के काया लय में रखा जायेगा।

(२) समस्त ऐसे नक्शे, रजिस्टर तथा अन्य दस्तावेज ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा निश्चित रीति में संगठित किए जायेंगे।

(३) ऐसा अधिकारी या प्राधिकारी ऐसे नकशों में ऐसे अधिकारी द्वारा जो इस ओर राज्य सरकार द्वारा या समझौता स्वीकृति से नियुक्त किया जाय, नियमित रीति में और नियमित समयांतरा पर संपादन करवायगा और ऐसे रजिस्टरों में का गड़ प्रविष्टियाँ को सही करवायगा।

परन्तु तब यह है कि किसी भा व्यक्ति को, ऐसे सरोवन या शुद्धि (Correction) के प्रयोजनार्थ ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी को जिसे भूमि या भू-मृदाओं में उसके द्वारा हित का अक्षाति के सम्बन्ध में नोटिस देने के लिए नहीं कहा जायगा।

(४) किसी नक्शे में सरोवन करने या किसी रजिस्टर में प्रविष्टियाँ को सही करने के, प्रयोजनार्थ उप धारा (३) के अधीन नियुक्त अधिकारी, एसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो नियमित की जायें।

प्राधिकारी को सर्वेक्षण पाय प्राप्त हो जाय वे परन्तु ऐसे समय के भीतर तथा ऐसी सीमा तक एवं ऐसी दर से तथा ऐसी शर्तों में जिसे राज्य सरकार निर्धारित कर, सर्वेक्षण शुल्क के भुगतान करन का भागी होगा और जोड़ भी सर्वेक्षण शुल्क जिसका भुगतान नहीं किया गया है, भू राजस्व की वसूली के रूप में वसूली योग्य होगा

परन्तु शत यह है कि—

(क) सर्वेक्षणाधीन आवादी क्षेत्र या उसके भाग की भूमिया तथा भू-गृहादि के स्वामिया से वसूल किए जाने वाले सर्वेक्षण शुल्क का कुल राशि, सर्वेक्षण के कुल व्यय के १/३ से अधिक नहीं होगी, और

(ख) निम्नलिखित द्वारा जोड़ भी सर्वेक्षण शुल्क भुगतान योग्य नहीं होगा —

[१] राज्य सरकार द्वारा या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या

[२] सर्वेक्षणाधीन आवादी क्षेत्र या उसके भाग की हिस्सा ऐसी भूमि या भू-गृहादि के सम्बन्ध में जो ऐसे क्षेत्र या मूल्य में ऐसी सीमाओं का निर्धारित की जाय से, अधिक है या

(ग) भूमि या भू-गृहादि का प्रत्येक स्वामी जिसने इस धारा के अधीन सर्वेक्षण शुल्क का भुगतान कर दिया है नि शुल्क तथा भूमि या भू-गृहादि का प्रत्येक स्वामी जो ऐसे सर्वेक्षण शुल्क के भुगतान का भागी नहीं है, ऐसे प्रभारों (Charges) का जो निर्धारित किये जाय, भुगतान करने पर इस अध्याय के अधीन तैयार किये गये नक्शों से तथा रजिस्ट्रार से प्रमाणित उद्धरण (Exhibit), जहां तक वे ऐसी भूमि या भू-गृहादि से सम्बन्धित हैं प्राप्त करने का अधिकारी होगा।

[धारा १४१] सर्वेक्षण का खर्चा — धारा १४१ का मे निर्दिष्ट प्रावधानों के अधीन रहते हुए, इस अध्याय के अधीन किये गये प्रत्येक सर्वेक्षण का खर्चा —

[१] ऐसे सर्वेक्षण का खर्चा स्थानीय प्राधिकारी के होने की दशा में ऐसे स्थानाय प्राधिकारी द्वारा और

[२] अन्य मामलों में राज्य सरकार द्वारा पूरा किया जायगा

परन्तु शत यह है कि खण्ड (१) के अधीन आने वाले मामले में राज्य सरकार —

(क) राज्य की सघनित निधि (Consolidated Fund) में से ऐसे खर्च का भाग का भुगतान करना स्वीकार कर सकेगी या

(ख) ऐसे खर्च की पूर्ति के लिए, स्थानीय प्राधिकारी को खर्च की दर पुन भुगतान की अधि और प्रतिभूति तथा वित्तसदृश सिस्टीम जो दोनों (पक्षों) द्वारा स्वीकार की जाय के सम्बन्ध में ऐसी शर्तों तथा प्रतिबंधों पर अग्रिम रूप में करण देना स्वीकार कर सकेगी।

[धारा १४१ता] नोटिस की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में विफल रहने पर शक्ति — जो कोई भी इस अध्याय के अधीन जारी किये गये तथा यथाविधि तामील किये गये नोटिस में निहित आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रहता है, ऐसे श्रम दण्ड से जो एक सौ रुपये से अधिक नहीं होगा, दण्डित होगा।

[धारा १४१ था] नर्सों, रजिस्ट्रारों तथा अन्य दस्तावेजों का निरीक्षण और उमर उद्घरणों की प्रतियां — (१) धारा १४१ डा की उपधारा (१) में निम्नलिखित समस्त नर्सों रजिस्ट्रार तथा अन्य दस्तावेजों का ऐसी रीति तथा ऐसे घंटों के बीच, ऐसे स्थानों पर तथा ऐसी शता के अधीन रहते हुए एवं ऐसे शुल्कों का भुगतान करने पर जिन्हें राज्य सरकार नियमित कर, सार्वजनिक रूप में निरीक्षण किया जा सकेगा।

(२) ऐसे नर्सों रजिस्ट्रारों तथा दस्तावेजों की या उसके उद्घरणों की प्रमाणित प्रतिलिपियां एवं प्रतिलिपि शुल्क का भुगतान करने पर तथा ऐसी रीति में जिसे राज्य सरकार नियमित कर मजूरी का जायेगी।

[धारा १४१ डा] नियम — राज्य सरकार सरकारी राजपत्र में विज्ञापित द्वारा निम्नलिखित के सम्बन्ध में ऐसे नियम बना सकेगी जो इस अध्याय के प्राधान्यों से असंगत न हो —

[१] सर्वेक्षणार्थ आगामी क्षेत्र के भीतर किसी भूमि या भू-गृहादि के सम्बन्ध में नर्सों तथा रजिस्ट्रार तैयार करने उसका रूप तथा मसूदा और मूचना को रकड करने,

[२] इस अध्याय के अधीन की जाने वाली समस्त कार्यवाहिया का विनियमन करने

[३] तदनुगुण की जाने वाला समस्त जाच का रीति

[४] समस्त ऐसे मामलों के विनियमन के लिए जिनका इस अध्याय के अधीन निवारण किया जाना अपेक्षित है या जो निवारित किये जायेंगे और

[५] सामान्य सम्बन्धों का जाने वाली समस्त कार्यवाहिया के अतिरिक्त मंचालन के लिए और उसके प्रयोजना तथा प्राधान्यों की क्रियाविधियों के लिए।

[धारा १४१ धा] रायवाहिया अनौपचारिकता (Informality) द्वारा प्रभावित नहीं होगी — इस अध्याय के अधीन की गई कोई भी कार्यवाहिया किसी अनौपचारिकता के कारण प्रभावित नहीं होगा बशर्ते कि उससे प्राधान्यों का सारत एवं प्रभावपूर्ण रूप में सामिल हो गई हो और इस अध्याय के अधीन की गई कार्यवाहिया इस कारण से प्रभावित नहीं होगा कि इस अध्याय के द्वारा या अधीन जारी तथा तामील किए जाने के लिए अपेक्षित कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था।

[धारा १४१ ना] नक्शों तथा रजिस्ट्रार में प्रविष्टियाँ के सम्बन्ध में अनुमान — इस अध्याय के अधीन तैयार किये गये समस्त नक्शे तथा रजिस्ट्रार में की गई समस्त प्रविष्टियाँ सही समझी जायेंगी जब तक कि उसका विपरीत साधित न कर दिया जाय।

परन्तु शर्त यह है कि ऐसा कोई नक्शा या प्रविष्टि किसी व्यक्ति या किसी भूमि या भू-गृहादि के या में अधिकार स्वत्व या हित को प्रभावित नहीं करेगी या उसे ऐसे अधिकार स्वत्व या हित को विधि अनुसार किसी सक्षम न्यायालय में प्रामाणिक (enforcing) कराने से नहीं रोकगी।

अध्याय ८

भूग्रन्थ कार्य

(क) सामान्य

[धारा १४२ भू ग्रन्थ तथा पुनर्भूग्रन्थ—(१) सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित कर राज्य सरकार किसी जिले या अथवा क्षेत्र को बन्दोस्त अथवा पुनर्बन्दोस्त में, जैसी भी अवस्था हो, रखन की आज्ञा दे सकती है।

(२) उपधारा (२) के अधीन निम्नलिखित गये श्रितहार की तारीख से ऐसे क्षेत्र बन्दोस्त के अन्तर्गत, बन्दोस्त की फायदाही के अन्त की विज्ञप्ति निकाले जाने तक समझा जायेगा।

[धारा १४३] पुनर्बन्दोस्त के अनुमानत परिणाम — राज्य सरकार धारा १४ की उपधारा (१) के अन्तर्गत, जब किसी जिले या अथवा क्षेत्र के सम्बन्ध में राजस्व की मसूली के लिये नियत किया गया समय समाप्त होने को होगा, विज्ञप्ति प्रकाशित करन के पूर्व द्वारा बन्दोस्त के अनुमानत परिणाम का मन्विष्याकन करवा दिया है।

[धारा १४४] पुनर्बन्दोस्त के औचित्य को तय करने का कारण (CONSIDERATION) — कोई जिला या क्षेत्र पुनर्बन्दोस्त के कारणमा तर्गत लिया जाय या नहीं, इसका निर्णय करने के लिये राज्य सरकार विचार करगी।

(१) यह कि राजस्व में कोई विचारणीय कमीवशी होने वाली है या नहीं,

(२) कि ऐसी वृद्धि होने की अवस्था में पुनर्बन्दोस्त को स्थगित करने के सतोपदायक कारण हैं कि नहीं।

(३) कि वर्तमान राजस्व का निधारण अनुचित हो गया है या ऐसे पयाप्त कारण वर्तमान हैं कि नहीं। निम्नी वृद्धि में भविष्य में राजस्व वृद्धि की कोई सम्भावना न होने लये भी पुनर्बन्दोस्त करना उचित होगा।

परन्तु शर्त यह है कि राजस्व की ऐसी वृद्धि समीचीन मानी जायेगी कि जो पुन राजस्व की कार्यवाही में किये गये समस्त खर्च को दस गुना के अर्से में बेगार करदे।

टिप्पणी—यह धारा प्रावधान करती है कि यदि राज्य सरकार उचित समझ तो किसी क्षेत्र प्रथम जिले का पुन बन्दोबस्त का कार्यक्रम में संभवता है।

[धारा १४५] भूस्वाम्याधिकारी—धारा १४० की उपधारा (१) के अन्तर्गत विहित प्रशासन करने पर, राज्य सरकार—

(१) जब तक कि बन्दोबस्त कार्य के लिए प्रत्येक जिले या क्षेत्र में कोई स्थायी भूस्वाम्य अधिकारी नियुक्त न हो जाय, धारा १४० की उपधारा (२) में उल्लिखित कार्य-वाहियों के लिए एक भूस्वाम्य अधिकारी का नियुक्ति करणी और

(२) आनन्दकान्तुसार सहायक भूस्वाम्याधिकारियों की नियुक्ति कर सकती है।

[धारा १४६] भूस्वाम्याधिकारी को भूलेख अधिकारी के कर्तव्यों का हस्तान्तरण—जब कभी कोई जिला अथवा कोई स्थानीय क्षेत्र भूस्वाम्य कार्य के अधीन होगा तबसे उसमें की व्यवस्था तथा वार्षिक राजस्वों के निर्माण का कार्य राज्य सरकार के आदेशानुसार भूलेख अधिकारी से भूस्वाम्याधिकारी को हस्तांतरित किये जा सकन हैं और यह अध्याय ७ द्वारा भूलेख अधिकारी को प्रदत्त अधिकारों का व्यवहार करगा।

[धारा १४७] नियम—राजस्थान सरकारी गजट में विहित प्रशासन कर राज्य सरकार, भूस्वाम्य का कार्यक्रम के सम्बन्ध में भूस्वाम्याधिकारी की प्रक्रिया के लिए नियम बना सकती है।

(१२) लगान की दरें—

[धारा १४८] आर्थिक सर्वेक्षण—जब कोई जिला या अन्य स्थानीय क्षेत्र भूस्वाम्य का अधीन रखा जायगा, भूस्वाम्य अधिकारी ऐसे जिले या क्षेत्र के फारमवारों की आर्थिक अवस्था के बारे में सर्वेक्षण करगा और ऐसे सर्वेक्षण के मध्य निम्नांकित बातों का विशेष ध्यान रखेगा—तथा

- (क) यह सीमा जिस तक कोई जिला या क्षेत्र सिंचाई से लाभ नहीं उठता है और विगत भूस्वाम्य से तत्समय तक सिंचाई की सुविधाया न किया गया विकास यदि कोई हो,
- (ख) कृषि का स्तर, और विगत भूस्वाम्य से तत्समय तक कृषि की जाने वाली भूमि के क्षेत्रफल का वृद्धि या कमी
- (ग) कृषि व्यय तथा कृषक पर उसके परिवार के सम्मिलित व्यय,
- (घ) बन्दोबस्त के अधीन क्षेत्र में अथवा उसके आसपास मौजूद धाजार,

- (६) आयागमन के साधन और विगा भूमि के परमात् उनमें होने वाला विकास यदि कोई हो,
 (७) जोत की सम्पत्ति चौड़ाई।
 (८) आसामिया की बंजरों का परिणाम और ग्रहण की सुविधाएँ—

[धारा १४८] रू निर्धारण क्षेत्र या वर्ग —(१) धारा १४८ में उल्लिखित अधिक संप्रदाय के साथ साथ या उनके समाप्त होने के उपरान्त शीघ्र ही भूमि-धाधिकारी कर निर्धारण के क्षेत्र या वर्ग निर्धारण सम प्रत्येक लेने विने और क्षेत्र में तैयार करेगा जे कि बन्दोस्त के अधीन होगा।

(२) धारा १४८ में उल्लिखित विषय एवं अन्य निम्नांकित विषयों के मध्य एकता बनाये रखने का भी, कर निर्धारण के क्षेत्र या वर्ग बनाने के समय ध्यान रखा जायेगा—

- (क) प्राकृतिक बाधाकार,
 (ख) जलवायु एवं वर्षा
 (ग) जनसंख्या एवं श्रम की प्राप्ति
 (घ) कृषि के साधन,
 (ङ) बोई जाने वाली प्रमुख फसलें एवं उनकी उपज की मात्रा तथा बाजार में प्रचलित उनके भाव
 (च) जोत के लिए प्य लगान की दर, और
 (छ) विगत भूमि-ध के समय निमत कर निर्धारण के क्षेत्र या वर्ग निर्धारण वर्गों, यदि कोई हो।

[धारा १५०] मिट्टी का वर्गीकरण —धारा १४८ के अधीन बनाये गये कर निर्धारण के क्षेत्र अथवा कर निर्धारण वर्गों में स्थिति गांवों को भूमि-धाधिकारी, इस सम्बन्ध में बनाये गये नियमों के अनुसार मिट्टी को विभिन्न वर्गों में बाँटेगा।

[धारा १५१] लगान की दरों का विकास —भूमि-धाधिकारी प्रत्येक कर निर्धारण के क्षेत्र या वर्ग में, जैसी भी स्थिति हो, प्राप्त मिट्टी की प्रत्येक श्रेणी के उचित लगान-दरों का विकास करेगा।

[धारा १५२] लगान दरों का आधार —(१) धारा १५१ के अन्तर्गत किसी उचित एवं ठीक लगा दर के निर्धारण हेतु भूमि-ध अधिकारी निम्नांकित का ध्यान रखेगा —

- (क) बन्दोस्त के तत्कालपूर्व २० वर्षों में लगान अथवा लगान की सूत्र में अन्य अभिदेय के द्वारा प्राप्त रकम। राज्य सरकार द्वारा सरकारी गजट में प्रकाशित विज्ञप्ति द्वारा असाधारण घोषित वर्षा को इन २० वर्षों में से घटाया लिया जायेगा।

(न) बन्नेरस्त के तत्कालपूर्व ० वर्षों में कृषि उपज के सम्बन्ध में प्रचलित आँकड़ों का भाग । ऐसे आँकड़ों में ऐसे वर्षों में शेष कर दिये जायेंगे जोकि राज्य सरकार ने सरकारी गनट में प्रिजिप्ति निजाल कर असाधारण घोषित कर दिये हैं ।

(ग) जोड़ जाने वाली फसलें और उनकी उपज का परेणाम,

(घ) स्टाइ (स) में उल्लिखित आँकड़ों का भाग के आधार पर ऐसी उपज का मूल्य,

(ङ) कृषि व्यय तथा कृषक पर उनके परिवार के खर्च,

(च) प्रत्येक जात का वह आँकड़ा प्रति वर्ष जुगाई नहीं की जाती है, जुगाई छोड़ने का क्रम तथा ऐसी जुगाई छोड़ने की अवधि,

(छ) कर-मुक्ति, कर-स्वागत एवं कर के न्यून-समूह की एक सूची,

(ज) निम्न सम्पत्ति की लगान दरें यदि कोई हों और उपज का अंश तथा परिणित भाग जिन पर ऐसी दरें प्रयुक्त की गई हैं, और

(झ) लगान दरें, यदि कोई हों, जोकि आसपास के देशों में स्थित समान श्रेणी की भूमि के विषय में तय की गई हैं ।

(ञ) भूस्वाम्याधिकारी द्वारा निश्चित की जाने वाली दरें, उनसे सम्बद्ध शर्तों

में धारा (१) स्टाइ (घ) में निर्दिष्ट उपज के प्रचलित मूल्य का अधिकतम छद्म भाग होगी ।

[धारा १५३] दरों का मजबूत — भूस्वाम्याधिकारी नम विषय में भी कि उसके द्वारा निश्चित लगान दरें नम सम्पूर्ण गांव या उसके किसी निर्दिष्ट अंश या उसकी मिट्टी की किसी निर्दिष्ट श्रेणी के लिए जिना किसी मजबूत के लागू होने के योग्य है अथवा उनमें किसी भीमा तक मजबूत की आवश्यकता है प्रत्येक गांव के लिए दिखाना लिखेगा ।

टिप्पणी — यह धारा स्पष्ट करती है कि यद्यपि लगान दरें बन्नेरस्त अधिकारी तय करता है कि किन्तु इस सम्बन्ध की कतिन शक्ति सरकार में ही निहित है । सरकार चाह तो बन्नेरस्त अधिकारी द्वारा तय लगान दरों को बदल सकता है ।

[धारा १५४] निर्मित एवं अभिलेख मामले — नम अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा निर्मित नियमों के अधीन बन्नेरस्त अधिकारी निश्चयन एवं रिकॉर्ड करेगा—

(क) कि पर एक किस्त में देय हो अथवा अग्रिम में

(ख) कर के एक में अधिक किस्तों में देय होने की अवस्था—

(१) ऐसा किस्तों का मन्त्र,

(२) ऐसा आँकड़ा जो वर्तमान किस्त अदा किया जायेगा

(ग) लगान अथवा मन्त्र किस्त की, जैसी भी अवस्था हो अदायगी की तारीख, और

(घ) ऐसा अन्य विषय जिसके निश्चय एवं अभिलेख किस्त जान के लिए उसे ऐसे नियम निर्दिष्ट हों ।

[धारा १५५] प्रस्तावों का प्रकाशन तथा प्रस्तुतीकरण — (१) जब धारा १५५ और १५३ के अनुसार लगान दरों का निर्णय हो जाय, भूद्वारा अधिकारी उस सम्बन्ध में निर्धारित रीति से प्रस्ताव प्रकाशित करेगा और उनमें साथ-साथ उसे आगरा भा प्रकाशित करेगा जिन्ना पर ऐसी लगान दर नियत की गई है।

(२) तदन्तर बन्दोबस्त अधिकारी निर्धारित रीति से जन सूचना देगा तथा उस जन सूचना में निर्दिष्ट समय के भीतर उपधारा (१) के अन्तर्गत प्रकाशित प्रस्तावों पर विरोध प्रस्तुत करने की मांग करेगा।

(३) यदि उपधारा (२) में निर्धारित समय के अन्दर कोई आपत्तियाँ प्राप्त की जायेंगी तो बन्दोबस्त अधिकारी उन पर विचार करेगा और ऐसी राति से जो कि वह उचित समझे, अपने प्रस्तावों में संशोधन कर सकता है।

(४) इससे परवाना भूद्वारा अधिकारी द्वारा उठाई गई आपत्तियाँ एवं उन पर जारी किये गये आदेशों सहित अपने सुभाष भूद्वारा आयुक्त को प्रस्तुत करेगा।

[धारा १५६] प्रस्तावों की स्वीकृति — धारा १५५ के अधीन प्राप्त किये गये प्रस्तावों का सेटिलमेन्ट कमिशनर अनुरीक्षण करेगा और उनमें विहित विषयों में ऐसी पृथक्पृथक् करेगा जो कि वह आवश्यक समझे—

(१) तदन्तर वह अपने रिमार्क तथा सुझावों के साथ उन प्रस्तावों को बोर्ड के पास प्रस्तुत करेगा।

(२) उपधारा (१) के अन्तर्गत भेजे गये प्रस्तावों की प्राप्ति पर बोर्ड उनमें निहित किसी भी मामले में आर जांच कर सकता है।

(३) ऐसी आर जांच के परान्त यदि कोई हो, जो कि उपधारा (२) में उल्लिखित है। बोर्ड ऐसे प्रस्तावों में संशोधन किये जिन्ना ही अथवा लिखित में कारणों के लिये जाने पर प्रस्तावित कर निरूपण क्षेत्र या थग में या मिट्टी की श्रेणियाँ तथा लगान दरों में ऐसा परिवर्तन करते हुये, जो वह उचित समझे, उन प्रस्तावों की स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को भेजेगा।

(४) राज्य सरकार—

(१) बोर्ड द्वारा भेजे गये प्रस्ताव स्वीकार कर सकता है या

(२) निर्देश दे सकता है कि कोई उचित जांच की जाय, या

(३) बोर्ड को पुनर्विचार के लिए प्रस्ताव लौटा दे, या

(४) ऐसे परिवर्तनों के उपरान्त जो वह उचित समझे, प्रस्ताव स्वीकार करे और इस प्रकार स्वीकृत लगान दरें स्वीकृत लगान दरें कहलायेंगी।

(ग) लगान का निरूपण

[धारा १५७] लगान का निर्धारण — स्वीकृत लगान दरों के आधार पर भूद्वारा अधिकारी देय लगान का निर्धारण करेगा जो तत्समय वर्तमान लगान को कम करने बढ़ाने, उसमें परिवर्तन करने अथवा अन्य किसी रूप से पूर्य करेगा। बन्दोबस्त के अधीन क्षेत्र अथवा प्रत्येक जिले के लिये ऐसा निर्धारण किया जायेगा।

जोत एवं घोये जाने वाले भेज या, सूची जोनी जाने वाली एवं प्रतिष्ठापन वाली छोटी जाने वाली भूमि का ध्यान रखा जायेगा और ऐसा लगान 'गाही सूची' और भूमि के लिये प्रहण की गई स्वीकृत दर के अनुसार गन पांच वर्षों के लिये, सूची या उत्तर जोनी के क्षेत्र के सिलसिले में निम्न जाया लगान के पूर्ण रूप में होगा।

(२) ऐसी किसी साभिप्राय सूची जोनी गई अथवा धनर छोटी गई नमीन पर उपधारा (१) की पाइ भी या, लागू नहीं होगी जो कि इस प्रकार सही लगान के निधारण से पचने के लिए छोटी गई होगी और ऐसा भ्रम लगान निधारण के बारे में गाही के रूप में जोना गया समझा जायेगा।

[धारा १६४] पत्तों का निर्माण तथा प्रसारण — (१) उपरोक्त रीति से लगान का निधारण के परगत नन्दोयन अधिकारी नन्दोयन के आधीन निम्नी जिले या क्षेत्र की चोतों के लिये लगान निधारण के पंच तैयार करवायेगा।

(२) किसी चोत के लगान निधारण पंच में निम्नांकित विवरण होंगे—

(क) जोत की अवस्था,

(ख) उसने प्रत्येक रेत का खसरा नम्बर और उसका भेजफल,

(ग) चोत में अननिहित प्रत्येक रेत की मिट्टी का वर्गीकरण,

(घ) मिट्टी की श्रेणियों के लिये प्रथम प्रथम लगान दरें,

(ङ) ऐसी जोत की मिट्टी की ऐसी श्रेणी के लिए धारा १८० के अनुरूप नन्दोयन अधिकारी द्वारा निधारित लगान,

(च) धारा १८६ के अनुरूप छूट दिये गये कोई प्रियास, यदि हो, और

(छ) प्रत्येक जोत के लिये निर्धारित लगान की कुल चोड और धारा १६१ और १६२ के अनुरूप दिये गये तत्सम्बन्धी समाधान अथवा आदेश।

(३) इस प्रकार निर्मित पत्रा नियत प्रणाली से सम्प्रतिष्ठन आसामी को भेजा जायेगा तथा उसकी एक नकल भूमिधारी को, यदि कोई हो भेजी जायेगी।

(४) उपधारा (२) में और उसने अधीन निर्धारित प्रणाली से सभी लगान निधारण पत्रा घाट दिये जाय तब नन्दोयन अधिकारी तत्सम्बन्धी आपत्तिया प्रस्तुत करने के लिये जन-सूचना प्रकाशित करेगा।

[धारा १६५] पैदावारी लगान की वसूली पर अन्तरिम अवरोध—

(१) यदि किसी वस्तु कृषि वर्ग प्रारम्भ होने के उपरान्त किसी जिले भेज के सम्प्रतिष्ठन में धारा १६४ की उपधारा (३) के अनुरूप लगान निधारण के पंच बाटे जाने की सम्भावना हो और नन्दोयन अधिकारी इससे सन्तुष्ट हो कि भूमाधारित एवं कृषकों के बीच में तनावपूर्ण मामलों के कारण अथवा अन्य किसी कारण ऐसे जिले या क्षेत्र में

फसल की पैदाशारी के आधार पर समूल किये जाने वाले लगान पर अवरोध लगाना उचित होगा तो वह इस सम्मन्ध में राज्य सरकार से सिफारिश करेगा ।

(२) यन्त्रोपकरण आधुनिक यन्त्रोपकरण अधिकारी की ऐसी सिफारिश राज्य सरकार को अपनी ऐसा टिप्पणी के साथ भेजेगा जो वह उचित समझे ।

(३) राज्य सरकार, यदि उचित समझेगी, इस सिफारिश को स्वीकार कर नत्सन्देही आज्ञा दे सकती है ।

(४) उपधारा (३) के अन्तर्गत प्रकाशित किया गया राज्य सरकार या किसी जिले या स्थानीय क्षेत्र में पैदाशारी के आधार पर किये जाने वाले लगान की वसूली पर अवरोध लगाने वाला आदेश निधारित प्रणाली से प्रकाशित किया जायेगा और उसमें निर्देशित होगा—

(क) कि उस वसूली रूप में प्रारम्भ में, ऐसे जिले या क्षेत्र में कोई भी भूमिदारी लगान पैदाशारी के आधार पर समूल नहीं करेगा और

(ख) कि धारा १६६ के अन्तर्गत निधारित नदी लगान के निर्णित होने तक, ऐसे जिले या क्षेत्र में भूमिदारी प्रत्येक जोत के लिये उसी लगान की अपेक्षा ऐसा नगदी लगान वसूल करे कि जो लगान निधारण के पूर्व में इस सम्मन्ध में निर्धारित मात्रा लगान के रूप में उल्लिखित किया गया हो

परन्तु शर्त यह है कि इस माते वसूल किये जाने वाला नगदी लगान धारा १६६ के अन्तर्गत निर्णित किये जाने वाला नगदी लगान के पेटे प्रमाणित किया जायेगा ।

(५) पैदाशारी लगान की वसूली पर रोक लगाने सम्बन्ध आदेश सभी निम्नलिखित बातों पर आदेश देने पर्य में खरीफ की फसल का निराया वसूल नहीं किया गया हो ।

[धारा १६६] आपत्तियों की सुनवाई तथा लगान का निर्धारण — यदि धारा १६८ की उपधारा (४) के अन्तर्गत प्रकाशित घोषणा के पर्याप्त सोस दिन की अवधि के अन्तर यदि कृषक अथवा भूमिदारी आपत्ति प्रस्तुत कर तो सूत्रमन्त्र अधिकारी इसकी सुनवाई करने के उपरान्त कानून के अनुसार उमदा निषटारा करेगा तथा अपने आदेश का अभिलेखन करने के बाद जोत का लगान तय करेगा ।

[धारा १६७] लगान नियम दिनांक से देय होगा—धारा १६२ के प्रावधानों के धारा १६६ के भूधन अधिकारी के आदेश द्वारा निर्धारित लगान, यन्त्रोपकरण की अवधि पाल होने की तारीख से ही देय होगा किन्तु शर्त यह है कि ऐसे कारणों के

आधार पर, जो लक्ष्यकृत किये जायेंगे और जिन्हें यह अधिकारी उचित समझत होय यह आदेश द कि ऐसा लगान किसी पृथ की तारान से ही प्रभावशील हो जायगा।

[धारा १६८] नियत लगान की अस्वीकृत करने का कृपक को विम्वन् प्राप्त होगा,—जिस पारनकार की जोत का लगान घटोयस्त अधिकारी न धारा १६७ के अन्तर्गत तय किया हो, उसे आदेश के प्रकाशित होने के तीस दिन के अन्दर निर्धारित लगान की अस्वीकृति लिखित में दे सकता है।

[धारा १६९] अस्वीकृति का प्रतिफल —(१) निर्धारित लगान की अस्वीकृति पर कृपक उस जोत का खाली कर देगा।

(२) जोत को खाली न करने पर यह अतिव्याप्तक समझ जायेगा और यह उस जोत से राजस्थान दिनें सी अधिनियम, १९५५ की धारा १८३ के प्राधानों के अनुसार बदलल किये जाने योग्य होगा।

टिप्पणी—यह धारा स्पष्ट करती है कि यदि कृपक को निर्धारित लगान स्वीकार नहीं होगा तो उसे वह जोत खाली करनी पड़ेगी और तद्विस्तार उसे बेमाल कर सकेगा।

[धारा १७०] जोत का अन्य व्यक्ति को दिया जाना,—धारा १६६ के अन्तर्गत जोत के खाली होने पर या जोत से बेदखल किये जाने पर यह किसी अन्य व्यक्ति के लिये सुलभ हो सकेगी और उसको कानून के अनुसार कृपक बनाने के लिए योग्य व्यक्ति को दिया भी जा सकेगा।

[धारा १७१] स्वीकृति के उपरान्त जाता —यदि धारा १६८ के प्राधानों के अनुसार कृपक लगान स्वीकार करने से इन्कार न करे तो धारा १६६ के अन्तर्गत इससे द्वारा लगान का स्वीकार किया जाना परिकल्पित किया जायेगा और यह धारा १६७ के अनुसार उसकी अदायगी किये जाने के लिये उत्तरदायी होगा।

[धारा १७२] बन्दोस्त की अवधि के भीतर लगान नहीं बदलेगा — धारा १६६ के अधीन बन्दोस्त अधिकारी द्वारा किसी जोत के लिये तय किया गया लगान, धारा १७२ के अन्तर्गत तय किये गये बन्दोस्त के कार्यकाल के बीच परिवर्तित नहीं किया जायेगा सिवाय ऐसी दशा के जब कि इस अधिनियम या राजस्थान टीनेन्सी अधिनियम, १९५५ के प्राधानों द्वारा यह अपेक्षित हो।

[धारा १७३] ग्राम क दस्तूर का निर्माण —(१) गन्दोस्त के अधीन गन्दोस्त अधिकारी प्रत्येक जिले या अन्य स्थानीय क्षेत्र के प्रत्येक गांव के लिए एक उचित ग्राम दस्तूर का निर्माण करवायेगा।

(२) इस अधिनियम के अंतर्गत बनाये गये नियमों के अधीन गन्दोस्त अधिकारी प्रत्येक ऐसे ग्राम दस्तूर में तय करेगा और उल्लिखित करेगा —

(२) सम्बन्धित गांव में प्रचलित प्रथा,

(१) उदा के निवासिया के अथवा गांव की सम्मिलित जमीनों में से जोत गारा करन गला के और उसकी उपज तथा गांव की स्थिति के सम्बन्ध में, और

(२) गिराद के हेल राजा के लिये अधिकारी तथा अन्य प्रयोजना के सम्बन्ध में, और

(३) गिराद के सम्बन्ध कोड अधिकार, रिजान या अन्य बात निसरा न्य दस्ता गना एवं ग्राम-दस्तूर में प्रसिद्ध किया जाना, इस अधिनियम के अन्तर्गत या अन्यथा न्य से राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित हो।

(३) जब ग्राम-दस्तूर तैयार हो जाय, तब सम्बन्धित गांव के निवासिया व सामन गन्ने पड़े जान का कोड तारीख न दोस्त अधिकारी तय करेगा और निर्धारित राति से वही तारीख के कम से कम सात दिन पूर्व वह उस बारे में जन-सूचना प्रकाशन करेगा।

(४) उपधारा ३ के अधीन नियत किये गये दिन तथा समय पर उपधारा (१) के अन्तर्गत बनाई गई दस्तूर गानाई की एकत्र ग्राम निवासिया के सामने गन्दोस्त अधिकारी पढ़ेगा या उसे पढ़ावेगा।

(५) यदि उपधारा ४ के अधीन दस्तूर गानाई के पढ़े जाने के समय कोई व्यक्ति उसके किसी प्रसिद्ध के सम्बन्ध में आपत्ति उठाव तो गन्दोस्त अधिकारी उसे नगरपट्टा करेगा तथा उस आपत्ति पर अपना निर्णय दगा जो कि अन्तिम होगा।

[धारा १७४] गन्दोस्त की प्रतिलिपियाँ और परिसंख्या — धारा १७३ के अन्तर्गत निर्मित दस्तूर गानाई का प्रतिलिपिया तब तक सार परिकल्पित का जायगी जब तक कि विपरित सिद्ध न करदी जाय।

(५) गन्दोस्त की अगति

[धारा १७५] गन्दोस्त की अगति — इस अधिनियम के अधिनियम के अन्तर्गत गन्दोस्त की अगति २० वर्ष की होती।

परन्तु शर्त यह है कि राज्य सरकार भूमि पर अधिपतियां जामग्या के भार, कृषि योग्य भूमि के भेद्यफल तथा लगान की पूर्णता का ध्यान म रखते हुए एम्मा अधिधी बीम वर्ष से अधिन घटा सकती है।

एक शर्त और भी है कि लखनऊ नियं जाने याग्य विशेष कारणों से भूमि की गहरी क्षति, सम्पत्ति की गभार गोपनीयता अथवा कृषि व अभिप्राय एवं अधिन मात्रा म भूमि के बाहर फेरन आदि विद्दी अ य पय पन कारण का अथवा म अथवा किसी स्थानाय क्षेत्र के लिए राज्य सरकार बन्दोस्त की बीम वष से वम कोद् अधिधी स्थानार कर सकती है।

[धारा १७५क] बन्दोस्त की अधिधी की शुन्यात — प्रत्येक बन्दोस्त की अधिधी इस कानून के अन्तर्गत उस दिवस स चालू होगा जिस दिन से राज्य सरकार सरकारी गनट म, नोटिफिकेशन के द्वारा नियत कर।

टिप्पणी — राजस्थान अधिनियम २ भाक १९५८ के लण्ड ल की प्रथम शूषि व अनुसार जो राजस्थान गनट लण्ड व-क विन्यास निनाक (३ १ १९५८ द्वारा प्रकाशित हुमा, सम्मिलित की गई।]

[धारा १७६] बन्दोस्त की पून समाप्ति — (१) धारा १७५ मे अन्तर्निहित किसी भी बात के होते हुये भी जब राज्य सरकार सन्तुष्ट हो जाय कि उस धारा के अधीन बन्दोस्त के लिए रखी या तय की गद् मयाद् के पहले ही मूर्यों मे तात्त्विक एवं विचारनाय वमी होने के कारण या उस क्षेत्र की रसीटन लगान दरो तथा उनसे सयुक्त मत्र का ऐसी हा दरा के बीच कोद् विशेष अ वर हान के कारण अथवा और जाच से स्वाकृत लगान दरो अत्यधिक ज्यादा ज्ञान होने के कारण अथवा अन्य किसी पयाप्त कारण से उसका समाप्ति करना आवश्यक हो तो राज्य सरकार सरकारी गनट मे निम्नलिखित प्रकाशित कर वतमान बन्दोस्त को समाप्त करने तथा तत्सम्बन्धी क्षेत्र को पुन बन्दोस्त व अधीन लेने का विचार प्रकट कर सकती।

(२) इस प्रकार की घोषणा से सलग्न अथवा उसके तत्काल परचान् एक ऐसी हा निम्नलिखित द्वारा राज्य सरकार ऐसा अधिधी की समाप्ति की घोषणा कर सकती है और सन्तुष्ट निले या क्षेत्र व पुन बन्दोस्त मे लिए जाने का आदेश दे सकती है तथा इस अध्याय के प्रावधान इस भाति प्रभावित होने मानों ऐसा निला या क्षेत्र बन्दोस्त की कार्यवाही के अधीन हो।

(३) [x x x x]

(४) [x x x x]

[] टिप्पणी — [(३) और (४) उप धारा दिनांक ३१ १२ ५६ के विन्यास गनट व छुने राजस्थान अधिनियम सध्या ४४ भाक १९५६ के सेक्शन २ के अनुसार नोपित करदी गई।]

[धारा १७६क] बन्दोस्त करने के दौरान म अन्तरिम सहायता — (१) जब कभी किसी निले या अन्य स्थानीय क्षेत्र को धारा १८० की उपधारा १ अथवा धारा १७६ की उपधारा () के अन्तर्गत पुन बन्दोस्त के अन्तर्गत लिए जाने मे आदेश

दिये जायें, राज्य सरकार बहा के कृपों की ऐसी जगहों पर जो वह उचित समझे, अनतर्विम
सहायता पहुँचाने के अर्थ से आज्ञा दे सकती है।

(२) जब किसी जिले या अन्तर्गत क्षेत्र को धारा १७८ की पंक्ति (२) के
अनुसार पुनर्गठित करने के लिए आदेश दिया जावे राज्य सरकार अपना इच्छा
में यह भी आज्ञा दे सकती है कि उन्देश्य अधिकारी को धारा १७८ के अन्तर्गत उसे
नोमिनेट मजदूर बनाना आवश्यक नहीं होगा।

टिप्पणी — [धारा १७८ (१) (२) राजस्थान अधिनियम सरकारी धारा १९५६ व
कानून ३ द्वारा जो राजस्थान गजट विधायक ४६ दिनांक ३१ १० ५६ के अनुसार सम्मि
नित का गई।]

[धारा १७७] ममाप्त जिये गये उन्देश्य के अन्तर्गत भूमि का नये
बन्दोस्त तब स्वरूप — धारा १७८ की पंक्ति (१) के प्रावधानों के अन्तर्गत भूमि
को धारण करने वाले सभी व्यक्ति उन्देश्य की अधि की समानि अथवा गुणान्त के
समय, उस उन्देश्य की गता के अनुसार ही नये उन्देश्य के किन जगह तक सभी भूमि
का धारण करेंगे।

टिप्पणी — राजस्थान गजट तब ४४, १९५६ व कानून ४ के द्वारा जो राजस्थान गजट
के खण्ड ४ में विधायक, दिनांक ३१ १२ १९५६, का प्रकाशित हुआ सम्मिलित किया गया।

(६) मध्यमों पुनर्गठन

[धारा १७८] अन्यसालीन उन्देश्य — जब धारा १७८ के द्वितीय अनुच्छेद
के अन्तर्गत किसी भी स्थानीय क्षेत्र के लिए नियत की गई उन्देश्य की अधि उन्देश्य
व अधीन पूर्व जिले या सम्पूर्ण क्षेत्र व सम्बन्ध में नियत की गई अधि से कम हो और
ऐसा अधि समाप्त हो जाय तो कलन्टर अथवा किसी जिले वहा कि स्थायी उन्देश्य
अधिकारी निरुक्त किया गया हो, ऐसा उन्देश्य अधिकारी ऐसे स्थानीय क्षेत्र के लिए इस
अधिनियम के अन्तर्गत निर्मित नियमों के अनुसार बर निधारण करता।

[धारा १७९] प्रवाह से हुन भूचय और उठार भूमि के उन्देश्य पर
निधारण का पुनर्गठन — (१) जोत में सटुक्त होने वाली कटार भूमि का, इस अधि
नियम के अधीन निर्मित नियमों के अधीन कलन्टर या स्थायी उन्देश्य अधिकारी,
कानून निरधारण करता।

(२) पानी के प्रवाह के कारण या अन्य रूप में कट कर, जब किसी जोत का अधि
धान्य सरह कम हो जाय तो कलन्टर या कौट स्थायी उन्देश्य अधिकारी पर निधारण
का पुनर्गठन करता।

(३) स्थायी भूमि अधिकारी या कलन्टर, किसी भी अवस्था हो, की राय में किसी
जोत का भूमि का मूल्य उसकी कृषि से गैर फल के कामों में अथवा गैर फल से फल
के कामों में उस समय से लिय जान पर जब कि वह पिछली बार निधारित का गटे थी तो
पर निधारण का पुनर्गठन किया जाकर इस अधिनियम के अधीन बनाने गये नियमों के
अनुसार ऐसी जमीन के परिवर्तित मूल्य के प्रस्तावानुसार उसका किराया कलन्टर अथवा
स्थायी उन्देश्य अधिकारी द्वारा नियत किया जायगा।

(८) उपरोक्त उपधाराआ के अधीन निये गये गुणवान तब तक अन्तिम नडा गा। तब तब नि नदीवस्त आयुक्त उक्त स्थापार करत।

[धारा १८०] सरस्वत का अतिरिक्त शरीर पर गुण गुने का अधिस्व — इस अधिनियम में समाहित किसी भी धान के होत गये भी, राज्य सरकार किसी भा यत्त सरकारी गात्र में निरूपित प्रकाशित कर आदेश में भन्ना है कि राज्य के किसी भी गल्ह में निवसित कोई शहरा में इस अधिनियम के अधीन निर्मित नियमा के अनुसार लगान के अतिरिक्त एक विशेष आगारिक पर देने के लिए उत्तरदाया होगा।

(च) निधि

[धारा १८१] बन्दोस्त के कय की ममाप्ति के समय बन्दोस्त अधिस्वारी के पास विचाराधीन प्रायना-पत्र एवं रायशाहियों — तब गारा १८० के अधीन निवृत्ति प्रकाशित कर किसी शत्रु में बन्दोस्त को बन्द कर दिया जाय तो उस समय बन्दोस्त अधिकारी के विचाराधीन समस्त प्रायना पत्र कायशाहिया, तब तब कि कोई श्रायी के बन्दोस्त अधिकारी नियुक्त किया जा सक यलम्बर को भन की जायेगी तो ननो निणय करने के सिलसिल में बन्दोस्त अधिकारी के अधिस्वारी को काम में ला सकेगा।

[धारा १८२] भूल चूरा का मशोधन — उपरोक्ता अध्या अध्या प्रणाली से बन्दोस्त अधिकारी किसी भूल चूरा का मशोधन कर सकना है तो कि—

(क) कर निधारण के क्षेत्र या कर निधारण के वग जनान में, मिट्टी के वर्गीकरण में और लगान दरा के विकास में धारा १५६ का उपधारा (५) के अधीन तत्समय उसके प्रस्तानों की स्वीकृति के पूरा किसी भी स्तर पर पाइ जाय, और

(ख) चोतों के लगान निधारण में धारा १६६ के अधीन ऐसे लगाना के निश्चित क्रिय जाने के पूर्ण किसी भी स्तर पर पाइ जाय।

[धारा १८३] स्वीकृत लगान दरा पर पुनर्विचार — (१) इस अध्याय में अध्या किसी विधान नियम, आज़ा या प्रपत्र में जो कि अभी गभायशील हो किसी भी बात के रहते हुये और किसी प्रतिवृत्त प्रथा सामानिक रिवाज या रीति के होते हुये भी राज्य सरकार यदि उसे धारा १५० की उपधारा (८) के अन्तर्गत बन्दोस्त के कार्य को बन्द कराने की निवृत्ति जारी करने के पूर्व यह सतोष हो जाय कि उसने द्वारा धारा १५६ की उपधारा (५) के अधीन स्वीकृत की गई लगान दरा में किसी भूल चूक के मादम होने के कारण कि तो

(क) कर निधारण क्षेत्र या कर निधारण-वग के निमाण में, रही या

(ख) मिट्टी के वर्गीकरण में रही, या

(ग) मिट्टी के किसी वर्ग के निर्मित लगान दरा के अन्विकस में रही,

मशोधन करना आवश्यक है तो आदेश दे सकती है कि ऐसी लगान-स्वीकृत दरा का बन्दोस्त अधिकारी पुनर्विचार कर।

(२) तत्पश्चात्-बन्नेस्वत अधिकारी अपने निम्न परिष्कृत प्रस्ताव निम्नान्वित प्रणाली से बनायेगा और धारा १५२ एवं १५६ के प्रावधान उसके सम्बन्ध में प्रभावशील होंगे।

टिप्पणी — यह धारा स्पष्ट करता है कि यदि जगान निवारण में कोई त्रुटि घटित हो जाय तो और बन्नेस्वत की सम्पत्ति के पूर्व कोई त्रुटि मंजूर हो जाय तो राज्य सरकार ग्राह्य हो परिष्कृत जगान दलों को लागू करने का आदेश दे सकती है।

अध्याय ६

सम्पत्तियों का निवारण

[धारा १८४] निवारण — निवारण या। टावर से प्रयोजन किसी निवारण योग्य सम्पत्ति को एक से ज़े अधिक भागों में बांटने से है और प्रत्येक भाग पर अलग अधिक हिस्से हो सकते हैं।

[धारा १८५] निवारणीय सम्पत्तियाँ — सम्पूर्ण सम्पत्तियाँ अविभाज्य वस्ति पत्र का पायेगी किन्तु शर्त यह है कि उनका विभाजन होना प्रयास अथवा अन्य रूप से निवृत्त न कर दिया जाय।

[धारा १८६] व्यक्ति जो कि विभाजन के अधिकारी होंगे — (१) विभाज्य सम्पत्ति का प्रत्येक हिस्सेदार ऐसी सम्पत्ति से अपने हिस्से का विभाजन माग सकता है।

(२) ऐसे बात में कोई हिस्सेदार सम्मिलित हो सकते हैं।

[धारा १८७] निवारण का आवेदन पत्र — विभाजन के आवेदनपत्र में निम्नान्वित निवारण होने तथा उसका साथ सम्पत्तिधारियों के वास्तविक रजिस्टर की प्रमाणित प्रतिलिपि और उसे अन्य पत्र निम्न पर कि विभाजन का अधिकार निम्न है साथ में पत्र किया जायेगा और वही सम्पत्ति के हिस्सेदार के रूप में अभिलिखित व्यक्तियों में से किसी एक या दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा साबुद्दित रूप से प्रस्तुत किया जा सकेगा।

परन्तु शर्त यह है कि जब किसी कोई हिस्सा अधिक प्रतीता के अधिपत्य में होगा विभाजन का कोई भी आवेदनपत्र चाह वह वास्तविक कर्ता द्वारा पेश किया जाय अथवा वास्तविक कर्ता द्वारा। तब तक नहीं सुना जायेगा जब तक जोना न सम्मिलित आवेदनपत्र न द दिया हो या उनमें से किसी एक को विशेषी पत्र न बनाया गया हो।

[धारा १८८] प्रार्थना पत्र कैसे प्रस्तुत हो — धारा १८८ के प्रावधानों के अन्तर्गत निवारण का आवेदन पत्र जम निम्न के क्लर्क का प्रस्तुत किया जायेगा जिसमें कि अर्जित विभाजन से न बढ सम्पत्ति स्थित हो।

किन्तु शर्त यह है कि क्लर्क ऐसे किसी प्राप्तावत्र को मुनवाई एवं निवारण के लिये किसी सचिव निवारण अधिकारी अथवा सहायक क्लर्क का जो कि जमक

अधीनस्थ हो और वतमान में उसे आवेदन पत्र की सुगन्धि एवं विनियोग के सम्बन्ध में शक्ति सम्पन्न हो, भज दगा।

[धारा १८६] विभिन्न निती में अवस्थित सम्पत्तियाँ का बटवारा — जब कोई सम्पत्ति दो या दो से अधिक चित्तों में अवस्थित हो तो किसी एक चित्त में राजस्व मण्डल के निदेशानुसार विभाजन किया जायेगा।

[धारा १८७] मागा का एकीकरण — जहाँ किसी एक ही सम्पत्ति के विभाजन के लिए विभिन्न अधिकारी प्रथम प्रथम बाद प्रस्तुत करें तो तत्पश्चात् के लिए वह सबका एकीकरण कर लिया जायेगा तथा उक्त एक ही बाद मानते हुये एक ही निर्णय से निर्णीत कर दिया जायेगा।

[धारा १८८] सम्पत्ति के विभाजन को रोकने की शक्ति — (१) यदि प्राथना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अधिकाधिकरण के किसी अन्य स्तर पर कोई पर्याप्त कारण सम्पत्ति के बटवारे की अस्वीकृति के लिए अधिकाधिकरण के स्थगित करने के लिए प्रतीत हो तो क्लर्कटर सम्बन्धित अधिकारी या महायुक्त क्लर्कटर जिसके पास उस प्राथना पत्र पेश किये गये हों या ऐसे प्राथनापत्र विचाराधीन हों विभाजन को स्थगित कर सकता है और तत्पश्चात् की आवश्यकता को समाप्त कर सकता है।

२। कोई भी सम्पत्ति ऐसी रीति से विभाजित नहीं की जायेगी कि निर्धारित किये गये क्षेत्र से कम क्षेत्रफल वाली कोई एक या एक से अधिक सम्पत्ति उससे प्राप्त हो।

[धारा १८९] विभाजन के आवेदनपत्र की घोषणा — जब विभाजन के आवेदन पत्र प्राप्त हो जाय तब यदि वे विधि संगत हुये और प्रत्यक्ष रूप में उसमें कोई आपत्तिजनक बात नहीं हुई या धारा १८८ के अधीन अस्वीकृत अधिकाधिकारी से मना नहीं किये गये हों, क्लर्कटर इस सम्बन्ध में एक घोषणा निकालते हुये विभाज्य सम्पत्ति के भागीदार के रूप में अभिलिखित ऐसे व्यक्तियों को जो उन आवेदनपत्रों में सम्मिलित नहीं हुये हों अपने मामले व्यक्तिगत रूप से प्रतिनिधि द्वारा किसी ऐसे दिन पर जो घोषणा की तारीख ३० दिन पूर्व या ६० दिन पश्चात् नहीं होंगे उपस्थित होकर और विभाजन के सम्बन्ध में अपनी आपत्तियाँ यदि कोई हों रखने का आमन्त्रण दे सकता है। घोषणा की प्रतिलिपि निर्णायक को प्रेषित की जायेगी।

[धारा १९०] टा टल के सम्बन्ध में आपत्ति — (१) यदि उक्त निश्चित दिन को अधिकाधिकरण से पूर्व किसी अभिलिखित हिस्सेदार द्वारा कोई आपत्ति उठाई जाय और उसमें स्वामित्व के टा टल का विवाद उठाया गया हो तो कि उस समय तक किसी सुलभ अधिक्षेत्र वाले न्यायालय द्वारा निर्णित न हुआ हो तो क्लर्कटर —

(क) आवेदनपत्र को स्वीकार करने में उदासीनता दिखा सकता है जब तक कि विवादास्पद प्रश्न सुद्ध न्यायालय द्वारा निर्णित न होय, अथवा

(म) किसी भी पक्षकार से आग्रह कर सनना है कि वह तीन मास की अवधि के भीतर किसी दीनानी न्यायालय में प्रश्न के निर्णय हेतु दावा प्रस्तुत कर, या

(न) साधारण तौर पर ऐसे प्रश्न के मूल्यांकन के लिए पृष्ठताद्व करने की कार्यवाही करे।

(२) जब उपपारा (१) म्यूट (ख) के अन्तर्गत कार्यवाही स्थगित कर दी जाय और यदि वह पक्षकार आग्रह के अनुसार कार्य करने में असफल रहे तो क्लर्क उस प्रश्न को उसके निरुद्ध निश्चित करेगा। यदि वह दावा ठाकर करता है तो क्लर्क दीनानी न्यायालय के निर्णय के अनुसार कार्य सम्पादन करेगा।

(३) जब क्लर्क आपत्ति के तथ्यों के सम्बन्ध में जाच पड़ताल करने की सोच तो वह मूल अभियोग के निपटारे के सम्बन्ध में दीनानी प्रक्रिया समूह, १९०८ (केन्द्रीय एक्ट संख्या ५, सन् १९०८) में प्रावहित प्रावधानों के अनुसार कार्य करेगा।

(४) उपपारा (३) के अधीन पाठित सभी द्वित्रियों दीनानी अन्तर्गत की द्वित्रिया मानी जाएंगी और उनकी अपील जिला न्यायाधीश या हाईकोर्ट में जैसी भी अवस्था हो, उन न्यायालयों की अपील के नियमों के अनुसार, वापस की जा सकती है।

[धारा १९४] अपील के निर्णय तक विमानन पर रोक — अपील की सुनवाई करने वाला न्यायालय, अपील का निर्णय होने तक, क्लर्क को विमानन को स्थगित करने का निर्देश करेगा जो कि उपरि विधि द्वारा कर सकता है। ऐसी अपील धारा १९१ (१) (ख) के अधीन किसी दीनानी न्यायालय के बाहे निरुद्ध हो या धारा १९१ के अन्तर्गत क्लर्क की अदालत के निरुद्ध हो।

[धारा १९५] विमानन के पूर्णता के पूर्व सम्पत्ति की बुरी — (१) आवेदन पत्र के किसी भी स्तर पर बोर्ड की स्वीकृति प्राप्त हुए क्लर्क सम्पूर्ण सम्पत्ति को बुरी कर सकता है और विमानन की समाप्ति होने तक सीधे अपने प्रपत्र में रत करता है।

(२) इस प्रकार की बुरी के समय सम्पत्ति से प्राप्त होने वाली रकम राजस्व के दुफार में और व्ययसा लघु में और समीक्षित रकम का इस प्रतिपात मसूदा शुल्क के लिये पहले दी जायेगी और तब वर्तमान सम्पत्ति या उसके किसी अंश पर मौजूदा भार स्वल्प किसी अन्य परवर्त्य के दुफार के लिए दी जायेगी और अग्रोप यदि कोई हो, इस मूल में हिस्से रखने वाले जागीरदारों को उनके हिस्से को अनुपात से इस प्रकार बांट दी जायेगा जैसे कि साधारण साम विभाजित किया जाता है।

[धारा १९६] तनवीन की प्रणाली — (१) क्लर्क पटवारी को निर्देश देगा कि—

(अ) वह सम्पत्ति के मानचित्र पर किसी विशिष्ट रंग से विमान्य विशेष क्षेत्र पर चिह्न लगाये,

- (ग) यह इस सम्पत्ति में मिट्टी का विशेष वर्गीकरण बनाये,
- (घ) यह विभाजन को पूर्ण करने के लिये अपने रास्ते और गली-गली और अन्य विवरणों के आवश्यक सारांश तैयार करे।
- (ण) रुद्धवारन के रूप में धारण किया गया भूखण्डों की यदि कोई हो, यह एक सूची तैयार करे।
- (ङ) यह उप धारणा की, यदि कोई हो, एक सूची बनाये,
- (च) यह विभाजन भूखण्डों के मूल्यांकन हेतु कोई प्रणाली बनाये,
- (छ) यह राजस्व तथा मूल्य सम्पत्ति समग्र विवरण द्वारा पेड़ा की एक सूची तैयार करे,
- (ज) वनभूमि की आय अथवा अन्य साधना को शामिल कर विवरण प्रस्तुत करे, और
- (झ) यह पन्ने बुझा की एक सूची यह दिखाने हुए कि वे कहाँ अवस्थित हैं, जिन गतों को सोचते हैं और जिनसे खर्चा सँभाला गया है तैयार करे।

(२) उपरोक्त काम को शीघ्रविशीघ्र समाप्त करने के लिए यदि फलन्टर उचित, समझे, पटवारी के नाचे एक अस्थायी सहायक नियुक्त कर सकता है। ऐसे अस्थायी सहायक का व्यवहार प्रशमन बादी द्वारा दिया जायेगा। और तत्परचान् बाद-परिचय में सम्मिलित कर लिया जायेगा।

टिप्पणी — यह धारा से यह स्पष्ट होता है कि विभाजन सम्पत्ति आवश्यक कार्यवाही करने के लिए कम से कम पटवारी को बतियव आदेश देगा।

[धारा १६७] सिद्धान्त के निर्धारण व मूल्यांकन की शर्तें — (१) राज्य सरकार द्वारा त्रिनिमित्त नियमों के अधीन, इस सम्पत्ति में विभाजन करने हेतु सम्पत्ति में शामिल भूमियों के समस्त वर्गों के मूल्यांकन की शर्तें एवं साधारण सिद्धान्त के निर्धारण का कार्यवाही, फलन्टर इस विचार से करेगा कि उसमें निहित विभिन्न भूखण्डों का पारस्परिक मूल्य का अनुमान न्याय सार हो। ऐसे मूल्य की भिन्नता केवल भूखण्डों के क्षेत्रफल के कारण ही न होकर मिट्टी के वर्ग सिंचाई की सुविधाएँ, उससे भूमि-धर्म की प्रगति उससे कारतकारों की व्यक्तिगत विशेषताओं और मूल्य पर प्रभाव डालने वाले अन्य कारणों के आधार पर हाँगी।

(२) मूल्यांकन की शर्तें तथा सामान्य सिद्धान्तों के निश्चित होने पर पटवारी उससे अनुसार प्रत्येक भूखण्ड के मूल्य का आकड़ा बनायेगा।

[धारा १६८] विभाजन के लिये प्राथमिक आदेश — (१) फलन्टर यदि यह उसे या उससे पूर्वर्ती किसी स्थित पर आवेदनपत्र को खण्डित न कर तो धारा १६६ द्वारा नियत पद्धतियों करने के परचान् निर्धारित प्रपत्र में विभाजन के प्रत्येक अधिकारी के हिससे की प्रकृति और मात्रा की घोषणा कर सम्पत्ति, जितनी अंशों में विभाजित होगी वनसी सत्ता निदिष्ट करते हुये और प्रत्येक अंश की मात्रा बनाते हुए एवं ऐसे विभाजन

क नियम में उदाये गये विवादग्रस्त प्रश्नों को तय करते हुए और उस प्रणाली का निश्चित विमानन विज्ञा जायेगा, विवरण दते हुये, एक प्रारम्भिक आदेश निकालेगा।

(२) क्लर्कटर किसी ऐसे आदेश द्वारा निर्देश कर सकता है कि किसी दो या अधिक दावदारा व अश, यदि व सहमत हो, विमानन के अर्थ के लिये समुक्त कर दिये जाय और उनके समुक्त हिस्से के मूल्य के अनुपात में एक अथ अग सम्पूर्ण सम्पत्ति से विला कर दिया जाय और एसी स्थिति में नरीनरुन सम्पत्ति में ऐसे हिस्सेदारा के प्रत्येक प्रथक अधिसारा के सम्बन्ध में उसी समय घोषणा करदी जायगी।

[धारा १६६] विमानन कान करगा — विमानन के प्राथमिक आदेश प्रकाशित होने पर क्लर्कटर विमानन से सम्बन्धित पक्षों को विमानन करने की आज्ञा देगा। अथवा वह उसे कार्य के पंच नियुक्त करने की राय देगा।

[धारा २००] सविदा-सम्मत विमानन — यदि परीक आपस में ही विमानन करना स्वीकार करें तो—

(ए) एक दिनांक नियत किया जायेगा और उस दिनांक तक विमानन पूर्ण किया जायेगा।

(ब) सम्बद्ध अभिलेख की ऐसी प्रतिलिपिया जो वे चाहें उन्हें मुफ्त दी जायेंगी

(ग) पटवारी को यह निर्देश दिया जायगा कि वह उनको प्राथमिक आदेश के अनुसार विमानन करने में और विमानन हिस्सों के सम्बन्ध में क्लर्कटर के सामने पेश किने जाने योग्य अभिलेख तैयार किये जाने में आवश्यक सहयोग दे।

(घ) वे नियत तारीख पर उपस्थित होंगे और उपयुक्त मातिनेयार किने गये हिस्से के अभिलेख प्रस्तुत करेंगे जिनके साथ जायदाद का नक्शा भी होगा। इस नक्शे में एम्मे अनेक हिस्सा को प्रत्येक प्रत्येक रंगों में दिखाया जायेगा जो अनेक हिस्सों में प्रदर्शित किने गये हों।

(ङ) क्लर्कटर ऐसे सभी हिस्सों पर अपनी उपस्थिति में सभी पक्षों अथवा उनके सम्बन्ध में यथारिधि स्वीकृत प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर करा लेगा और

(च) क्लर्कटर के अन्तर्गत कार्य के पूर्ण होने पर व हिस्से स्वीकार किने जायेंगे किन्तु शर्त यह है कि वे कानून के प्रावधानों के पंच प्राथमिक आदेश के अनुसार हों।

[धारा २०१] पक्षों द्वारा विमानन — (१) विमानन करने के लिय यदि पक्ष पंच नियुक्त करने पर तैय हों और पंच नियुक्त कर तो भा क्लर्कटर को विमानन को पछे पंच नियुक्त देना संच दगा।

(२) चारद्वि मन एक्ट १९४० (केन्द्रीय एक्ट संख्या १०, मन् १९४०) के प्रावधान ऐसे सविदा और पंच नियुक्त देना किये गये अधिदेश और पक्षों की नियुक्ति और

सायराहिया और उनसे द्वारा दिये जाने वाले पैसों के बारे में गणनामन्त्र परिचयन सहित लागू होंगे।

(३) धारा २०१ 'य' प्राक्धान उस प्रकार लागू होगा माना जाता है 'पचास' का अर्थ पचास प्रतिस्थापित किया गया हो।

(४) व्यक्तिगत तौर पर पंच का क्लर्क के समान उपस्थित होना और अपने फैसले प्रस्तुत करना अथवा क्लर्क के सामने उस पर या बात कही गई हो पर हस्ताक्षर करना आवश्यक नहीं होगा किन्तु फैसले और हिस्सा पर वह स्वयं हस्ताक्षर करेगा न कि किसी स्वीकृति प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षर करायगा। ऐसे हस्ताक्षर क्लर्क के समान उनसे प्रस्तुत किये जाने के पहले दिये जायेंगे।

[धारा २०२] न्यायानय स्वयं क्या विभाजन करेगा? — न्याय पत्र परस्पर विभाजन करने पर अथवा उस सम्बन्ध में पत्र निर्णय करने में एक मत न हो अथवा न पत्र निष्पत्ति अधिलिखित कर दिया जाय अथवा फैसला यह कर दिये जाय तो क्लर्क स्वयं विभाजन के विषय में निर्णय देगा।

[धारा २०३] विभाजन व्यय का अनुमान और उमकी गड़ली — (१) न्याय पत्र के अधीन क्लर्क स्वयं विभाजन करने का तय करले ता वह शास्त्रानुसार खर्च के अनुमान का वायदागी करेगी और निम्न दूनी कि ऐसे स्वयं प्रथमतः विभाजन के प्रार्थी अथवा सभी हिस्सेदारों से ऐसी किराना में और विभाजन की प्रगति के क्रमिकान ऐसे अवकाशों पर जो कि राज्य सरकार निध रित कर उसल किया जावेगा।

(२) यदि पूरा अनुमानित रकम अपयत्न पाई जाय तो पूरक अनुमान समय समय पर लगाये जा सकने हैं और उपरोक्त रीति में से ऐसी अनिश्चित रकम उसल की जायेगी।

(३) राज्य सरकार ऐसी मन्त्र के निर्देश सहित जो कि ऐसे विभाजन के खर्च के निष्पत्ति में अथवा उससे लिये सम्मिलित किये जाय नियम बनायेगी और राजस्व मण्डल में खर्चा के वितरण के विधान के निष्पत्ति के लिये नियम बनायेगी।

[धारा २०४] प्रमीन आदि की नियुक्ति और वारण्ट जारी करना — न्याय विभाजन के सम्बन्ध में आखिरी खर्च आदि जमा कर दिय जाय तो एक प्रमीन अथवा अन्य उपयुक्त व्यक्ति विभाजन के कार्य के सम्पादन हेतु नियुक्त किया जावेगा और उस कार्य के लिये क्लर्क उसने नाम के कमिशन वारण्ट प्रसारित करेगा तथा उसे ममरन आवश्यक पत्र तथा सूचनाओं प्रदान करेगा।

[धारा २०५] वारण्ट निष्पादन की प्रणाली — (१) प्रमीन अथवा अन्य व्यक्ति उपरोक्त रीति से विभाजन के लिये नियुक्त किया गया हो कमिशन वारण्ट की प्राप्ति पर —

(१) बायरी रंगेगा और उसमें वह चारट प्राप्त की तारीख, उसने निष्पादन हेतु उस द्वारा किया गया दिन प्रतिदिन का विवरण, उस कार्य के लिये निरीक्षित स्थान उसने समस्त प्रस्तुत किये गये दाव एवं आपत्तियाँ ऐसे व्यक्ति एवं विधान निनके द्वारा एवं जिस भाति व प्रस्तुत की गई और उस सम्बन्ध में दिय गये निर्णय के कारण प्रविष्ट किया जायेंगे।

(२) व्यक्तिगत निराक्षण का कार्यक्रम उनायेगा और पनसारा को तत्सम्बन्धी एवं पम्बाड का नोटिस देगा।

(३) प्राथमिक आदरा की निम्नलिखितों के अनुसार निम्नमें प्रत्येक अंश व अन्तर्गत पम्ब लखड बनाये जाने का विधान किया हो कि जिनमें जायदाद प्रितरित होगी एवं प्रयोगात्मक मूची तैयार करेगा और उसे रिनाई पर रखेगा।

(४) उपरोक्त कार्यक्रम के अनुसार सम्बद्ध स्थल पर जायेगा, स्थल निरीक्षण करेगा, पक्षकारों को, यदि उपस्थित हों, सुनेगा और उनकी आपत्तियाँ पर विचार करेगा सम्पत्ति का उद्धार किय जाने जान अथवा से सम्बन्धित सभी व्याक्तियों को एकत्र करेगा निम्नमें वे जुगानी या लिमिन में अपने दाव अथवा आपत्तियाँ प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त कर सकें और जमी चण्ड पर लम्बरदारा की उपस्थित में पम्बे गये एवं आपत्तियों का फैसला करेगा।

(५) ऐसा अमीन या व्यक्ति तब चारट को अपने प्रतिवेदन के साथ लख देगा जिसमें वह चारट के द्वाराय की प्रणाली प्रस्तावित विभाजन लखड, ऐसा व्यक्ति या पम्बे व्यक्ति जो वह धारण किये हों और पम्बे भ्रमराध सरिता पट्टे अथवा अनुभाषन निम्न अमीन व प्रहण किये गये हैं, सभी का उसने उल्लेख होगा, प्रतिवेदन के साथ पम्ब किये जायेंगे —

(क) उपधारा (१) के लखड (१) के अन्तर्गत रानी गई मूल बायरी

(ख) एक रगीन नम्बरा निम्नरा सदम धारा २०० के लखड (घ) में दिया गया है और

(ग) ऐसे अन्य विवरण-पत्र एवं लख निम्नमें बोर्ड द्वारा निशचित विवरण हों।

टिप्पणी — यह धारा लखड करती है कि बटवारे की बार्डवाही सम्पूर्ण करने व विषय पम्बन अथवा का दूसरा व्यक्ति भेजा जायेगा। यह सम्बन्धित पम्बारा को बुनाकर उनका प्राप्तिगी पम्बगा। अमीन की बार्डवाही इस धारा के अनुसार प्रविष्ट नही है।

[धारा २०६] घोषणा करना — धारा २०५ की उपधारा (२) के विम्ब प्रस्तुत करने के लिये, पम्बी रिपोर्ट की प्राप्ति पर कन्स्टट एवं घोषणा सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को उस पर लिख निम्नित बोर्ड तारीख पर हाजिर होने के लिये एवं अपने दावे अथवा आपत्तियाँ, यदि कोई हों जारी करेगा और पम्बी घोषणा की प्रविष्टिपदा सम्बन्धित प्रीपेन को अपनी आपत्तियाँ यदि कोई हों, घोषणा के तामीन व पम्बान पम्ब निम्न की अरवि के अन्तर्गत प्रस्तुत करने के लिये भेजेगा।

[धारा २०७] प्रस्तावों पर विचार तथा दावों एवं आपत्तियों का निरूपण,—
निर्दिष्ट तारीख पर प्लान्टर

(ए) घम से मुनेगा तथा फैसला करेगा—

(१) पक्षधारा द्वारा उठाई गई आपत्तियाँ और,

(२) अन्य व्यक्तियों द्वारा पेश किये गये दावे एवं आपत्तियाँ और

(ए) तब यह दर्खों के लिये प्रस्तावों की परीक्षा करेगा कि वे प्राथमिक आदेशों की शर्तों के अनुसार हैं और कानून पर प्रावधानों का पूर्ण करत है।

[धारा २०८] कृषक की जेत या विभाजन —यथा समस्त कारनकार की जेत का घंटघारा नहीं किया जायेगा और नही ऐसा करना अनियमित है, प्रत्येक जेत का लगान उनके हिस्सों पर बांट दिया जायेगा।

[धारा २०९] खुद कारत की भूमि —ऐसी भूमि जिसमें खुद कारत के अधिकार पैदा हो गया हो और वर्तमान में मौजूद हों, अलग से विभाजन का जायेगी ताकि प्रत्येक विभाजन अश मूल्य के समानता रखने वाले अथ हिस्से के अनुपात में अश के रूप में आवंटित किया जा सकेगा।

[धारा २१०] सयुक्त भूमि का आवंटन —धारा २०९ में उल्लिखित भूमि के अलग सयुक्त भूमि का आवंटन इस ढंग से किया जायेगा कि प्रत्येक भाग को उसका ऐसा अश प्राप्त हो जो कि उसको बनाने वाले या अश या अशों के मूल्य अनुपात में बँटना हो।

(२) धारा २०९ में उल्लिखित भूमि के अलावा भिन्न भिन्न व्यक्तियों द्वारा धारण की गई भूमि यथा समस्त उनको धारण करने वाले हिस्सेदार या हिस्सेदारों के मध्य विनिरित करदी जायेगी।

[धारा २११] आवंटित भूमि पर निजी हिस्सेदार का मकान या बाड़ा आदि —जब विभाजन में हिस्सेदार या हिस्सेदारों को दिये जाने वाले हिस्सों में किसी अन्य हिस्सेदारों के आधिपत्य में स्थित किसी रहने के मकान अथवा अन्य भवन अथवा बगीचों या घाटिकाओं द्वारा घेरी गई भूमि का सम्मिलित किया जाता आवश्यक हो या जो ऐसे अन्य हिस्सेदारों के लिये वहाँ पर उसके व्यवसाय से किये गये विकास के फलस्वरूप कोई विशेष मूल्य रखते हों तो तब वाला व्यक्ति आउटड-रेण्ट देने के परवाना ऐसी शर्तों, ऐसे बगीचों एवं घाटिकाओं एवं विकासों द्वारा आवंटित भूमि को धारण कर सकेगा। ऐसी भूमि एवं तत्सम्बन्धी लगान की सीमा प्लान्टर तय करेगा और ऐसे सब मामलों में यथा समस्त एक नियत किया गया भाग बनाना, बगीचों घाटिकाओं अथवा विकासों के किसी भी अवस्था हो, मालिक के लिये आम सड़क से वहाँ पहुँचने हेतु सुरक्षित करेगा अथवा किसी अन्य संपत्ति का कोई अश उसे अलग से आवंटित किया जायेगा।

(ग) प्रत्येक भागीदार के हिस्से की प्रकृति एवं सीमा के विवरण सहित ऐसे भागीदार का विवरण लग्न जहा कोई खण्ड एक से अधिक भागीदारा के हिस्से का प्रतिनिधित्व करता हो, और

(घ) उपरोक्त रीति से विभाग सिद्धित खण्ड पर प्रत्येक भागीदार अथवा वह भागीदारी द्वारा व्यक्तिशः अथवा सामंजस्य से वसूली प्राप्त करने के सम्बन्ध में अधिकार एवं अधिकार ।

(२) किसी अधीनस्थ अधिकारी द्वारा, जिसे धारा १८६ के प्रावधान के अन्तर्गत यदि अंतिम आदेश के लिए मामला सौंपा गया हो तैयार किया जायेगा, यह क्लर्क को पेश किया जायेगा जो आदेश की पुष्टि कर सकता है या रद्द कर सकता है या परिवर्तित कर सकता है या अधिकृत पड़ताल करने पर अथवा अनिश्चित साक्षी सुनने का निर्देश कर सकता है अथवा स्वयं ऐसी पड़ताल करता है अथवा साक्षी ले सकता है अथवा नई तनवीर स्थापित कर उन्हें नियंत्रण के लिए भेज सकता है

परन्तु पुष्टि का कोई भी आदेश उस सम्बन्ध में प्रस्तुत की जा सकने योग्य अपील की अधि के समाप्त होने के पूर्व पास नहीं किया जायेगा या यदि कोई निपटारा न कर दिया जाय ।

एक शर्त यह भी है कि उस आदेश को परिवर्तित करने या रद्द करने का आदेश दिया जायेगा और न अधिक पड़ताल करने या साक्षी लेने का आदेश दिया जायेगा न तब कि उस आदेश का समर्थन के लिए पक्षकारों को सुनना अथवा ऐसी जांच पड़ताल या साक्षी के वक्त उनकी प्रतिनिधित्व का एक अरसर न दे दिया जाय ।

[धारा २१७] नद्वारे के कागजात —(१) जायदाद के विभिन्न खण्ड के सम्बन्ध में, क्लर्क, बंटवारा के कागजात अंतिम आदेश की शर्तों के अनुसार, प्रार्थी अथवा प्रार्थियों के जैसी भी दशा हो जिनके हिस्सों का वे खण्ड प्रतिनिधित्व करते होंगे पक्ष में तैयार करवायेगा और उनमें विभाजन के लागू होने का दिन दर्ज करायेगा तथा ऐसे प्रत्येक कागजात पर केन्द्रीय धारा सभा के भारतीय स्टाम्प एक्ट १८६६ (एक्ट संख्या २ सन १८६६) की जैसा कि राज्य में प्रहित हुआ है, अनुसार स्टाम्प लगेगा ।

(२) ऐसी तारीख जब तक अथवा निर्देशित न किया जाय अंतिम आदेश की पुष्टि नये जाने के बाद या अंतिम आदेश के क्लर्क द्वारा जारी किये जाने के तत्काल बाद आने वाले जुलाई माह का प्रथम तारीख मानी जायेगी ।

(३) जिस दिनांक में बंटवारा लागू होगा, इस भाति विभाजित प्रत्येक खण्ड सभी अभिप्रायों के लिए स्वतंत्र जायदाद समझी एवं प्रयुक्त की जायेगी मानों कि वे ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के पक्ष में जिनके हिस्से या हिस्सा का उससे प्रतिनिधित्व होता हो वह मूल रूप से ही स्वतंत्र जायदाद के रूप में निमित्त हो ।

(४) बंटवारा के कागजात तैयार होने पर क्लर्क वापिकर रजिस्ट्रार का तदनुसार सुधार करेगा और भूमि अभिलेख में आवश्यक प्रविष्टियां करने के लिए बोर्ड को सुधारिश करेगा ।

[धारा २१८] विभाजन पर आगटित सम्पत्ति का रज्जा देना — विभाजन के दस्तावेज में जिस व्यक्ति या व्यक्तियों को कोई भूमि आगटित की गई हो, विभाजन के अथ पत्रकारों और उनके वैधानिक प्रतिनिधियों के विरुद्ध उस सम्पत्ति में अलग बहना पान का अधिकारी होगा और कलक्टर धारा २१७ की उपधारा (१) के अन्तर्गत पट्टवार व कागजातों में उल्लिखित ताराख के गठ तीन साल की अवधि के अन्दर ऐसे व्यक्ति द्वारा आवेदनपत्र दिये जाने पर उस दस्तावेज को प्रभावशाली घोषित करेगा मानो कि यह अवलम्बित पर कब्जा दिलाने के लिए दिवानी अदालत द्वारा पास की गई कोई निका हो।

[धारा २१९] सम्मिलित सम्पत्तियों का पट्टागार — जब किसी सम्पत्ति में दो या दो से अधिक गांव या गावों के खण्ड सम्मिलित हो तो राज्य सरकार उसके विभाजन को प्रशासनिक सुविधा के लिए अनिवार्य सम्पत्तियों में किये जाने का निर्देशन कर सकती है। ऐसे निर्देश की प्राप्ति पर कलक्टर सम्बन्धित सम्पत्तिधारियों द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्रों पर विचार करने के बाद, इस अधिनियम के अन्तर्गत निर्मित नियमों के अनुसार उस जायदाद का राजस्व ऐसी जायदाद पर वितरित कर दगा और तदनुसार वापिस पत्रिका में सुधार करेगा। इस प्रकार प्रत्येक प्रत्येक निर्मित जायदादों उन पर आरोपित राजस्व के लिये उत्तरदायी होगा।

[धारा २२०] राजस्व का प्रयोजनात्मक अथवा आमन वितरण — इस अध्याय के अधीन वितरण करते समय जब राजस्व किसी भ्रम या छल के कारण गलत वितरित हो जाय तो कोई, किसी भी समय मूल सम्पत्ति के राजस्व की ऐसी अनेक जायदादों पर जिनमें यह बांटी जाय, वितरित करने हेतु आदेश दे सकता है नैसा कि छल या भ्रम के रहित होने पर विभाजन की स्थिति होनी है।

[धारा २२१] कम निर्धारित सम्पत्तिया अधिक निर्धारित से वापिस लौटा देगी — धारा २२० के अधीन किसी भी मामले में कोई निर्देश दे सकता है कि कोई भी स्थानीय जिसकी सम्पत्ति पर अनु निवारण हुआ हो प्रत्येक अधिक से अधिक तीन वर्ष तक, उनके साथ यह अपनी अलग जायदाद का अधिपति रहता है किन्ती अन्य जायदाद पर जिस पर अधिक निर्धारण अभिलिखित स्थानों को ऐसी रकम जितनी पुर्य लिखित जायदाद न्यून निर्धारित पाई जाय, देने के लिए बाध्य होगा और उसका भुगतान नहीं किया जान पर उसको अदायगी राजस्व के गणन के अनुसार की जायगी और उस स्थानी को ही जायेगा जो कि उसका अधिकारी होगा।

(२) इस धारा के अधीन किये गये किसी भी हुक्म के बारे में कोई भी प्रश्न दिवानी अथवा माल अदालत में नहीं उठाया जायेगा।

[धारा २२२] एक गांव की विभिन्न सम्पत्तियों का एकत्रीकरण — जब दो या दो से अधिक राजस्व भुक्तने वाली सम्पत्तिया किन्ती गांव की मोता में हूँ, या सम्बन्धित

सम्पत्तिधारी उनही एक सम्पत्ति में क्लैमरिंग न किया क्लैमर में प्राप्त कर मन्त्र है और क्लैमर अपन विरा में ऐसी प्राप्ति को स्वीकार कर सक्ता है तथा ऐसे मामला में तत्पुनार वार्षिक रजिस्ट्रो में भी परिवर्तन करेगा।

[धारा २२३] सरकार एक सम्पत्तिधारी के मध्य में होने वाले विभाजन के सम्बद्ध यह अध्याप लागू नही होगा — (१) किसी सम्पत्ति के धारण करने वाले एक सरकार के बीच, इस अध्याय के प्राधान लागू नहीं होंगे और न ही कभी ऐसा विभाजन जन्म ही जायेगा क्लैमर में विभाजन करेगा।

परन्तु शत यह है कि क्लैमर के प्रभाव राज्य सरकार न सम्पत्ति के लिये जो द्वारा भजे जायेंगे।

(२) ऐसा प्रत्येक विभाजन इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा निमित्त नियमों के अनुसार किया जायेगा।

अध्याय १०

राजस्व संग्रह

[धारा २२४] भूमि और उसके उत्पादन पर प्रथम भार के रूप में राजस्व — (१) प्रत्येक सम्पत्ति अथवा जोत पर उसके निर्धारित राजस्व अथवा लगान और उसके किराया, लाभों अथवा उपज पर प्रथम भार होगा।

(२) ऐसी सम्पत्ति अथवा जोत के लगान लाभ व उत्पादन किसी भी कीमती अथवा राजस्व व्यापार के आदर्श अथवा डिग्री के भुगतान हेतु काम में तब तक नहीं लिये जायेंगे जब तक कि उस सम्बन्ध में शेष राजस्व अथवा लगान की समस्त रकम न चुका दी जाय।

[धारा २२५] राजस्व का उत्तरदायित्व — किसी सम्पत्ति के सभी हिस्सेदार और धारणकर्ता सम्मिलित तौर पर और व्यक्तिगत तौर पर क्लैमर राज्य सरकार को देय राजस्व के लिये उत्तरदायी होंगे।

(१) किसी सम्पत्ति पर स्थित किसी जोत के सभी कृषक और हिस्सेदार वर्तमान में राज्य सरकार को देय राजस्व के लिये सम्मिलित तौर पर से और निजी तौर से उत्तरदायी होंगे।

(२) किसी सम्पत्ति अथवा किसी जोत का आधिपत्य प्राप्त करने वाले सभी व्यक्ति उनके ऐसे कर्जे प्राप्त करने वाले व्यक्ति से राजस्व अथवा लगान के सभी अवशेषों के लिये उत्तरदायी होंगे।

(३) इस अध्याय में प्रयुक्त अभिव्यक्ति भूमिधारा अभिप्राय किसी ऐसे व्यक्ति से होगा जो स्वतः के लिये कृषि धारण करता हो और भूमिधारी न अधिकार का पट्टेदार भी उसमें शामिल होगा।

[धारा २२६] अवशेषों के भुगतान के नियम और दोषी—राजस्व अथवा लगान ऐसी शर्तों में ऐसे समय और ऐसे स्थान पर तथा ऐसी रीति से ऐसे व्यक्तियों को दिया जायेगा जो निर्धारित किये जाय और इस, प्रभार नहीं भुगतान प्रत्येक रकम लगान अथवा राजस्व के अयरोप कहलायेंगे अथवा उसके सम्बंध में उत्तरदायी व्यक्ति दोषी कहलायेंगे।

किंतु शर्त यह है कि जब तक राज्य सरकार अथवा निर्देशन के तत्समय राज्य सरकार को भुगतान-योग्य राजस्व या लगान का भुगतान सकल के पटवारी की मार्फत, किया जायेगा।

[धारा २२७] प्रमाणित हिमाय अवशेषों की माफी होना — तहसीलदार द्वारा प्रमाणित हिमाय का विवरण पत्र इस अध्याय के अधिप्रायाग अयरोप की रकम के समय में और उससे समय दोरा व्यक्ति के बार में प्रमाणित माफी होगा। किंतु शर्त यह है कि इस धारा की फाइल ऐसे व्यक्ति के द्वारा भुगतान किये जान के हक पर और इतनात्र एउ प्रत्येक कार्यवाही के द्वारा कलक्टर के सामन हिसाब के सुधार सम्बंध प्रान रवान के हल पर कोई इनिफर प्रभाव नहीं-डालगा।

[धारा २२८] दातव्यों की बचनी की कार्यवाही — राजस्व या लगान के दातव्य निर्माकित किसी एउ या अधिक प्रणालियों द्वारा बसूल किये जायेंगे—

- (क) किसी दोषी पर मागपत्र अथवा उपस्थित पत्र की तामील द्वारा
- (ख) उसकी चल सम्पत्ति की कुर्सी और बिक्री द्वारा
- (ग) किसी निर्धारित क्षत्र हिस्सा पट्टी अथवा सम्पत्ति जिसके बारे में ऐसे दातव्य हो कुर्सी द्वारा,
- (घ) ऐसे हिस्से या पट्टी को निम्नी साम्य वाले हिस्सेदार को हस्तान्तरित करके।
- (ङ) ऐसे किसी निर्धारित हिस्से या पट्टी अथवा सम्पूर्ण, सम्पत्ति का बिक्री द्वारा,
- (च) दोषी की अथ किसी अचल सम्पत्ति की बिक्री द्वारा किंतु शर्त यह है कि स्वयं (ङ) के प्रावधान निसा जागीर भूमि अथवा भूमिधारक की सम्पत्ति पर लागू नहीं होगा।

[धारा २२९] मागपत्र एउ उपस्थिति पत्र — यदि राजस्व अथवा लगान का कोई दातव्य गेप हो एक मागपत्र उसमें उल्लिखित नारीस तक बरगारा रकम चुकाये जान के निर्देश सहित दोषी पर तामील कराया जायेगा अथवा एक उपस्थिति-पत्र उसमें उल्लिखित नारीस पर उपस्थित होने बाकत, उस पर जारी किया जायेगा।

[धारा २३०] चल सम्पत्ति की कुर्सी एउ बिक्री — कलक्टर नेयी व्यक्ति की चल सम्पत्ति को कुल कर सकता है और बेच सकता है। इस धारा के अन्तर्गत निर्देशित प्रत्येक कुर्सी और बिक्री भी किन्तु दातव्यी अदायग की बिक्री के अतगत चल सम्पत्ति की कुर्सी एवं बिक्री के विषय में लागू विधि के अनुकूल की जायेगी। नाना

दीवानी १९०८ (केन्द्रीय एकक सन्ध्या ४ मा १९०८) की धारा ६ के प्रविधियों में बताया गये विवरण के अलावा इस धारा के अंतर्गत नहीं लगे हुए मंथन कार्यों के लिए अलाव की गई वस्तुओं की भी कुर्सी एवं धिरी से मुक्त रखा जायेगा। वहीं एवं धिरी का स्वयं राजस्व या लगान के मतालबे में जोड़ दिया जायेगा और इसी भाँति वगूली योग्य रहेगा।

(धारा २३१) भूमि की कुर्सी —(१) पहले निर्दिष्ट किसी भी प्रविधा को छोड़ कर अथवा उससे बचाव क्लस्टर निर्दिष्ट क्षेत्र हिस्से पट्टी अथवा जागदाद की, निम्न सम्बंध में ऐसा मतालबा जंग रह कर मरुता के नीचे अपने प्रबंध के अंतर्गत ले सकता है और ऐसी कुर्सी उस समय समाप्त हो जायेगी जब सभी दानव्य चुस्त हो जायेंगे।

(२) दात्यों के चुस्त होने के पश्चात् माली को छोड़ दिया जायेगा और प्राप्त किया गया अधिस्वय यदि कोई हो, दोषा को अथवा उसके बीच प्रतिनिधि को दे दिया जायेगा।

[धारा २३२] उत्तरी क अधिस्वय और आभार —क्लस्टर जहाँ कोई भी माली प्रत्यक्ष प्रबंध के अधिन हो उसकी कुर्सी के समय दोषा और कारनकारों के बीच वर्तमान प्रत्येक माली को मानने के लिए बाध्य होगा और इसी प्रकार कुर्सी की गई सम्पत्ति के प्रबंध हेतु शक्ति सम्पन्न होगा और उससे प्राप्त होने वाले सभी कार्यों एवं लाभों को वासनेगा। इस प्रकार कुर्सी की गई सम्पत्ति से उत्तर रकम कुर्सी के बाँट शेष रहने वाले राजस्व या लगान की शर्तों की अदायगी में और कुर्सी के प्रबंध व्यवस्था में लगाई जायेगी और शेष रकम ऐसे दातव्य के चुकाने हेतु काम में ली जायेगी, जिनके कारण वह कुर्सी की गई हो।

[धारा २३३] कुर्सी की घोषणा —(१) धारा २३१ के अंतर्गत जब क्लस्टर कोई जमीन हट कर रहा है, वह इस सम्बंध में एक घोषणा करेगा।

(२) ऐसी घोषणा की तारीख के पश्चात् अथवा ऐसी अधिम तारीख के पूर्व ही उस भूमि के लगान के बतौर अथवा ऐसे अथवा लाभ हेतु देय रकम अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को दिये जाने पर उस सम्बंध में क्लस्टर का चुनाव करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति ऐसी उत्तरदायिता से मुक्त नहीं होगा।

(धारा २३४) दोषी, क मा १ का हस्तांतरण —(१) जब किसी सम्पत्ति के भाग या पट्टे के विषय में कोई दातव्य शेष हो तो क्लस्टर पहले निर्दिष्ट तरीका के अलावा अथवा उनकी बचाव राजस्व मण्डल की पूरा स्वीकृति लेने पर ऐसे हिस्से या पट्टे को ऐसी स्वीकृति के तत्काल बाद, प्रथम जुलाई में अधिस्तम १० घण्टे के लिए किसी एक अथवा अधिक सामीदारों को, जिनमें सम्पत्तिधारी सम्मिलित नहीं होगा दानव्य चुकाने की शर्तों और ऐसी शर्तों पर जो छोड़ माफ़ने में निर्धारित करे हस्तांतरण कर सकता है और ऐसे हस्तांतरण से उस सम्पत्ति के सम्बंध में वह लागू होगा, सामीदारों की निजी और सम्मिलित उत्तरदायित पर किसी भाँति प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(२) जय हस्तान्तरण की अवधि समाप्त हो जाय तो वह हिस्सा या पट्टे सम्बन्धी सम्पत्तिधारी को सरकार अथवा ऐसे हिस्से या पट्टे के सम्बन्ध में शेष रकम व हस्तान्तरण ग्रहीता के प्रत्येक दावे से मुक्त कर लौटा दी गई समझी जायगी।

[धारा २३५] दोषी के निर्दिष्ट इन्के, पट्टी या सम्पत्ति का विक्रय — कलक्टर की राय जब यह हो कि पूर्वाङ्कित प्रणालियाँ दातव्य की वसूली के लिए पर्याप्त नहीं होंगी तो उन सभी या उनमें से किसी प्रणाली के धज्जाय अथवा उनमें से या उनमें प्रतिरिक्त किसी निर्दिष्ट क्षेत्र पट्टी या सम्पत्ति जिसके सम्बन्ध में ऐसे दातव्य देय हों, के विक्रय नीलाम द्वारा कर सकता है परन्तु शत यह है कि कोई भी अन्य निर्दिष्ट क्षेत्र पट्टी या सम्पत्ति किसी ऐसे दातव्य के लिए नहीं विभज्य किये जायेंगे जो कि उपार्जित हुई हो, जब कि वह सम्पत्ति—

(क) कोट आफ वाडस के अन्तर्गत हो, अथवा

(ख) कलक्टर के प्रत्यक्ष प्रबन्ध में रही हो।

[धारा २३६] भूमि का विक्रय मार मुक्त होगा—विगत धारा के अन्तर्गत बची गई भूमि तत्काल समस्त भारों से मुक्त कर दी जायेगी और कंता के प्रतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ऐसे भूमि के सम्बन्ध में पूर्व से किया गया सभी अनुबंध नीलाम के समय कंता के विफल पर निष्प्रभाव हो सकेंगे।

(२) उपधारा (१) की कोई वस्तु रहवासी गृह बनाने के लिये या शिल्प निर्माण के लिए अथवा उपवन, तालाब, नहर, पूजास्थान अथवा मरघट अथवा कब्रगाह बनाने के लिए वास्तविक अस्थायी अथवा निरन्तर पट्टा के अन्तर्गत धारण की गई भूमि पर लागू नहीं होगी और ऐसी भूमि ऐसे पट्टों में उत्सिखत बायों के लिए काम में ली जाती रहगी।

(३) उपधारा (१) में किसी वस्तु के रहते हुए भी राज्य सरकार विक्रय के पूर्ण होने के पूर्व यह निर्देश कर सकती है कि किसी, भूमि के धारणकर्ता द्वारा अथवा ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसके सम्बन्ध में उत्पन्न ऐसा हिस्सा या अधिकारी के अन्तर्गत जिन्हें यह उचित समझ, की जाय।

[धारा २३७] दोष से अमम्यद्ध सम्पत्ति में निहित दोषी के हितों के निम्न कार्यवाही — (१) जब उपरोक्त प्रणालियाँ द्वारा किसी में अवशेष वसूल नहीं हो सके और दावी किसी अन्य सम्पत्ति के किसी भाग का अथवा सम्पत्ति का अथवा किसी अन्य अचल सम्पत्ति का स्वामी हो या उसमें कोई हित रखता हो, तो कलक्टर ऐसी सम्पत्ति या उसके भाग या उस अचल सम्पत्ति के विरुद्ध इस प्रकार कार्यवाही करण माने वह ऐसी भूमि हो जिसके विषय में इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत राजस्व अथवा संपाल दातव्य हो किन्तु शत यह है कि दावी के प्रतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के हितों पर ऐसी रीति से प्रभाव नहीं डाला जायगा।

(२) राजस्व या लगान के अवशेषों के रूप में यमुन की जाने वाला घनराशि जो कि किसी विशेष भूमि के सम्बन्ध में दातव्य नहीं है, इस धारा के अन्तर्गत आना की किसी अचल सम्पत्ति के विरुद्ध बायबाही कर वसूल की जा सकती है ।

[धारा २३८] विक्रय की घोषणा — (१) जब धारा २३८ व अथवा २३७ के अधीन किसी भूमि अथवा अचल सम्पत्ति के विक्रय का आदेश पारित कर दिया जाय तो कलक्टर ऐसे नियत विनय का एक घोषणापत्र बेची जाने वाली भूमि पर निर्धारित राजस्व व ऐसे अवशेष जिनके लिए बरी जा रही है विनय का समय और स्थान, भूमि के भार सहित या भार मुक्त बेची जान पर ऐसे अथ विवरण सहित जो कलक्टर आवश्यक समझे एक घोषणा निकाली जायगी ।

(२) उपधारा (१) के अन्तर्गत जारी की गई घोषणा की प्रतिलिपि दोषी पर निकाली जायेगी ।

[धारा २३९] विक्रय कब और किसके द्वारा होगा ? — (१) इस अध्याय के अधीन प्रत्येक विक्रय एक कलक्टर द्वारा अथवा उस सम्बन्ध में विशेष रूप से उसके द्वारा नियुक्त सहायक कलक्टर द्वारा किया जायगा ।

(२) कोई भी विक्रय रविवार अथवा अन्य स्वीकृत छुट्टी के दिन अथवा घोषणा निकाले जाने के दिन के पश्चात् ३० दिनों की समाप्ति के पूर्व संपादित नहीं किया जायगा ।

(३) समय समय पर कलक्टर विक्रय को स्थगित कर सकता है ।

[धारा २४०] विक्रय के सम्बन्ध सम्पत्ति पर बोली लगाने और उनके ग्रहण करने पर निषेध — किसी ऐसे विक्रय के सम्बन्ध में कोई कतय पूरा करने वाला कोई भी पदाधिकारी और ऐसे अफसर के अधीन या उसके द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष किसी भी विक्रय का जाने वाला सम्पत्ति जो उसमें निहित किसी प्रत्यक्ष हित के विक्रय में काट आफ वाइड अथवा राज्य सरकार के निमित्त अवस्था के अलावा कोई बोली नहीं लगायगा और न उसे ग्रहण करने का प्रयास करेगा ।

[धारा २४१] विक्रय को रोकना — जब दोषी ऐसा बकाया जिसके बारे में कोई भूमि या अन्य अचल सम्पत्ति बेचे जाने का हो उसके विक्रय के दिन के पूर्व कलक्टर की अथवा राजस्व या लगान के चक्राने को प्राप्त करने के लिए नियुक्त व्यक्ति को अथवा ऐसे सहायक कलक्टर को जो कि ऐसे सब डिजिज का कार्याधिपति है या जिसमें वह जमीन या अचल सम्पत्ति स्थित हो उसे शेष ग्रहण का भुगतान करेगा तो विक्रय को रोक दिया जायगा ।

[धारा २४२] खरीददार द्वारा धरोहर रखना व उसके अभाव में पुनर्विक्रय — खरीददार के रूप में घोषित व्यक्ति को उसकी बोली की रकम की २५

प्रतिशत शीघ्रतरनर अमानत रखनी होंगी और उससे न रखे जाने पर भूमि अथवा धन अचल सम्पत्ति तदुपरान्त दुवारा नचा जायेगी और ऐसा व्यक्ति प्रथम विषय के सन हतु और द्वितीय विषय से प्राप्त मूल्य के कारण उत्पन्न अमान के लिये उत्तरदायी होगा और एसी रखन बलमन्दर द्वारा राजस्व के अग्रोप के रूप में उससे वसूल की जायेगी ।

[धारा २४३] क्रय के मूल का चुकाया जाना —(१) नय वनराशि का पूरा श विषय की तारीख के १५ वें दिन या उससे पूर्व क्रेता द्वारा कलमन्दर के कार्यालय में चुकाया जायेगा ।

(२) जब क्रय-राशि इस भाति न चुकाई जाय तो विषय का वय चुकाने के परचान् धरोहर की शेष रकम राज्य सरकार द्वारा जप्त करली जायेगी और दोरी कृपा की उस सम्पत्ति में से अथवा तत्परचान् प्राप्त विषय राशि के किसी हिस्से से सम्बन्धित सभा दाव भी जप्त हो जायेंगे ।

[धारा २४४] पुन विषय से होने वाली हानि के लिए क्रेता का दायित्व —जब ऐसे विषय की राशि निम्ने फलस्वरूप पुनविषय किया जाय ऐसे अभियुक्त क्रेता द्वारा लगाद गई होती। की कीमत से कम हो तो वत्सम्ब की अन्तर उससे राजस्व के अग्रोप के रूप में वसूल किया जायेगा ।

[धारा २४५] पुनविषय के पूर्व घोषणा —धारा २२६ के अन्तर्गत लिये गये स्थगन व परचान् फोड़ भी विषय या धारा २२७ के अन्तर्गत क्रय राशि के भुगतान नहीं किये जाने पर फोड़ भी पुनविषय तब तक नहीं किया जायेगा जब तक मूल विषय के लिये निधारण प्रणाली से नवीन घोषणा नहीं करदा जाय ।

[धारा २४६] अग्रोप के जमा होने पर विषय को निर्मूल करने का आवेदनपत्र —इस अधिनियम के अन्तर्गत वेच की गई किसी व्यक्ति की भूमि या चल सम्पत्ति उसके विषय की तारीख के बाद ३० दिन की अवधि के अन्तर्गत कलमन्दर के कार्यालय में निम्नांकित रकम जमा करा कर विषय को निर्मूल करने हतु आवेदनपत्र प्रस्तुत कर सकता है —

- (क) क्रेता को देय रकम जो क्रय राशि के प्रतिशत के बराबर हो,
- (ख) अग्रोप के सम्बन्ध में देय रकम के निम्नलिखित विषय की घोषणा में किया गया हो और जिसके लिये विधायी का आदेश दिया गया हो, भुगतान हतु एसी रकम में से विषय के घोषणापत्र से ऐसा रकम के जमा कराव जान की तारीख के साथ चुकाई गई रकम शेष करदा जायेगी, और
- (ग) विषय-व्यय ।

यदि इस प्रकार जमा ३ दिनों की अवधि के भीतर हो जाय तो कलमन्दर विषय को रद्द करने का आदेश निम्नोक्त

परन्तु शर्त यह है कि कोई व्यक्ति धारा २५७ के अन्तर्गत विमय को रद्द करने हेतु आवेदन करता है तो यह इस धारा के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत करने का अधिकारी नहीं होगा।

एक शर्त यह भी है कि इस धारा के अन्तर्गत विमय को रद्द करने के साथ ही यदि भूमि धारा २६६ के अन्तर्गत सर्व भार मुक्त विमय की गद् होगी तो उसे भार पुन प्रभावशील हो जायेगा।

[धारा २४७] अनियमित इराजि की वनह से विक्रय को निर्मूल करने का आवेदन पत्र — विक्रय को किसी वास्तविक अनियमितता अथवा प्रकाशन भी सम्पादन की छुट्टि के आधार पर विक्रय की तारीख के परमात् ३० दिन की अवधि के भीतर किसी भी समय, रद्द किये जाने के सम्बन्ध में कोई आवेदन पत्र क्लर्क को दिया जा सकता है किन्तु कोई भी विक्रय तब तक ऐसे आगार पर रद्द नहीं किया जायेगा जब तक कि आवेदनपत्र क्लर्क के सम्मोप के लिए यह साबित न करे कि उसे ऐसी अनियमितता या गलती के कारण कोई मॉलिन हानि नहीं पहुँची है।

[धारा २४८] विक्रय को पुष्ट अथवा निर्मूल करने हेतु आना — यदि, विक्रय के परमात् ३० दिनों का समाप्ति पर धारा २४६ अथवा २४७ में उल्लिखित कोई आवेदनपत्र पेश करना हो अथवा यदि ऐसा आवेदनपत्र प्रस्तुत किया गया हो और स्वरित कर दिया गया हो तो क्लर्क विक्रय की पुष्टि हेतु एक आदेश प्रकाशित करेगा और यदि ऐसा आवेदनपत्र धारा २४७ के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया हो और स्वीकृत कर लिया गया हो तो क्लर्क विक्रय को रद्द करने के लिये आदेश देगा।

[धारा २४९] अनियमितता अथवा गलती पर आधारित दावों पर प्रतिबन्ध — यदि धारा २४७ के अन्तर्गत इस सम्बन्ध में दिये गये समय के अन्दर कोई आवेदनपत्र प्रस्तुत नहीं किया जाय तो विक्रय के प्रकारान तथा सम्पादन के सम्बन्ध में हुई गलती या अनियमितता के आधार पर किये जाने वाले सभी दावे प्रतिबन्धित होंगे। परन्तु इस धारा में उल्लिखित कोई भी नस्तु धोरे के आधार पर किसी को रद्द किये जाने के अथ के लिये दीनानी न्यायालय में दायर किये जाने वाले दावे पर प्रतिबन्ध नहीं लगायेगी।

टिप्पणी — यह धारा स्पष्ट करती है कि विक्रय से सम्बन्धित कार्यवाही की छुट्टि या अनियमितता का विषय में दिय जाने वाले आवेदनपत्र के प्रतिरिक्त विक्रय के सम्बन्ध में दोषाधी न्यायालय में धोरे के कारण की गई कार्यवाही सिद्ध करने पर रद्द कराई जा सकती है।

[धारा २५०] विक्रय के रद्द होने पर क्रय राशि की वापसी — धारा २४८ के अन्तर्गत जब कभी किसी भूमि अथवा अचल सम्पत्ति के विक्रय को रद्द कर दिया जाय तो उसीद्वारा व्याप्त सहित जो कि ६ प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से अधिक नहीं होगा, अथवा व्याप्त रहित वैसा कि क्लर्क उचित समझे, धनराशि के पुन प्राप्त का अधिकारी होगा।

- (१८) धारा १०१ के अधीन कृषिकार्यों के लिए भूमि के आउटन के नियमन हेतु,
- (१९) धारा १०६ के अंतर्गत सर्वेक्षण अभिलेख कार्य अथवा केवल अभिलेख कार्य प्रमों के संचालन में भूमि अभिलेखाधिकारियों द्वारा ग्रहण किये जाने वाले जाने के नियमन के लिए,
- (२०) धारा ११० एवं १३१ के अधीन मानचित्र तथा खसरे के निर्माण, प्रमाणीकरण एवं प्रबंध विधान के निश्चयन के लिए,
- (२१) उक्त धाराओं के अधीन मानचित्र या खसरे के स्वरूप एवं विषय वस्तु के और उनमें परिवर्तनों के अभिलेख के लिये मध्यांतर एवं प्रणाली के नियमन के लिए,
- (२२) धारा ११७ तथा १३२ में निर्दिष्ट अधिकार अभिलेख एवं वार्षिक रजिस्टरों के निर्माण, प्रमाणीकरण एवं प्रबंध के नियमन के लिए, जिसमें अधिकार अभिलेख के अक्षय स्वरूप ऐसे रजिस्टर उल्लिखित होंगे जिनका विवरण धारा ११७ में नहीं दिया गया हो और धारा १२१ में उल्लिखित विवरणों के अतिरिक्त ऐसे विवरणों के नियमन के लिए जिनका उल्लेख खानी में किया जायेगा,
- (२३) धारा १२३, १२४ और १२५ के अधीन नाच पड़ताल करने के समय भूमि अभिलेखाधिकारी द्वारा प्रयोज्य कार्य प्रणाली के नियमन के लिये,
- (२४) धारा ११५ के अधीन सरकारी भूमियों की सूचि के निर्माण की रीति के नियमन के लिए और ऐसी भूमि के बारे में की जाने वाली जाच पड़ताल के ढंग के निर्धारण के लिये,
- (२५) धारा ११८ के अधीन गुणाकार के निष्पण और अभिलेखन के ढंग के नियमन के लिए,
- (२६) गांव के याशिदा के रहने के लिए आरक्षित किये जाने योग्य क्षेत्र के निष्पण तथा निश्चयन के लिये,
- (२७) धारा १२० के अधीन गांवों की मुखियों के प्रपत्र, विषय-वस्तु एवं निर्माण की विधि के निर्धारण के लिए
- (२८) ऐसे अवसरों के निर्धारण के लिए जब कि सालाना रजिस्टर धारा १३० के अधीन तैयार किये जायेंगे जिस प्रणाली या तरीके से परिवर्तनों को उनमें दर्ज किया जायेगा और उस प्रकार के परिवर्तनों का इन्तज करने पर जो फीस चान की जायगी

टिप्पणी — [राजस्थान अधिनियम ११ धारा १९५६ के सेक्शन २० द्वारा जो राजस्थान मजदूर, विप्लव दिनांक १० १ १९५६ के अधिनियम ४-४ में प्रमाणित हुआ पदस्थित किया गया और सत्र के परिचालन तथा समझा जायेगा]

- (२६) अध्याय ७ व अधीन निर्माता मातृगित्र-नामरे और रजिस्ट्रारों के जनता द्वारा किये जाने वाले निरीक्षण या समय और सन्धिपरी गर्व, उमरी प्रविष्टियाँ की प्रतिलिपि तैयार करने का शुल्क व उनका जारी करने तथा प्रमाणित कराने की रीति के निधारण के लिये,
- (३०) धारा १७७ व अधीन बन्दोस्त के वायव्य व निष्पादन में बन्दोस्त अधिकारियों द्वारा प्रयोग्य वाय प्रणाली के नियमन के लिये,
- (३१) धारा ११० व अधीन मिट्टी की विभिन्न श्रेणियाँ में लगान निधारण के क्षेत्रों या वर्गों व विभाजन के नियमन के लिए,
- (३२) धारा १६२ व अधीन ग्राह्य सम्पत्ती लगानों की वसूली को रोकने के लिए आदेश जारी करने की प्रणाली के निधारण के लिए,
- (३३) धारा १७४ के तृतीय अनुच्छेद व अगत मामला में बन्दोस्त के अन्तरिम पुनराचन के नियमन हेतु,
- (३४) धारा १८० के अधीन विशेष नागरिक-र आरोपण के नियमन हेतु,
- (३५) धारा १६७ के अधीन विभाजन के प्रयोजनार्थ भूमियाँ के मूल्यांकन के उपनियम तथा सामान्य सिद्धान्तों के नियमन के लिये
- (३६) धारा २०३ के अधीन विभाजन के रच के निरूपण और उनकी किरता और उनके भुगतान के समय के नियमन के लिये।
- (३७) धारा २२३ के अधीन सरकार और किसी सम्पत्तिधारी के बीच किसी सम्पत्ति के विभाजन के नियमन के लिये,
- (३८) धारा २०६ के अधीन राज्य सरकार को देय लगान या लगान की किरता स्थान, समय तथा भुगतान की प्रणाली आदि के निधारण के लिये
- (३९) धारा २०६ के अधीन मागपत्र तथा उपस्थितिपत्र जारी करने किन अधिकारियों अथवा अधिकारियों के वर्गों द्वारा व जारी किये जायेंगे और दोषियों से उस सम्बन्ध में वसूल किये जाने वाले खर्चों के निश्चयन के नियम बनाने के लिये
- (४०) धारा २३४ के अधीन किसी सम्पत्ति अथवा उसके किसी निर्दिष्ट अंश या पट्टे को हस्तान्तरित करने अथवा धारा २३५ के अधीन बेचने की रीति के नियमन के लिये।
- (४१) ऐसे परिणामों के नियमन के लिये जो इस धारा के अधीन बन्दोस्त के असम्बद्ध किसी भी गैर अन्तर्गत कार्यवाही के सम्बन्ध में वसूल किये जा सकें हैं
- (४२) किसी भी गैर अन्तर्गत कार्यवाही के सम्बन्ध में जो बन्दोस्त से सम्बद्ध नहीं हो, किसी पदाधिकारी या इस अधिनियम के किसी प्राधान के अधीन शक्ति सम्पन्न अथवा राजस्व व्यक्ति द्वारा प्रयोग्य कार्य प्रणाली के नियमन के लिये

(४३) निर्धारित सभी अथ विषयों के नियमन हेतु अथवा जिनका निर्धारण किया जाना आवश्यक हो अथवा जिनके सम्बन्ध में इस अधिनियम की उपधारा (१) के अधीन बोर्ड द्वारा निर्मित नियमों के अतिरिक्त नियम बनाये गये हों या बनाया जाना आवश्यक हो और

(४४) सामान्यतः इस अधिनियम के प्रावधानों के प्रयोग के लिये ।

[धारा २६२] पटवारी इत्यादि जन-सेवक होमे — भारतीय दण्ड विधान (केन्द्रीय एक्ट संख्या ४५ सन् १८६०) की धारा २१ के प्रयाजनाथ, अध्याय ३ के अन्तर्गत नियुक्त प्रत्येक पटवारी, गिरदावर, कानूनगो अथवा भूमि अभिलेख निरीक्षक सदर कानूनगो, और ग्राम रक्षक और उपरोक्त व्यक्तियों में से किसी के कर्तव्यों को अल्पकाल के लिए सम्पादन करने के लिये नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति को जनसेवक माना जायेगा और ऐसे सभी व्यक्तियों द्वारा या उनमें से किसी एक द्वारा रखे जाने वाले सभी राजकीय अभिलेख एवं कागजात सार्वजनिक अभिलेख एवं राज्य की सम्पत्ति माने जायेंगे ।

टिप्पणी — यह धारा स्पष्ट करती है कि पटवारी इत्यादि राज्य कर्मचारी भारतीय दण्ड विधान के प्रावधानों के अनुसार जन सेवक कहलायेंगे और इन प्रकार जन सेवक के अपने समस्त कर्तव्य पूरे न करने पर उन्हें भारतीय दण्ड विधान के प्रावधानों के अनुसार ही दण्ड दिया जायेगा ।

इस उपरोक्त कर्मचारियों द्वारा रखा जाने वाला रेकर्ड तथा प्रपत्र सार्वजनिक तथा राजकीय सम्पत्ति माने जायेंगे ।

[धारा २६३] परित्राण एवं सण्डन — इस अधिनियम के लागू होने पर निम्नांकित इस अधिनियम के प्रावधानों में समविष्ट अथवा उनमें सगुन विषय तक खण्डित समझ जायेंगे अर्थात्—

(क) द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित विधान,

(ख) द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित विधान के अतिरिक्त इस अधिनियम के प्रावधानों में शामिल किसी विषय से सम्बद्ध किसी संधि पत्रावलीगत राज्य के कोई कानून, और

(ग) सण्ड (क) एवं (ख) में उल्लिखित विधानों का संपादन करने वाले कोई कानून,

(२) इस अधिनियम द्वारा किसी विधि या विधान के खण्डित किए जाने में इस अधिनियम के पारित किये जाने के तत्काल पूर्व अनुचित समझी जाने वाला कोई भी प्रयास उचित नहीं हो सकेगा ।

(३) इस अधिनियम के प्रारम्भ के समय राजस्थान के किसी भी सण्ड में प्रचलित कोई भी सामाजिक प्रथा, या रीति या कहीं कोई विधि के रूप में प्रभावशील रहो हो यदि वह इस अधिनियम के प्रावधानों में प्रतिबन्ध या अंगगत होगी या तभी अंगगत या प्रतिबन्धिता की सीमा तक प्रभावशील हो जायेगा ।

प्रथम अनुसूची

(धारा २३ देखिय)

न्यायिक मामला की सूची

- (१) धारा ८८ की उपधारा २ के अंतर्गत यन्त्र ।
- (२) तरागाह भूमि पर चरावाही पशुओं के हानि व सम्बन्ध व भण्ड ।
- (३) जंगलात की भूमि से बाढ़ देना व जंगलात की उपज पर प्रयोग करने वाले के हानि सम्बन्धी भण्ड मामला,
- (४) भूमि सीमा का निपटारा व भण्ड ।
- (५) रजिस्ट्रार आफ राइट्स व वार्षिक रजिस्ट्रार स इन्ड्रोज करने व भण्ड ।
- (६) किसान की श्रृंखला या भू-स्वामित्व रखने सम्बन्धी भण्ड ।
- (७) मवादल, उत्तराधिकार या अन्य विषयक नामांतर ।
- (८) रेंट या रिवेन्यू देन सम्बन्धी भण्ड ।
- (९) दस्तूर गराई या बाजिव-उल-अज सम्बन्धी भण्ड ।
- (१०) रिवेन्यू या रेंट से मुक्त रखी हुई भूमि के मूल्य निर्धारण एवं जाच करने सम्बन्धी ।
- (११) जायदाद के टुकड़ करने व जोड़ने ।
- (१२) इस कानून के अंतर्गत जुर्माना करने, पेनेलटी लगाने, जम्मा करने सम्बन्धी ।
- (१३) मुआवजा को नियत करने ।
- (१४) इस कानून व अन्तर्गत विधियों व नीलाम करने ।
- (१५) ऐसे अन्य मामला जो राज्य सरकार द्वारा नियत किये गये हों ।

द्वितीय अनुसूची

(धारा २६३ देखिय)

(सूची उन अधिनियमों की जो रद्द कर दिये गये)

- (१) राजस्थान टरीटोरियल डिवीजन अधिनियम १९४६ ।
- (२) राजस्थान बोर्ड आफ रिवेन्यू अधिनियम १९४६ ।
- (३) राजस्थान रिवेन्यू कांटस (डिसिगनेशन) अधिनियम १९४६ ।
- (४) राजस्थान रिवेन्यू कोटस (प्रोसीजर एण्ड ज्यूरिसडिक्शन) एक्ट १९५१ ।

- (५) अलवर स्टेट रिवेन्यू कोड ।
- (६) भरतपुर रिवेन्यू कोड ।
- (७) भरतपुर लेण्ड रिवेन्यू मेनुअल ।
- (८) बीकानेर लेण्ड रिवेन्यू एक्ट १९४५ ।
- (९) बून्नी स्टेट लेण्ड रिवेन्यू एक्ट १९४० ।
- (१०) वामनवाडा कलाइदे माल ।
- (११) डूंगरपुर रिवेन्यू रूल्स ।
- (१२) जयपुर स्टेट माटस लेण्ड टेन्पोर एक्ट १९४५ ।
- (१३) जयपुर लेण्ड रिवेन्यू एक्ट १९४७ ।
- (१४) जयपुर जिलेन सविमेन एक्ट १९४८ ।
- (१५) फरीली स्टेट लेण्ड रिवेन्यू कोड ।
- (१६) कोटा रिवेन्यू सरसुलर्स ।
- (१७) मारवार लेण्ड रिवेन्यू एक्ट १९४६ ।
- (१८) मारवाड जागीर सेटलमेन्ट रज्यूलेशन्स १९४६ ।
- (१९) कानून माल मेवाड रिवेन्यू कोर्टस् एक्ट १९४६ ।
- (२०) मेवाड रिवेन्यू कोड एक्ट १९४७ ।
- (२१) शाहपुरा बयाइद इस्लाम रारिन १९२३ ।
- (२२) सिरोही लेण्ड रिवेन्यू एक्ट १९४७ ।

[राजस्थान राजस्व विभागां दिनांक ११-१-५८ व सख ४-५ में प्रकाशित]

राजस्थान राजस्व अधिनियम (विस्तार) अधिनियम, १९५७

(अधिनियम संख्या २, सन १९५८)

[राष्ट्रपति की स्वीकृति दिनांक ७ जनवरी, १९५८ को प्राप्त हुई]

प्रारंभ पुनर्गठन राजस्थान राज्य की कतिपय सार्वजनिक विधियों को आरू अजमेर तथा मुनेल १५ म विस्तारित करने का प्रावधान करने के लिए अधिनियम ।

यूनि नये राजस्थान राज्य नैसा कि स्टेट्स रीथा नाइनेरान एक्ट, १९४६ (मेन्ट्रल एक्ट सं० २७ सन् १९४६) की धारा १० द्वारा निर्मित हुआ की राजस्व विधियों में एक रूपता लाने के लिये यह इष्टकर है कि प्रारंभ-पुनर्गठन राजस्थान राज्य में प्रभावशील राजस्थान टेनेन्सी एक्ट १९४५ (राजस्थान एक्ट सं० ३, सन १९४५) और राजस्थान लेण्ड रिवेन्यू एक्ट, १९४६ (राजस्थान एक्ट सं० १५ सन् १९४६) से नये राजस्थान राज्य के आरू अजमेर तथा मुनेल दोनों म विस्तारित करने के लिये प्रावधान किया जाये और तत्प्रयोजनार्थ तथा अन्य प्रयोजना के लिये, जो इसमें नीचे अर्जित हैं, उनमें व्यवस्त संशोधन किये जायें

अन राजस्थान राज्य में विधान मण्डल द्वारा भारत सरकार के आदेशों के अन्तर्गत निम्न रूपेण अधिनियमित किया जाता है —

१ सक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ — (१) यह अधिनियम राजस्थान राजस्व विधिया (विस्तार अधिनियम १९५७) कहलायगा।

(२) यह ऐसी तारीख से प्रभाव में आयेगा जो राज्य सरकार राजपत्र में विज्ञापन द्वारा नियत करे।

२ परिभाषा — इस अधिनियम में जहाँ तक विषय अथवा प्रसंग में अन्यथा अपेक्षित न हो—

[१] 'नियत दिन' में अभिप्राय धारा १ की उप-धारा (२) के अंगीन जारी की गई विज्ञापन द्वारा इस अधिनियम के प्रारम्भ के लिये नियत किये गये दिन से है।

[२] राजस्थान राजस्व विधियों से अभिप्राय प्राप्त पुनर्गठन राजस्थान राज्य में प्रभावी राजस्थान एक्ट १९५४ (राजस्थान एक्ट ३, सन १९५५) तथा राजस्थान लेण्ड रवेन्यू एक्ट, १९५६ (राजस्थान एक्ट २०, सन १९५६) से है।

३ राजस्थान राजस्व विधियों का संशोधन — नियत दिन को तथा से राजस्थान राजस्व विधिया ऐसी रीति से तथा ऐसी सीमा तक जो धारा ४ और अनुसूची १ में उल्लिखित हैं संशोधित की जायेंगी।

४ राजस्थान राजस्व विधियों में सामान्य रूपभेद — राजस्थान राजस्व विधिया में सर्वत्र जहाँ तक विषय अथवा सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो और इस अधिनियम में ऐसा अन्यथा उल्लिखित हो उसे छोड़ कर —

[१] अभिव्यक्ति *Rajasthan Gazette* जहाँ कहा भी प्रयुक्त हुआ हो के स्थान पर अभिव्यक्ति 'Official Gazette' प्रतिस्थापित की जायेगी।

[२] शब्द '*Rajasthan*' अभिव्यक्ति '*Rajasthan Gazette*' में अथवा अभिव्यक्ति '*State of Rajasthan*' में अथवा राजस्थान राजस्व विधियों के सक्षिप्त शीर्षकों अथवा अन्य किसी राजस्थान अधिनियमित में हुई प्रयुक्ति को छोड़कर अन्यत्र जहाँ कहीं प्रयुक्त हुआ हो उसके स्थान पर शब्द '*the State*' प्रतिस्थापित किये जायेंगे और

[३] राजस्थान राजस्व विधियों में से किसी विधि के प्रारम्भ या प्रभावी होने के निर्देश से ऐसी विधि के आगु अन्तर्गत तथा सुनेल भेज में प्रारम्भ के प्रसंग में अथ इस अधिनियम के प्रारम्भ का निर्देश, लगाया जायेगा।

५ राजस्थान राजस्व विधियों तथा उनके अन्तर्गत निमित्त नियमों अति

रा विस्तार — नियत दिन को तथा से राजस्थान राजस्व विधिया धारा ३ तथा ४ द्वारा संशोधित रूप में और सक्षम प्राधिकारी द्वारा अन्तर्गत बनाये गये या जारी किये गये नियम, अनियम आदेश तथा विज्ञापित आगु अन्तर्गत तथा सुनेल भेजों सहित संपूर्ण नये राजस्थान राज्य में विस्तारित तथा लागू होगी।

अधिनियमितिया तथा विधिया के प्रायधाना द्वारा अथवा एगदुदारा अधिवमित नियमा विनियमा आमाया तथा विशाजिया के प्रायधाना द्वारा प्रदत्त निमा अधिनार अथवा आरोपित निमी पक्ष न्य के अनुसरण म अजिा निमी हेमिया (a' title) या सम्पत्ति पर अथवा लिये गये निसी दायित्व पर एमे निरसन अथवा अधिवमण का, इस याा के हात हुए भी नि एमी हेमियन, सम्पत्ति या दायित्व राजस्थान राजस्थ विधिया के प्रायधाना के प्रतिदूल या असगत के अथवा उनक अतगत अन्वित नही किया जा मजता या लिया गीं चा सजता या फोट प्रमाय नही पदगा।

प्रथम अनुसूची

नोट —प्रथम अनुसूची के सगावन मून अधिनियम के लागू कर निचे के मत दग। (५।
अनुसूचा प्रथम म नही प्रकाशित की जा रही है।

द्वितीय अनुसूची

(देखिये धारा (६))

निरस्त मी गइ अधिनियमितियों की सूची

- | | | |
|----|--|---|
| १ | गान्धे रवेयू जुरिस्टिकशन एक्ट, १८७६ | जहा तक व आनू क्षत्र पर लागू होते हैं। |
| २ | गान्धे लैंड रवेयू कोड, १८७६ | |
| ३ | गान्धे रेवेन्यू ट्रिब्यूनल एक्ट, १९३६ | |
| ४ | गान्धे टिनेन्सी एण्ड एग्रीकल्चरल लैंड्स एक्ट, १९४८ | |
| ५ | अजमेर तालुकादास रिलीफ रेगुलेशन, १८७७ | जहा तक वे अजमेर क्षेत्र पर लागू होने हैं। |
| ६ | अजमेर लैंड एण्ड रेवेन्यू रेगुलेशन १८७७ | |
| ७ | पचाय लैंड रेवेन्यू एक्ट, १८८७ | |
| ८ | अजमेर एग्रीकल्चरल आफ लैंड रेगुलेशन १९१४ | |
| ९ | अजमेर मेरवाडा रिडम्पशन आफ मार्गेंजेज रेगुलेशन १९२८ | |
| १० | देहली एण्ड अजमेर लैंड डेवलपमेंट एक्ट, १९४८ | |
| ११ | अजमेर टिनेन्सी एण्ड लैंड रेकाइस् एक्ट १९४० | जहा तक वे सुनेल क्षेत्र पर लागू होते हैं। |
| १२ | मध्यभारत जागीर लैंड रेकाइस् मेनेजमेंट एक्ट, १९४६ | |
| १३ | मध्यभारत लैंड रेवेन्यू एण्ड टिनेन्सी एक्ट १९४० | |

